HVS/Lib/7

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 फरवरी, 2004

खण्ड–1, अंक– 7

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 16 फरवरी, 2004

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(7)22
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	(7)23
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(7)28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(7)28
वाक आउट्स	(7)30
विधान सभा समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना	(7)35
वर्ष 2004–05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)36
वाक आउट	(7)37
वर्ष 2004–05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)50
वाक आउट	(7)50
वर्ष 2004-05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)52
वर्ष 2004–05 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(7)52
मूल्य :	(7)77

96

HWS/Lib/7

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 16 फरवरी, 2004

विधान सभा की बैठक हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेब्ल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या-1747

(इस समय माननीय सदस्य श्री राम भगत सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न संख्या-1688

(इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Amount allocated under Indra Awaas Yojana

*@1722. **Sh. Ram Phal Kundu**
Dr. Malik Chand Gambhir } : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the detail of amount allocated under Indra Awaas Yojana during the year 2002-2003 and 2003-2004 togetherwith the amount spend for the construction of houses therefrom separately ; and

(b) the district-wise number of houses constructed under the scheme referred to in part 'a' above during the said period ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अधीन क्रमशः 1563.92 लाख रुपये तथा 1771.10 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इसके विरुद्ध

@ Put by Shri Ram Phal Kundu.

[श्री राम पाल माजरा]

वर्ष 2002-2003 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए 1927.659 लाख रुपये तथा वर्ष 2003-2004 (दिसम्बर, 2003 तक) के दौरान 1213.896 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

(ख) एक विवरणी सदन के पटल पर रखी गई है।

विवरणी

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष 2002-2003 के दौरान निर्मित किये गये मकानों की संख्या	वर्ष 2003-2004 (दिसम्बर, 2003 तक) के दौरान निर्मित किये गये मकानों की संख्या
1.	अम्बाला	892	441
2.	भिवानी	735	301
3.	फरीदाबाद	719	569
4.	फतेहाबाद	266	225
5.	गुड़गाँव	717	253
6.	हिसार	602	301
7.	झज्जर	202	176
8.	जीन्द	330	280
9.	कैथल	330	194
10.	करनाल	627	268
11.	कुरुक्षेत्र	522	130
12.	महेन्द्रगढ़	270	121
13.	पंचकूला	109	40
14.	पानीपत	445	73
15.	रिवाड़ी	401	187
16.	रोहतक	384	323
17.	सिरसा	563	395
18.	सोनीपत	605	183
19.	यमुनानगर	1121	433
	कुल :	9840	4893

चौ० राम फल कुण्डू : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इनको बनाने के लिए नार्म्ज क्या हैं ? स्पीकर सर, जिस प्रकार से 5100 रुपए कन्यादान के रूप

में हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले चाहे वे किसी भी वर्ग से सम्बन्धित हों, को देने का फैसला किया है। क्या उसी तरह से गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले हर वर्ग को ये मकान देने का सरकार का कोई विचार है ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम केन्द्र सरकार की 75 प्रतिशत की और राज्य सरकार की 25 प्रतिशत की भागीदारी से चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों के लिए रहने के मकान बनाने की योजना है। स्पीकर सर, इसमें 60 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और 40 प्रतिशत दूसरी जाति के गरीब लोगों के लिए मकान बनाने का पहले से ही पैरामीटर बना हुआ है। हमारे पास जितनी राशि आती है उसका 60 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के मकानों पर और 40 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले दूसरे वर्गों के लिए मकान देने के लिए है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 31 मार्च तक यह साल खत्म हो जाएगा और जो अब तक अम्बाला में 892 हाउसिज कंस्ट्रक्ट किए जाने थे लेकिन इसमें 442 हाउसिज ही कन्स्ट्रक्ट किए गए हैं। लगभग आधे का फर्क है और अब यह सरकार मार्च खत्म होने पर हड़बड़ाहट में पैसा देकर इन मकानों को बनवाने का काम करेगी। ये जो मकान इन्कम्पलीट रह गए हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि सभी कार्य प्रोग्रेस में हैं। 2003-04 के अंत का लेखा जोखा अप्रैल में आएगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बताना चाहूँगा कि 1991 से 1996 तक 16130 मकान बनाए गए थे, 1996 से 1999 तक 21494 मकान बनाए गए थे और 1999 से लेकर अप टू दिसम्बर, 2003 तक 37361 रिकॉर्ड तोड़ मकान बने हैं। (विघ्न) इक्ट्ठा मिलाने के बाद भी ये मकान इनके समय के मुकाबले ज्यादा बनते हैं। इन्होंने हड़बड़ाहट वाली बात कही है लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि हड़बड़ाहट में कुछ नहीं होगा। जो लाभार्थी हैं उनकी मर्जी है, कई बार तो वह सामान ले लेते हैं और कई बार वे लिखकर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि उनको सामान नहीं चाहिए। कई बार वे डिपार्टमैंट से मैटीरियल लेकर भी बना लेते हैं क्योंकि अगर वे डिपार्टमैंट के थ्रू मैटीरियल लेते हैं तो उनको सीमेंट और ईंटों के दामों में फायदा होता है लेकिन अगर वे चाहें तो मैटीरियल के स्थान पर कैश भी ले सकते हैं इस तरह से वे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या-1680

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री शशि परमार सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Improvement in burnout rate of transformers

*1765. **Sh. Ramesh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is fact that a large number of distribution transformers are burnt in the State; if so the improvement, if any, made in burnout rate of such transformers alongwith the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हाँ, श्रीमान् ! यद्यपि विभिन्न उपयुक्त कदमों के परिणामस्वरूप राज्य में वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षतिग्रस्त दर वर्ष 1996-1997 में 31.21% से घटकर वर्ष 2003-04 (दिसम्बर तक) में 12.18% हो गई है। पिछले आठ वर्षों के दौरान वितरण ट्रान्सफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :--

वर्ष	स्थापित किए गए ट्रान्सफार्मरों की संख्या	क्षतिग्रस्त हुए ट्रान्सफार्मरों की संख्या	क्षति का प्रतिशत
1996-97	95221	29721	31.21
1997-98	98500	33266	33.77
1998-99	103507	27635	26.70
1999-2000	107011	24902	23.27
2000-01	111476	21133	18.96
2001-02	117301	18457	15.73
2002-03	125368	18229	11.90
2003-04 (दिसम्बर तक)	131647	16034	12.18

श्री रमेश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो यह ट्रांसफार्मर्ज का डेमेज रेट दिसम्बर, 2003 तक 12.18 प्रतिशत घटकर आया है तो क्या और भी कोशिश की जा रही है कि यह रेट इससे भी कम आए ?

श्री राम पाल माजरा : हाँ, स्पीकर साहब, जब से माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक 26342 नये ट्रांसफार्मर्ज और इसमें जोड़े गये हैं। इसकी वजह से ही इनके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा भी और कदम उठाए जा रहे हैं, नये ट्रांसफार्मरज लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से वितरण लाइनों में कंडक्टर लगाए जा रहे हैं, फीडरों का द्विविभाजन और त्रिविभाजन किया जा रहा है और एल.टी. प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है। एल.टी. प्रणाली में केबल क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से वितरण ट्रांसफार्मर्ज का नियुक्ति अनुरक्षण किया जा रहा है और वितरण ट्रांसफार्मर्ज का तीन फेज का भार भी संतुलित किया जा रहा है तथा चैकिंग भी की जा रही है ताकि कोई कम्पेसटर न लगा सके। इस तरह से ये जो सारे पग उठाए जा रहे हैं। उनकी वजह से ही ट्रांसफार्मर्ज का बरन्ट रेट 12.18 प्रतिशत रह गया है जो कि हमारी उल्लेखनीय उपलब्धि रही है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, पी.यू.सी. ने एक बार कई जगहों पर ट्रांसफार्मर्ज का और वर्कशाप वगैरह का इंसपैक्शन किया था। जब पी.यू.सी. ने इनका कार्ड मेनटेन करने के लिए कहा था तो बिजली महकमे ने इसके लिए हाँ भरी थी तो मैं आपकी मार्फत इनसे जानना चाहूँगा कि क्या अब इनकी मेंटीनेंस के लिए वे कार्ड मेनटेन किए जा रहे है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक पी.यू.सी. की रिकमंडेशन का प्रश्न है उसके लिए अभी तक कोई कार्ड मेनटेन करने की बात नहीं आई। किसी भी प्रकार से बरन्ट ट्रांसफार्मर को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए इसके लिए हम और योजना भी बना रहे हैं ताकि किसी प्रकार से प्राइवेट आदमी को देकर, बोली आमंत्रित करके जल्दी से ठीक करके दिया जा सके।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से रमेश राणा जी ने ट्रांसफार्मर्ज के बारे में प्रश्न पूछा है। क्या विभाग ने प्रदेश में कोई ऐसा सर्वे कराया है कि जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जैसे 25 के.वी.ए. के हैं, 63 के.वी.ए. और 100 के.वी.ए. के हैं क्या ऐसा कोई सर्वे कराया है कि उनको जलने से पहले उनमें इम्प्रूवमैंट करके उनकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, इतनी ज्यादा संख्या में ट्रांसफार्मरज लगाए गए हैं और यह लोगों की शिकायत पर लगाए गए हैं जब लोग यह कहते हैं कि हमारे बल्ब नहीं जलते हैं, हमारी मशीनें नहीं चलती हैं, हमारी इण्डस्ट्री नहीं चलती। कंज्यूमर की तरफ से कोई शिकायत की जाती है तो चैकिंग की जाती है और जहां लगता है कि वास्तव में ऑगमैंट कराने की जरूरत है वहीं पर किया जाए और इसमें लोगों की शिकायत के ऊपर यह अंदाजा लगा लिया जाता है। वह ट्रांसफार्मर जो आलरेडी कमीशंड हैं वह ओवरलोडिड हैं और बल्ब तक नहीं जल रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं चल रही हैं, ट्यूबवैल नहीं चल रहे हैं, मशीनरी नहीं चल रही है तो इस बात को लेकर यह लोगों की शिकायत पर किया जाता है।

चौ० रामफल कुण्डू : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूँगा कि जिस तरह ट्रांसफार्मर जल जाता है लोग शिकायत करने जाते हैं जैसे उस ट्रांसफार्मर पर 8-10 कनैक्शन हैं उनमें से यदि किसी एक का बिल बकाया रह जाता है तो महकमे वाले यह कह देते हैं कि पहले उसका बिल भरवाओ।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, रिकवरी तो बहुत ही जरूरी है एक दो लोगों के बिल जमा न हुए हों तो उनको कहा जाना जरूरी है। हां, यदि किसी एक दो का बिल बकाया रह जाता है तो ट्रांसफार्मर बदलने पर रोक नहीं लगायी जाती। आपका ट्रांसफार्मर एक व्यक्ति के बिल अदा न करने से नहीं बदला जाएगा, ऐसी कोई योजना नहीं है। दस कंज्यूमर हैं उनमें से आठ बिल जमा कर देते हैं दो बिल नहीं जमा करते हैं तो ट्रांसफार्मर बदला न जाए, ऐसा नहीं है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या किसी की रिसपौंसिबिलिटी फिक्स की जाती है जब ट्रांसफार्मर जलता है कि किस कारण से जला, ईवेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, नॉन मेंटीनेंस की वजह से जला या जी.ओ.सी. स्विच के फाल्ट से जला, क्या कहीं किसी की जिम्मेदारी फिक्स की जाती है। मैंने कार्ड का जिक्र किया था और पहले भी प्वाइंट आउट किया था यदि मुझे याद है तो इस हाउस के अंदर आश्वासन दिया गया था कि यह कार्ड प्रणाली चालू की जाएगी ताकि किसी की जिम्मेदारी निश्चित की जाए कि उस व्यक्ति की वजह से यह ट्रांसफार्मर जला है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है लोग जब उनकी लाईट चली जाती है तो अपने आप मोटा फ्यूज लगा लेते हैं क्योंकि उनको टैक्नीकल नॉलेज तो होती नहीं जिसकी वजह

[श्री राम पाल माजरा]

से ओवरलोड होने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाता है। जैसे किसी गांव में दस ट्रांसफार्मरज हैं और इनमें से दो ट्रांसफार्मरज जल गये हैं तो उन दो ट्रांसफार्मरज वाले लोग दूसरे ट्रांसफार्मरज पर कुण्डियां डाल लेते हैं जिसकी वजह से वे दूसरे ट्रांसफार्मरज भी जल जाते हैं। अब देहात में पता नहीं किसकी वजह से ट्रांसफार्मर जला है इसकी रिस्पौंसिब्लिटी तो फिक्स की नहीं जा सकती। सरकार की कोशिश यह रहती है कि जहां पर ट्रांसफार्मर जल गये हैं वहां 48 घण्टे के अन्दर-अन्दर ट्रांसफार्मर चेंज होने चाहिएं। ट्रांसफार्मर को जल्दी बदलने की नीति सरकार की है।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि मंत्री जी ने अपने जवाब में अभी बताया है कि गांव के देहात में जो लोग कुण्डियां लगा लेते हैं और कुण्डी लगाने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाता है तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कितनी जनसंख्या पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जब लोग अपना कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी जमा करते हैं तो उसमें अपना लोड दर्शाते हैं उसके हिसाब से ही ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जो कनेक्शन बढ़ जाते हैं उनको अनएथोराईज्ड कनेक्शन कहा जाता है।

चौ० नफे सिंह राठी : स्पीकर सर, मैं माननीय सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जैसा कि कुण्डु साहब ने अभी बिजली के बिल भरने के लिए सवाल उठाया। मैं माजरा साहब से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने बिजली बिल भरने के लिए जो बिल काउंटर खोले हैं क्या उसके बारे में कोई पहले सर्वे कराया गया है ? जैसे बहादुरगढ़ में 35 हजार कन्जूमर्स हैं और सिर्फ दो ही बिल काउंटर खोले गये हैं अगर वहां पर रोजाना आठ घण्टे भी काम किया जाये तो 30 दिन में 14,400 बिल ही भरे जायेंगे। इसलिए लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को घण्टों लाइन में खड़े होना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि पूरे हरियाणा में एक सर्वे करवा कर बिल काउंटर खोलने की स्कीम पर सरकार विचार करे।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, वैसे तो यह प्रश्न ट्रांसफार्मर से संबंधित था बिलों की रिकवरी के बारे में नहीं है। फिर भी मैं राठी साहब से कहना चाहूँगा कि वे पहले लोगों से रिकवरी करवायें, काउंटर तो और खोल दिए जायेंगे। हमने सब डिवीजन लेवल पर अधिकारियों को निर्देश जारी कर रखे हैं और हमारे अधिकारी उन गांवों में बिल लेने जाते भी हैं जिन गांवों की तरफ से यह मांग आये कि हमारे बिल तो हमारे गांव में ही लिए जायें इस बारे में एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है और ईवन डोर पर जाकर बिलों की रिकवरी की जाती है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर डैमेज का मामला है ये ओवरलोड की वजह से प्लेट्स हीटअप होकर जल जाती हैं। बहुत से ट्रांसफार्मर ऑयल की कमी के कारण भी जल जाते हैं। इस बारे में मैं सी.पी.एस. महोदय से पूछना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मरों की ऑयल चैकिंग के लिए कोई कमेटी गठित की गई है जो समय-समय पर ट्रांसफार्मरों की चैकिंग करें और ऑयल की कमी हो तो वह समय रहते पूरी की जाये ताकि कम मात्रा में ट्रांसफार्मर जलें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि जब ट्रांसफार्मर लगाये जाते हैं तब उनकी प्लेटें, फ्यूज, ऑयल आदि पूरी तरह से चैक करके लगाये जाते हैं। उसके

बाद भी बाकायदा ट्रांसफार्मरों की चैकिंग समय-समय पर होती रहती है। जब लोग शिकायत करते हैं तो इनिशियल स्टेज पर कोशिश यही रहती है कि वहीं पर ट्रांसफार्मर ठीक कर दिए जायें। यदि वहां ठीक नहीं होते हैं तो ट्रांसफार्मर उतारकर दूसरा ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर दिया जाता है और जो ट्रांसफार्मर खराब होते हैं उन्हें ठीक करवाने के लिए वर्कशाप में भेज दिया जाता है।

Adoption of Villages for Agricultural Technology

***1659. Sh. Puran Singh Dabra :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to adopt the villages of the State to impart training and to give know-how of the latest Agricultural Technology to the farmers ?

कृषि मंत्री (स. जसविन्द्र सिंह संधू) : नहीं, श्रीमान् जी ! तथापि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि ज्ञान केन्द्रों / कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु गांवों को अपनाया जाता है।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कार्पोरेशंज हैं और दूसरी बड़ी-बड़ी जो कम्पनीज हैं वे खेल टीमों को ऐडोप्ट करती हैं, कई कम्पनी सार्वजनिक तौर पर चौराहे या फव्वारे ऐडोप्ट करती हैं। क्या इसी तरह किसी कंपनी या कार्पोरेशन की तरफ से किसी गांव को ऐडोप्ट करने का कोई प्रपोजल सरकार के पास आया है ताकि लेटैस्ट टैक्नोलोजी की खेती के बारे में लोगों को जानकारी हो। सरकार भी चाहती है कि क्रौप पैटर्न में चेंज हो और किसान अच्छी फसल ले सकें। क्या सरकार के पास किसी गांव को ऐडोप्ट करने का कोई प्रस्ताव किसी कंपनी की तरफ से आया है यदि आया है तो क्या सरकार उसे कंसीडर कर रही है।

स० जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कार्पोरेशंज और अन्य बड़ी-बड़ी कंपनीज टीमें ऐडोप्ट कर रही हैं। मेरे माननीय साथी डाबड़ा साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हम इस पर विचार करेंगे कि विभिन्न कार्पोरेशंज की तरफ से इसके लिए गांव ऐडोप्ट किए जायें।

Number of Trees Planted in Pataudi Constituency

***1671. Sh. Rambir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of trees planted in the Pataudi Constituency during the year 2000-01, 2001-02 and 2002-03 together with the amount incurred thereon; and

(b) the present position of the above said trees ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(अ) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान पटौदी हल्के में 2,55,770 वृक्ष लगाये

[श्री राम पाल माजरा]

गये और उन पर 22.67 लाख रुपये खर्च किये गये। विवरण निम्न प्रकार से है :--

वर्ष	लगाये गये पौधों की संख्या	किया गया खर्च (लाखों में)
2000-01	34000	4.06
2001-02	65570	7.41
2002-03	156200	11.20
योग	**255770**	**22.67**

(ब) इन वृक्षों की औसत जीवित प्रतिशतता 80 से 90 प्रतिशत है और पौधारोपण स्थिति बहुत अच्छी है।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय से कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं मुझे लगता है कि वे सही नहीं हैं क्योंकि इन्होंने जीवित प्रतिशतता 80 से 90 प्रतिशत बताई है। मैं सी.पी.एस. महोदय से पूछना चाहूँगा कि गांवों में सरकार की तरफ से जो वृक्ष लगाये गये हैं उनकी देखरेख के लिए संबंधित गांवों की पंचायतों को कोई अधिकार दे रखें हैं ताकि वृक्षों की सुरक्षा हो सके। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा एक दफा मैंने अखबार में एक चुटकला पढ़ा था कि तीन आदमियों की पेड़ लगाने की ड्यूटी लगाई गई। एक आदमी की ड्यूटी गड्ढा खोदने की थी दूसरे आदमी की ड्यूटी पेड़ लगाने की थी और तीसरे आदमी की ड्यूटी मिट्टी से गड्ढा भरने की थी। एक दिन गड्ढा खोदने वाला गड्ढा खोद रहा था और मिट्टी डालने वाला मिट्टी डाल रहा था किसी ने उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रहें हो। उन्होंने जवाब दिया कि पेड़ लगाने वाला छुट्टी पर है। कहीं ऐसा ही तो अब नहीं हो रहा है। यह पर्यावरण से संबंधित मामला है। इन आंकड़ों की जांच की जाये कि पेड़ सही में लगाये गये हैं या नहीं लगाये गये ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने इन पौधों के सरवाईवल रेट पर विशेषतौर पर आक्षेप किया है। मैं सदस्य महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि इन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद अपनी निगरानी रखते हैं। इन पौधों के सरवाईवल के लिए पहले तो महकमे की तरफ से चैकिंग होती है। इसके अलावा सरकार द्वारा इसके लिए एक कमेटी कान्स्टीच्यूट की गई जिसमें प्रोमिनेन्ट आदमी शामिल किए गए, जिनमें अखबार के ऐडीटर, साईंटिस्ट और विभाग के एक्सपर्ट लगाये गए। इस कमेटी ने इन पौधों के बारे में जो अपनी रिपोर्ट दी है वह ही मैंने आपको बताई है। डिपार्टमैंट वाली रिपोर्ट तो हो सकता हो कि कुछ मिथ्या भी हो लेकिन इसकी निगरानी के लिए एक निष्पक्ष कमेटी कान्स्टीच्यूट की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट में माना है कि जो प्रतिशत रेट दिया है वह सही है। मैं कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट जिलावाईज आई हैं वह भी बता देना उचित समझता हूँ। इस कमेटी में एक श्री प्रेम कुमार, प्रैजीडेन्ट, ऐडीटर रिटायर्ड इन्डियन एक्सप्रैस थे, दूसरे एक आर.एस. शर्मा भी रिटायर्ड एडीटर, दैनिक ट्रिब्यून और तीसरे सदस्य श्री आर.एन. कौल एक्सपर्ट फोरेस्टरी को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया था। इस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि पंचकूला में सरवाईवल रेट 90 से 95 प्रतिशत, यमुनानगर में 90 से 95 प्रतिशत, कैथल में 95 से 98 प्रतिशत, रिवाड़ी में 90 प्रतिशत, महेन्द्रगढ़ में 95 प्रतिशत, झज्जर में 90 से 95 प्रतिशत, हिसार में 95 प्रतिशत, सिरसा में बैरी गुड और भिवानी में भी बैरी गुड़ सरवाईवल की रिपोर्ट आयी है। स्पीकर साहब, यह रिपोर्ट निष्पक्ष है जिसमें सरवाईवल रेट बहुत

अच्छा बताया गया है।

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सी.पी.एस. महोदय ने जो डेटा इन पौधों की सरवाईवल का सदन की टेबल पर रखा है और जितने प्लांट हरियाणा बनने के बाद लगे हैं अगर इनका सरवाईवल रेट इतना अच्छा होता तो आज के दिन सारे हरियाणा में ग्रीनरी नजर आती। अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने डेटा दिया इस बारे में मेरा सुझेशन है कि इसकी सही जांच पड़ताल के लिए एक हाउस की कमेटी बनायी जाये ताकि वह कमेटी पता लगा सके कि जो डेटा दिया गया है उसकी करैक्टनैस क्या है। यदि इस डेटा पर सुओ-मोटो विश्वास करें तो अलग बात है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच पड़ताल के लिए एक हाउस की कमेटी बनायी जाये जो इस सरवाईवल रिपोर्ट के बारे में पता लगा सके कि सही फैक्ट्स क्या हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मानित सदस्य को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब विधान सभा में किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो वह सही दिया जाता है और अगर किसी सदस्य को ऐसा महसूस हो कि गलत जवाब है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, ऐसे मौकों पर सुझाव नहीं दिये जा सकते।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो रिपोर्ट हाउस में दी है इनकी वह रिपोर्ट अच्छी है। मैं इनकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो नये पौधे लगाने से पहले के पौधे लगाये हुए हैं उनमें से बहुत भारी मात्रा में पौधे सूख भी गए हैं। उन सूखे हुए पौधों को महकमे के लोगों द्वारा काट लिया जाता है। मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने यह आदेश दिए थे कि इन काटे जाने वाले पौधों में से आधा हिस्सा किसान को दिया जायेगा। किसी किसान के खेत के 1 से लेकर 5 तक पौधे सूख जाते हैं और फोरेस्ट विभाग वाले काट कर उन पौधों को अपने स्टोर में ले जाते हैं लेकिन उनमें से जो किसान का हिस्सा होना चाहिए, वह उनको नहीं देते। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी बात इनके नोटिस में है, यदि है तो क्या किसान को उसका आधा हिस्सा उन पौधों का मिलेगा ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात अगर किसी के नोटिस में आती है तो वह शिकायत करे और यदि कोई शिकायत आए तो उसकी इन्क्वायरी की जाती है। वैसे जो पौधे किसान को दिए जाते हैं वे लाईन बांट कर दिए जाते हैं और जो लाईन किसान के हिस्से में आएगी अगर उसमें कोई दरख्त सूखा है तो वह किसान का है। अगर कोई व्यक्ति उस दरख्त को उठा कर ले जाए तो भी उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि स्टेट में पेड़ों के लिए कितना बजट रखा गया है, कितना खर्च हो गया है और टोटल कितने पेड़ लगाने की सरकार की योजना थी और कितने पेड़ स्टेट में लगे हैं ? इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने कहा है कि 95% पौधे कामयाब हो गए हैं और कई जगह पर तो 100% कामयाब हो गए हैं और वैरी गुड कह दिया। अध्यक्ष महोदय, सारे देश की जो एवरेज है वह 80-82% से ऊपर नहीं है। मैंने भी यह महकमा सैंटर में चार साल तक सम्भाला है और स्टेट में भी 5-6 साल यह महकमा मेरे पास रहा है इसलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार यह बताने की कृपा करे कि टोटल कितने पेड़ लगाने थे और कितने पेड़ लगे ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस के सम्मानित सदस्य चौधरी भजन लाल जी स्टेट के मुख्य मंत्री रहे हैं। केन्द्र में भी यह मन्त्रालय देखते रहे हैं और यह महकमा भी इनके पास रहा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक टारगेट मुकर्रर करके रखा है कि इतने पौधे लगाने हैं और हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पौधे दिए हैं ताकि वह पौधे लगाए और इससे स्टेट को लाभ होगा तथा किसान को भी लाभ होगा। पिछले साल स्टेट में भयंकर सूखा पड़ा और भयंकर सूखा पड़ने के बावजूद भी भयंकर सूखे की स्थिति होते हुए भी जो पौधे लगाए थे उनमें से बहुसंख्यक पौधे लगे हैं इसके लिए इन्हें प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा प्रदेश सरकार की सराहना करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस साल भी हमारी सरकार ने साढ़े चार करोड़ पौधे लगाए हैं और अगर जनाब की सरकार का लेखा जोखा किया जाए तो यह अंतर एक से सौ के बीच भी मिल सकता है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न) इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाए।

Repair of Roads

***1656. Shri Krishan Lal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged roads of district Panipat :—

(i) Baljatan to Dharamgarh ;

(ii) Matlodha to Sehra ; and

(iii) Matlodha (Bus-stand) to Grain Market, Matlodha; if so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : हाँ, श्री मान जी। उक्त सड़कों की मरम्मत 30-09-2004 तक कर दिए जाने की सम्भावना है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, हालांकि मेरा सवाल माननीय कृषि मंत्री महोदय से था लेकिन रिप्लाई माननीय सी.पी.एस. महोदय दे रहे हैं इसलिए मैं माननीय सी.पी.एस. महोदय से कहना चाहूँगा कि तीन रोड्ज का जिक्र आया है और बताया गया है कि 30-09-2004 तक उनकी मुरम्मत करवा दी जाएगी। मतलौडा बस स्टैंड से मतलौडा अनाज मण्डी तक की सड़क की हालात बहुत ही खस्ता है। यह रोड बी. एण्ड आर. विभाग ने बनाई थी लेकिन पिछली बार इस रोड की रिपेयर एग्रीकल्चर मार्कीटिंग बोर्ड ने की थी। जब इस रोड की रिपेयर के लिए उनके अधिकारियों से बात करता हूँ तो बोर्ड के अधिकारी यह कहते हैं कि हमने यह रोड बी. एण्ड आर. डिपार्टमैंट को ट्रांसफर कर दी है और बी.एण्ड आर. डिपार्टमैंट वाले कहते हैं कि इसकी रोड रिपेयर मार्किटिंग बोर्ड करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि मतलौडा बस स्टैंड से मतलौडा अनाज मण्डी तक जो रोड है उसकी रिपेयर मार्किटिंग बोर्ड करेगा या बी. एण्ड आर. महकमा करेगा ?

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी श्री कृष्ण लाल पंवार जी को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश के मुताबिक जिन रोड्ज की हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी उनमें से करीब एक हजार किलोमीटर रोड्ज की मुरम्मत हमने मार्किटिंग बोर्ड के थ्रू करवाई थी और वे रोड्ज वापिस पी. डब्ल्यू. डी. को दे दी थीं। जहां तक मतलौडा बस स्टैंड से मतलौडा अनाज मण्डी तक की सड़क की बात है, इसके बारे में मैं अपने माननीय साथी कृष्ण लाल पंवार जी को यह आश्वासन देता हूँ कि वह रोड सितम्बर, 2004 तक पूरी कर दी जाएगी और इसके लिए उन्हें किसी दूसरे विभाग के पास जाने की जरूरत नहीं है।

श्री रमेश राणा : स्पीकर सर, यह बात तो ठीक है कि आज हरियाणा के अन्दर सड़कों की बहुत अच्छी हालत है लेकिन स्पीकर सर, जैसे कि हरियाणा गवर्नमैंट ने एक स्कीम बनाई थी कि गांवों के अन्दर जहां पर पानी ठहरता है वहां सीमेन्ट के पैच लगा दिए जाएंगे। मेरे हल्के के अन्दर सड़कें बहुत ही अच्छी हैं लेकिन कई जगहों पर पैच लगाने बाकी रह गये हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि ये पैच उन सड़कों पर कब तक लग जाएंगे ? इसके साथ ही गानजबड़ से बढ़ौली तक जो रास्ता जाता है उस पर ठेकेदार ने काम करना रोक रखा है। उस सड़क पर रोड़ी, मिट्टी इत्यादि डाल रखी है। पता नहीं क्यों वह ठेकेदार बीच में ही काम रोक कर चला गया है।

श्री अध्यक्ष : राणा जी, यह प्रश्न तारांकित प्रश्न से अलग है इसलिए आप इस प्रश्न को अलग से लिखकर भेज देना और मंत्री जी इसका जवाब आपको दे देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की मौजूदा सरकार की पॉलिसी है कि जहां कहीं पर भी पानी खड़ा रहता है वहां पर सीमेंटिड पैच लगाए जाएंगे। चाहे वह स्टेट हाई-वे हों, लिंक रोडज़ हों या दूसरी सड़कें हों, चाहे फिरनी ही क्यों न हों वहां पर सीमेंटिड रोड बनाएंगे क्योंकि पानी और तारकोल का कोई मेल नहीं होता है। मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार-बार।

Number of New Power Generation Projects

***1731. Shri Nafe Singh Jundla :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there are any new power generation projects in hand, in the State; if so, the number thereof togetherwith the time by which the said projects are likely to be completed ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : हां श्रीमान। राज्य में तीन नई बिजली उत्पादन परियोजनाएं हाथ में हैं। ये इस प्रकार हैं :--

1. 500 मैगावाट क्षमता की ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में 7वीं तथा 8वीं इकाई।
2. 14.4 मैगावाट क्षमता की पश्चिमी यमुना नहर, हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना चरण-2।
3. 500 मैगावाट क्षमता की यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना चरण-2।

[श्री राम पाल माजरा]

500 मैगावाट थर्मल क्षमता की पानीपत परियोजना वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है। पश्चिमी यमुना नहर, हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना चरण-2, मार्च 2004 तक तथा 500 मैगावाट क्षमता की यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना चरण-2, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लगभग अन्त तक पूरा होने का अनुमान है।

श्री नफे सिंह जुण्डला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सी.पी.एस. महोदय ने अपने उत्तर में दर्शाया है कि पानीपत की ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत की 250-250 मैगावाट की दो यूनिट्स का काम चल रहा है और यह 2004-05 में बन कर तैयार हो जाएंगी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह सवाल है कि ये यह बताएं कि ये यूनिट्स किस एग्जैक्ट टाईम पर कम्पलीट हो जाएंगी, कौन से महीने में कम्पलीट हो जाएंगी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इसके अलावा 14.4 मैगावाट की क्षमता की पश्चिमी यमुना नहर, हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना चरण-2 तथा 500 मैगावाट क्षमता की यमुनानगर थर्मल पावर परियोजना चरण-2 पर टोटल कितना खर्च आएगा ? मंत्री जी इस बारे में बताने का कष्ट करें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जुण्डला जी का प्रथम सवाल यह है कि पानीपत की 7वीं और 8वीं यूनिट कब चालू हो जाएगी। 7वीं और 8वीं यूनिट की कौमैंसिंग डेट 25.10.04 और 25.2.05 हैं। इस पर 945.33 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा मोनिटरिंग भी की जा रही है, बार-बार सर्वे किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि जो समय निर्धारित किया गया है उससे पहले ही ये यूनिट्स शरू होने जा रही हैं। समय से पहले काम कम्पलीट करने के लिए कम्पनी को 2 करोड़ रुपए प्रति महीने के हिसाब से इन्सैंटिव भी दिया जाएगा। इस बात का ऐलान किया गया है। जहां तक माननीय साथी ने जो यह जानना चाहा कि हाईड्रल प्रोजैक्ट की प्रोग्रैस रिपोर्ट क्या है तो अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर बहुत लम्बा रिप्लाई होगा। मैं इसके काम के बारे में इनको बताना चाहूँगा कि कितना-कितना काम किस-किस जगह पर अभी तक हुआ है। टर्बो जैनरेटर की स्थापना का काम 65 प्रतिशत तक पहुँच गया है, एग्जलरी की स्थापना का काम 50 प्रतिशत, 66 के.वी. रिचर्ड थार्ड पावर की वैक्यूएशन प्रणाली का काम 80 प्रतिशत हो गया है, एग्जलरी सप्लाई के 11 के.वी. फीडर का 70 प्रतिशत का काफी काम हुआ है। इसी तरह से और भी काफी काम सिविल वर्क्स के हुए हैं जैसे हाईड्रल चैनल को 1.5.2000 को चालू कर दिया गया है। इसी प्रकार से सिल इन्जैक्टर के बाई पास के चैनल का डी.आर. ब्रिज जंक्शन ज्वाइनिंग चैनल का कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से इन्होंने हाईड्रल प्रोजैक्ट के बारे में भी जानना चाहा है। मैं थोड़ा-सा इसके बारे में इनको बताना चाहूँगा कि चरण दो के दो यूनिट 7.2 मैगावाट के हैं। केन्द्रीय प्राद्योगिकरण से 1990 में 28.80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इसकी तकनीकी स्वीकृति मिली थी परन्तु यमुना पानी के बंटवारे पर इंटर स्टेट डिस्प्यूट होने की वजह से यह रुक गया था लेकिन फिर इसका विवाद हल हो गया था इसलिए पहली अप्रैल, 1996 को इसका कार्य फिर से शुरू हुआ। यह कार्य योजन के लिए और परियोजन के लिए शुरू किया गया था लेकिन इसके लिए ऋण जुटाने का कार्य पोखरण में विस्फोट के मामले को लेकर डिले हो गया। फिर पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन ने इसको क्रियान्वित करने के लिए इसके लिए 56 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1998 के आधार पर अब 70 करोड़ रुपये हो गयी है। इसमें ब्याज आदि के लिए 24 करोड़ रुपये और अतिरिक्त शामिल किए गए। इस योजना का सिविल कार्य 7.8.2000 को 20.99 करोड़ रुपये की लागत पर मैसर्ज हरिश्चन्द्र इंडिया लिमिटेड

को दिया गया था। इस कम्पनी ने सितम्बर, 2000 में पावर हाउस का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है और अब इस का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। 1.5.03 को हाईड्रल चैनल का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल ने इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल कार्य 19.12.03 को आरम्भ कर दिये है इसका भी 65 प्रतिशत का काम पूरा हो गया है। इस परियोजना पर अब तक 44.77 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। यह परियोजना मार्च, 2004 में चालू हो जाएगी। इसके बाद राज्य को प्रतिदिन लगभग दो लाख से लेकर तीन लाख यूनिट बिजली अतिरिक्त मिलेगी।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पावर जैनरेशन के नये कीर्तिमान स्थापित हुए हैं जिसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद और बधाई देते हुए आदरणीय माजरा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। फरीदाबाद में थर्मल पावर स्टेशन पूर्ण रूप से आउटडेटेड है और उसकी लाईफ प्राय: खत्म हो चुकी है लेकिन उसे चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि बल्लभगढ़ में दूसरा जो गैस बेस्ड थर्मल प्लांट है उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और उसको उसकी कैपेसिटी से आधे पर हम चला रहे हैं इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्लांट की लाईफ खत्म हो चुकी है और जिसकी अब कॉस्ट ऑफ जैनरेशन भी काफी आ रही है एवं वह रैजोडैंशियल एरिया में भी आ गया है और उससे पौल्यूशन वगैरह भी है। इसलिए इसको डिसपोज ऑफ करके इसका पैसा यूं का यूं ही मूलाहेड़ी वाले गैस बेस्ड थर्मल प्लांट में लगा दिया जाए तो वह भी अपनी पूरी कैपेसिटी से चल सकेगा और इससे स्टेट को भी बड़ी भारी मात्रा में पावर मिल सकती है जिससे स्टेट का चहुँमुखी विकास हो सकता है तो इसके बारे में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि बिजली हमारे लिए नेसैसिटी है हम बिजली का उत्पादन निरंतर बढ़ा रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट यकलक बंद करके कहीं दूसरी जगह मशीनरी लगाते हैं तो एक थर्मल पावर प्लांट को चालू करने के लिए कम से कम 3 साल का अर्सा चाहिए और हम जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं कर लेते हैं। जैसे हमने पानीपत की 7वीं और 8वीं यूनिट्स हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अगले साल फरवरी तक पूरी कर लेंगे। सातवीं यूनिट तो सितंबर, 2004 तक तैयार हो जाएगी। हमारी कोशिश यह है कि इस साल के अंत तक दोनों यूनिट्स तैयार हो जाएं। काफी देर से यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट का काम भी शुरू कर रखा है। हिसार का थर्मल पावर प्लांट का काम शुरू करने जा रहे हैं। गैस बेस्ड प्रोजैक्ट है जितनी बिजली गैस से पैदा होती है वह सारी की सारी हम ले रहे हैं। गैस की कुछ प्रौब्लम है ज्यों ही पूरी गैस अवेलेबल होगी। गैस से बनी बिजली सस्ती भी पड़ती है हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा मिले। जब दूसरी जगह समुचित व्यवस्था हो जाएगी तब इस पर विचार करेंगे। हम ऐसी किसी चीज को एकदम नहीं रखना चाहेंगे जिससे आर्थिक नुकसान हो, लोगों को नुकसान हो। हम यह समझते हैं कि पौल्यूशन भी बहुत है प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट भी अब बिजली बना रहे हैं जिनकी वजह से बहुत पौल्यूशन फैल रहा है हम कुछ करना भी चाहें तो उसके रास्ते में कोर्ट की दिक्कतें आ जाती हैं। हमारी हरसंभव कोशिश है कि हम लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और प्रदेश के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली भी पैदा कर सकें।

Transfer of Patients from one Hospital to another

*1713. **Sh. Suraj Mal :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to provide facilities of transfer of patients from one hospital to another, if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ० एम.एल. रंगा) : हाँ श्रीमान जी, सैक्टर निवेश प्रोग्राम के अंतर्गत सभी 64 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को एक से दूसरे अस्पताल में लाने ले जाने के लिए एक एम्बुलैंस उपलब्ध करना विचाराधीन है।

Construction of Power Sub-stations

*1635. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of Power Sub-stations constructed in the State during the year 2000-2001, 2001-2002, 2002-December, 2003 togetherwith the capacity and location of these Power Sub-stations alongwith expenditure incurred on each Sub-station ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

''विवरण''

राज्य में वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 (दिसम्बर 03 तक) के दौरान निम्नलिखित उप-केन्द्रों का निर्माण किया गया है।

वर्ष	220 के.वी.	132 के.वी.	66 के.वी.	33 के.वी.	योग	लागत (रुपए करोड़ों में)
2000-01	--	2	--	3	5	7.02
2001-02	--	1	6	5	12	28.35
2002-03	3	5	3	4	15	98.62
2003-04 (दिसम्बर 2003 तक)	2	11	2	14	29	114.08

प्रत्येक उप-केन्द्र की क्षमता स्थल, खर्च को दर्शाने वाला वर्षानुसार विवरण निम्न प्रकार से है :-

अप्रैल, 2000 से मार्च, 2001 तक चालू किए गए नए उप-केन्द्र :

क्रम सं०	उप-केन्द्र का नाम	जोड़ी गई क्षमता	लागत (रुपए लाखों में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
I.	132 के.वी.				
	1. कुण्डली	16 एम.वी.ए.	273	30-05-2000	सोनीपत

	2. पाली/गोठड़ा	16 एम.वी.ए.	229	22-12-2000	रेवाड़ी
	योग (I)	**32 एम.वी.ए.**	**502**		
II.	**33 के.वी.**				
	1. आई ए सिरसा	4 एम.वी.ए.	56	27-05-2000	सिरसा
	2. जहाजगढ़	6.3 एम.वी.ए.	78	19-01-2001	झज्जर
	3. कबारतन	4 एम.वी.ए.	66	23-03-2001	कैथल
	योग-II	**14.3 एम.वी.ए.**	**200**		
	योग (I-II)	**46.3 एम.वी.ए.**	**702**		

अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक चालू किए गए नए उप-केन्द्र :

क्रम सं०	उप-केन्द्र का नाम	जोड़ी गई क्षमता	लागत (रुपए लाखों में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
I.	**132 के.वी.**				
	1. सेक्टर 27/28, हिसार	16 एम.वी.ए.	234	27-08-2001	हिसार
	योग	**16 एम.वी.ए.**	**234**		
II.	**66 के.वी.**				
	1. सैक्टर 46, फरीदाबाद	16 एम.वी.ए.	332	28-04-2001	फरीदाबाद
	2. एन.एच.-3, फरीदाबाद	16 एम.वी.ए.	428	30-06-2001	फरीदाबाद
	3. सैक्टर-31, फरीदाबाद	16 एम.वी.ए.	320	31-10-2001	फरीदाबाद
	4. रायपुररानी	16 एम.वी.ए.	295	30-11-2001	पंचकूला
	5. सैक्टर-34, गुड़गांव	16 एम.वी.ए.	340	25-12-2001	गुड़गांव
	6. सैक्टर-55/56, गुड़गांव	16 एम.वी.ए.	345	28-02-2002	गुड़गांव
	योग (II)	**96 एम.वी.ए.**	**2060**		
III.	**33 के.वी.**				
	1. बीआना	6.3 एम.वी.ए.	128	20-07-2001	करनाल
	2. खुशपुरा	5 एम.वी.ए.	108	30-09-2001	रिवाड़ी
	3. अजित नगर / पेण्डा	4 एम.वी.ए.	130	31-08-2001	फतेहाबाद
	4. भवानीयां	5 एम.वी.ए.	86	08-02-2002	महेन्द्रगढ़
	5. डबलाना	5 एम.वी.ए.	89	09-02-2002	महेन्द्रगढ़
	योग (III)	**25.3 एम.वी.ए.**	**541**		
	योग (I-III)	**137.3 एम.वी.ए.**	**2835**		

[श्री राम पाल माजरा]

अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 तक चालू किए गए नए उप-केन्द्र :

क्रम सं०	उप-केन्द्र का नाम	जोड़ी गई क्षमता	लागत (रुपए लाखों में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
I.	**220 के.वी.**				
	1. यमुनानगर	100 एम.वी.ए.	1375	23-07-2002	यमुनानगर
	2. महेन्द्रगढ़	100 एम.वी.ए.	2068	29-12-2002	महेन्द्रगढ़
	3. फतेहाबाद	100 एम.वी.ए.	2458	31-01-2003	फतेहाबाद
	योग (I)	**300 एम.वी.ए.**	**5901**		
II.	**132 के.वी.**				
	1. करीवाला	16 एम.वी.ए.	543	11-04-2002	सिरसा
	2. मुंडियाखेड़ा	16 एम.वी.ए.	442	03-09-2002	महेन्द्रगढ़
	3. जलमाना	16 एम.वी.ए.	437	24-10-2002	करनाल
	4. सतनाली	16 एम.वी.ए.	508	09-11-2002	महेन्द्रगढ़
	5. नेवल	16 एम.वी.ए.	449	14-02-2003	करनाल
	योग (II)	**80 एम.वी.ए.**	**2379**		
III.	**66 के.वी.**				
	1. भौराकलां	12.5 एम.वी.ए.	215	30-10-2002	गुड़गांव
	2. छेन्सा	16 एम.वी.ए.	611	01-12-2002	फरीदाबाद
	3. मनसा देवी कम्पलेक्स पंचकूला	16 एम.वी.ए.	341	26-03-2003	पंचकूला
	योग (III)	**44.5 एम.वी.ए.**	**1167**		
IV.	**33 के.वी.**				
	1. केहरवाला	4 एम.वी.ए.	128	29-04-2002	सिरसा
	2. जी.टी. रोड, पानीपत	6.3 एम.वी.ए.	112	01-05-2002	पानीपत
	3. झांसा	6.3 एम.वी.ए.	81	22-06-2002	कुरुक्षेत्र
	4. जखौली	8 एम.वी.ए.	94	17-10-2002	कैथल
	योग (IV)	**24.6 एम.वी.ए.**	**415**		
	योग (I-IV)	**449.1 एम.वी.ए.**	**9862**		

अप्रैल, 2002 से मार्च, 2003 तक चालू किए गए नए उपकेन्द्र :

क्रम सं०	उप-केन्द्र का नाम	जोड़ी गई क्षमता	लागत (रुपए लाखों में)	चालू होने की तिथि	जिला का नाम
I.	220 के.वी.				
1.	चीका	100 एम.वी.ए.	1411	29-07-2003	कैथल
2.	टेपला	116 एम.वी.ए.	1624	03-10-2003	अम्बाला
	योग (I)	**216 एम.वी.ए.**	**3035**		
II.	132 के.वी.				
1.	अहेरवान	66 एम.वी.ए.	966	14-05-2003	फतेहाबाद
2.	हरसानाकलां	16 एम.वी.ए.	603	04-06-2003	सोनीपत
3.	कंगथली	32 एम.वी.ए.	507	09-06-2003	कैथल
4.	पाड़ला	32 एम.वी.ए.	740	25-06-2003	कैथल
5.	ऐलनाबाद	16 एम.वी.ए.	447	23-07-2003	सिरसा
6.	मतलोडा	16 एम.वी.ए.	647	24-07-2003	पानीपत
7.	भागल	16 एम.वी.ए.	515	25-08-2003	कैथल
8.	खरखोदा	16 एम.वी.ए.	484	29-08-2003	सोनीपत
9.	चाकुलदाना	32 एम.वी.ए.	616	08-09-2003	कैथल
10.	ओढान	26.3 एम.वी.ए.	499	26-11-2003	सिरसा
11.	लोहारू	16 एम.वी.ए.	490	31-12-2003	भिवानी
	योग (II)	**284.3 एम.वी.ए.**	**6514**		
III.	66 के.वी.				
1.	मुलाना	8 एम.वी.ए.	215	11-06-2003	अम्बाला
2.	कालका	16 एम.वी.ए.	274	08-12-2003	पंचकूला
	योग (III)	**24 एम.वी.ए.**	**489**		
IV.	33 के.वी.				
1.	खेवड़ा	8 एम.वी.ए.	114	04-06-2003	सोनीपत
2.	मूरथली	8 एम.वी.ए.	93	12-06-2003	कुरुक्षेत्र
3.	नेसी	8 एम.वी.ए.	88	12-06-2003	कुरुक्षेत्र
4.	क्योडक	8 एम.वी.ए.	97	17-06-2003	कैथल
5.	दरीयापुर	8 एम.वी.ए.	125	25-06-2003	फतेहाबाद
6.	मंजूरा	8 एम.वी.ए.	87	10-07-2003	करनाल

[श्री राम पाल माजरा]

7. साधनवास	5 एम.वी.ए.	78	21-07-2003	फतेहाबाद
8. कुलानी रोड, पानीपत	16 एम.वी.ए.	123	10-08-2003	पानीपत
9. पाडा	8 एम.वी.ए.	118	28-08-2003	करनाल
10. सीवाह	8 एम.वी.ए.	77	16-10-2003	पानीपत
11. बरवाला रोड, हांसी	8 एम.वी.ए.	85	03-11-2003	हिसार
12. सिसाय	8 एम.वी.ए.	90	19-11-2003	हिसार
13. रसूलपुर खेड़ी	8 एम.वी.ए.	85	21-11-2003	सिरसा
14. जेरपुर	8 एम.वी.ए.	110	25-11-2003	महेन्द्रगढ़
योग (IV)	**117 एम.वी.ए.**	**1370**		
योग (I-IV)	**641.3 एम.वी.ए.**	**11408**		

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा फरीदाबाद जिला हरियाणा का सबसे ज्यादा हैवी जनसंख्या वाला जिला है और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी फरीदाबाद के अंदर हैं और गांवों में लोगों को सब-स्टेशन सही न होने की वजह से बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती और ओवरलोडेड होने की वजह से कई दफा ज्यादा बिजली आती है जिससे टेलीविजन, फ्रिज और जो अन्य मशीनें हैं उनको खराब कर देती है। एक तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि फरीदाबाद में क्षमता के मुताबिक जितने सब-स्टेशन होने चाहिएं वह क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं दूसरे जो सब-स्टेशन लगाए गए हैं उनकी जो कॉस्ट बताई है अगर आंकड़ों से देखें तो 2002-03 में 30 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं और उनकी कॉस्ट 98.62 करोड़ है और 2003-04 में 58 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उनकी कॉस्ट 114.08 करोड़ है तो क्या माजरा साहब यह बताएंगे कि जो ये ट्रांसफार्मर हरियाणा में लगाए जा रहे हैं हमारी इन्फरमेशन के मुताबिक जो कॉस्ट इन सब-स्टेशनों पर आती है सही मायनों में इतनी कॉस्ट नहीं आती है यह जो भारी मात्रा में बिना जरूरत के धन खर्च किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि ये कम कीमत पर लगाए जा सकते हैं।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, पहला प्रश्न तो माननीय सदस्य ने यह किया है कि जिला फरीदाबाद में आवश्यकता के मुताबिक सब-स्टेशंज क्यों नहीं लगाये गये हैं ? स्पीकर सर, आवश्यकता के मुताबिक ही सब-स्टेशन लगाये हैं। पहला उप-केन्द्र पाला में 220 के.वी. का जो 3-2-2000 को कमीशन हुआ, इसी प्रकार से 66 के.वी. का उप-केन्द्र सैक्टर-46 फरीदाबाद में 15 एम.वी.ए. की क्षमता का लगाया है जो 28-4-2001 को कमीशन हुआ और जिस पर 322 लाख रुपये का खर्च आया। 66 के.वी. का उप-केन्द्र एन.एच.-3 फरीदाबाद में लगाया है जो 3-6-2001 को कमीशन हुआ और जिस पर 416 लाख रुपये का खर्च आया। 66 के.वी. का उप-केन्द्र सेक्टर-31 फरीदाबाद में लगाया है जो 31-10-2001 को कमीशन हुआ और जिस पर 225 लाख रुपये का खर्च आया। इसी प्रकार से 66 के.वी. का सब-स्टेशन छायसा में 1-12-2001 को कमीशन हुआ और 66 के.वी. का सब-स्टेशन अलेवा में 20-1-2001 को कमीशन

हुआ जिस पर 462 लाख रुपये का खर्च आया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि वहां की जनता को बिजली की और जरूरत है तो 2004-05 में 351 करोड़ रुपये की लागत से जो संयंत्र लगायेंगे उससे भी फरीदाबाद को बिजली और मिलेगी। 220 के.वी. का पाली में, 66 के.वी. का हसनपुर में, 66 के.वी. का अगोल में, 66 के.वी. का पुन्हाना में, 66 के.वी. का धोपाली में, 66 के.वी. का एस्कोर्ट-1 में और 66 के.वी. का फतेहपुर बिलोच में ये सब-स्टेशन 2004-05 तक लग जायेंगे, जिसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। जहां तक 33 के.वी. 66, 132, 220 के.वी.ए. के सब-स्टेशंज पर ज्यादा खर्च कराने की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, स्पीकर सर, मैं पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि बिड मांगी जा रही हैं और पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और इस बारे में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। सारे काम में पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है।

श्री भगवान सहाय रावत : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आज के जमाने में बिजली एक महत्वपूर्ण और आवश्यकता का प्रश्न है और इससे पहले प्रश्न संख्या 1731 जो माननीय सदस्य श्री नफे सिंह जुण्डला जी द्वारा पूछा गया था और बिजली के उत्पादन के बारे में था और प्रश्न संख्या 1635 जो श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने पूछा है वह वितरण के बारे में है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं इन प्रश्नों की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। क्योंकि सन् 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी उस समय सरकार लोगों को 24 घण्टे बिजली देती थी और आवश्यकता पड़ी तो अब सातवीं और आठवीं यूनिट पूरी होने के बाद यह सरकार जनता को 24 घण्टे बिजली देने में सक्षम हो जायेगी। दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने 40 वर्षों के दौरान इस बारे में कोई प्रयास नहीं किए जबकि हिमाचल प्रदेश आज अकेला सारे प्रदेश को बिजली देने में सक्षम हो गया है और राजस्थान का मरुस्थल भी अपने आप में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या हरियाणा प्रदेश भी कभी बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पायेगा और हम जनता को 24 घण्टे बिजली का वितरण कर सकेंगे। इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जैसा कि पहले प्रश्न के जवाब में जो कि श्री नफे सिंह जुण्डला जी ने किया था तब मैंने बताया था कि सातवीं और आठवीं यूनिट 2004-05 तक पूरी हो जायेंगी जिनमें 500 मैगावाट अतिरिक्त बिजली इस प्रदेश को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट्स थी जो अधूरी रह गई थी उनको यह सरकार आने के बाद पिछले चार सालों में पूरा किया है और यमुनानगर का हाईडल प्रोजैक्ट पूरा हो गया है और उससे भी हमें बिजली मिलेगी और पूरे हरियाणा में बिजली निरन्तर सप्लाई की जायेगी और जनता को इससे अत्यधिक बिजली मिलेगी।

Construction of Bye-pass in Sonipat

***1610. Shri Dev Raj Dewan :** Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under considration of the Government to construct a bye-pass in Sonipat City which is to be linked to Bahalgarh road passing through over-bridge across Rathdhana Road Chowk ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) तथा (ख) हाँ, श्रीमान् जी यह कार्य पहले ही कार्यान्वित है और अगले तीन महीनों में पूरा होने की संभावना है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वहां पर कई महीनों से काम बन्द है। इस बारे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारे वहां आये थे तब उनको बताया था। वहां पर जल्दी से काम शुरू करवाया जाये ताकि शहर के लोगों को दिक्कत न हो।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया है कि वहां पर बाईपास का काम तीन महीने में पूरा हो जायेगा। इसके लिए तिथि निर्धारित की हुई है यह काम टाइम बाउंड है।

तारांकित प्रश्न संख्या-1624

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री कंवरपाल सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Repair of Bhagvi Road

***1648. Ch. Jagjit Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the main road of Village Bhagvi, Tehsil Charkhi Dadri, District Bhiwani has been damaged badly ; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said road ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी।

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह काम कब तक पूरा होगा, क्या इसके लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है, क्या इसको टाइम बाउंड किया गया है। क्या यह सड़क इसी 31 मार्च तक बनाई जायेगी या अगले 31 मार्च 2004-05 तक बनाई जायेगी ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इसका जवाब हमने हाँ में दिया है इसके लिए निर्धारित समय नहीं रखा गया है। लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कि कन्क्रीट की सड़कें जहां भी बनाई जानी हैं वे 2004-05 तक पूरी कर दी जायेंगी।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से जानना चाहूँगा कि क्या इनकी नॉलेज में बेरी हल्के की ऐसी सड़कें हैं जिन पर बनने के बाद रिपेयर नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, 1995 में जब बाढ़ आई थी उसके बाद बेरी हल्के की बहुत सी सड़कों पर रिपेयर का काम नहीं

हुआ है। कुछ सड़कों का नाम मैं बताना चाहूँगा जैसे डीघल से कलावट, बेरी से बसीन, बेरी से पलड़ा और बेरी से सेरिया आदि सड़कें बनने के बाद इन पर रिपेयर का काम नहीं हुआ है। इस समय ये खराब हालत में हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, प्लीज आप बैठें। इन सड़कों का जिक्र आपने बजट पर बोलते हुए भी किया था।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर साहब की इस बात की सराहना करूंगा कि ये आपके obedient student बन गये हैं और एक बार कहने पर ही आपकी बात मान ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि जहां तक बेरी की सड़कों का ताल्लुक है केवल बेरी ही नहीं बल्कि हमारी सरकार इस बात के लिए पूर्ण रूप से वचनबद्ध है कि पूरे प्रदेश की सड़कों की जल्दी से जल्दी मरम्मत की जायेगी और हमारे प्रदेश की सड़कों की हालत ऐसी होगी कि इन पर हवाई जहाज को भी उतारा जा सकेगा।

स० जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं बेरी हल्के के बारे में कादियान साहब को बताना चाहूँगा कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार पांच साल तक रही तब बेरी हल्के में एक पैसा भी सड़कों पर खर्च नहीं किया गया। इसी तरह चौधरी बंसी लाल जी की भी साढ़े तीन साल तक सरकार रही लेकिन बेरी हल्के में सड़कों के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया लेकिन हमारी सरकार के चार साल के शासनकाल में बेरी हल्के में 1.8 करोड़ रुपया सड़कों की रिपेयर पर खर्च किया जा चुका है और यह पैसा मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से खर्च किया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 1649

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री तेजबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Commissioning of Grid Sub-stations

*1729. **Sh. Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of new Grid Sub-stations Commissioned during the period from 1.8.1999 up till now, in comparison to the period from March, 1991 to April, 1996 and May, 1996 to July, 1999 ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान दिनांक 24-07-1999 से 31-01-2004 तक 71 नए ग्रिड उप-केन्द्र चालू किए गए हैं।

मार्च 1991 से अप्रैल 1996 तक की अवधि के दौरान 69 नए उप-केन्द्र निर्मित किए गए और मई 1996 से जुलाई 1999 के दौरान 34 नए उप-केन्द्र निर्मित किए गए हैं।

Shortage of Drinking Water

***1674. Smt. Anita Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that there is acute shortage of drinking water in the villages of Kosli station, Jhanswa, Mohanbadi, Khanpur Kalan, Nilokheri, Mundahera in Salhawas constituency; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to meet out the shortage of drinking water of the said villages ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) :

(क) नहीं, श्रीमान् ! गांव कोसली स्टेशन, झांसवा, मोहनबाड़ी, नीलोखेड़ी तथा मुंडाहेड़ा में पेयजल स्तर 70 लिटर प्रति व्यक्ति दैनिक है, जबकि गांव खानपुर कलां में पेयजल स्तर 40 लिटर प्रति व्यक्ति दैनिक है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Bridges on Kutcha Tracks on Gatauli Karela Drain

***1719. Sh. Sher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bridges on Gatauli Karela Drain at various kutcha track locations to facilitate the movement of farmers of villages :—

(i) Ghadwali ;

(ii) Bhakta Khera , and

(iii) Karela-Jhamola ;

If so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(i) हाँ, श्रीमान जी।

(ii) नहीं, श्रीमान जी।

(iii) हाँ, श्रीमान जी।

गतौली करेला ड्रेन पर एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले 9 कच्चे रास्ते और इन गांवों के 9 खेतों के रास्ते हैं।

एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाले 9 कच्चे रास्तों में से 6 रास्तों पर पहले ही पुल बनाये हुए हैं, 2 पुल जो कि गांव करेला व घड़वाली के लिए हैं, के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है और निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा। एक पुल का निर्माण सरकारी नीति

के अनुसार योग्य नहीं पाया गया है।

खेतों के 9 कच्चे रास्तों में से 2 कच्चे रास्तों पर पहले से ही पुल का निर्माण किया हुआ है और शेष 7 कच्चे रास्तों पर पुल का निर्माण सरकारी नीति के अनुसार योग्य नहीं पाया गया है।

National Programme for Education for Girls

***1758. Sh. Ramesh Kumar Khatak :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the national programme for education of girls has been started in the State at elementary level, if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ० बहादुर सिंह) : जी, हां।

राज्य के 10 जिलों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 38 खंडों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है।

भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिए जनवरी 2004 में 1.09 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की है।

Roads constructed in Badhra Constituency

***1701. Sh. Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the new roads, constructed in kilometers in Badhra Constituency during the last four years ?

कृषि मंत्री (स० जसविन्द्र सिंह संधू) : गत चार वर्षों (24.07.1999 से 31.12.2003 के दौरान बाढड़ा निर्वाचन क्षेत्र में 5.646 किलोमीटर लम्बाई की चार नई सड़कें निर्मित की गई हैं।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Selection of Lecturers by Haryana Public Service Commission

186. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state the detail of lecturers selected by Haryana Public Service Commission in various subjects during the year 2001-2002 and 2002-2003 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2001-2002 और वर्ष 2002-2003 में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के चयन से सम्बन्धित सूचना क्रमशः अनुबन्ध 'क' और 'ख' में सदन के पटल पर रखी जाती है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

अनुबन्ध 'क'

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2001-2002 में प्राध्यापकों (कालेज काडर) के पदों की सिफारिशों का विवरण

क्र.सं.	विषय	वर्गवार रिक्तियों का विवरण							वर्गवार सिफारिशों का विवरण							टिप्पणी
		सामा.	अनु. जा. -ए	अनु. जा. -बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विकलांग	योग	सामा.	अनु. जा. -ए	अनु. जा. -बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विकलांग	योग	
1.	पंजाबी	4	1	--	--	--	--	5	4	1	--	--	--	--	5	
2.	वाणिज्य	23	4	4	4	2	1	38	23	4	4	4	2	1	38	
3.	कम्प्यूटर विज्ञान	13	2	2	2	1	--	20	13	--	--	--	--	--	13	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 2 अनु. जाति-ए, 2 अनु. जाति-बी, 2 पिछड़े जाति के तथा 1 पद भू.पू.सै. के खाली रहे
4.	मनोविज्ञान	4	1	--	--	--	--	5	4	1	--	--	--	--	5	
5.	गृह विज्ञान	4	1	--	--	--	--	5	4	1	--	--	1	--	5	
6.	अंग्रेजी	48	8	7	8	4	2	77	48	3	3	8	4	2	68	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 5 अनु. जाति-ए, 4 अनु. जाति-बी के पद खाली रहे
7.	भूगोल	32	5	5	5	2	1	50	32	5	5	5	2	1	50	

		वर्गवार रिक्तियों का विवरण							वर्गवार सिफारिशों का विवरण							
क्र.सं.	विषय	सामा.	अनु. जा.-ए	अनु. जा.-बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विकलांग	योग	सामा.	अनु. जा.-ए	अनु. जा.-बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विकलांग	योग	टिप्पणी
8.	राजनैतिक विज्ञान	8	1	1	1	1	--	12	8	1	1	1	1	--	12	
9.	इतिहास	34	6	5	6	3	2	56	34	6	5	6	2	1	54	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1 पद भू.पू.सै. के तथा 1 पद विकलांग के खाली रहे
10.	शारीरिक शिक्षा	13	2	2	2	1	--	20	13	2	2	2	1	--	20	
11.	लोक प्रशासन	2	--	--	--	--	--	2	2	--	--	--	--	--	2	
12.	समाज विज्ञान	7	1	1	--	--	--	9	7	1	1	--	--	--	9	
	योग	**192**	**32**	**27**	**28**	**14**	**6**	**299**	**192**	**25**	**21**	**26**	**12**	**5**	**281**	**18 पद खाली रहे।**

अनुबन्ध 'ख'

हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2002-2003 में प्राध्यापकों (कालेज काडर) के पदों की सिफारिशों का विवरण

क्र.सं.	विषय	वर्गवार रिक्तियों का विवरण							वर्गवार सिफारिशों का विवरण							टिप्पणी
		सामा.	अनु. जा. -ए	अनु. जा. -बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विकलांग	योग	सामा.	अनु. जा. -ए	अनु. जा. -बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विक-लांग	योग	
1.	संस्कृत	4	2	2	--	--	--	8	4	2	2	--	--	--	8	
2.	भूगोल	10	2	1	2	1	--	16	10	2	1	2	--	--	15	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1 पद भू.पू.सै. का खाली रहा
3.	अर्थ शास्त्र	3	1	1	--	--	--	5	3	1	1	--	--	--	5	
4.	गणित	5	7	7	--	--	--	19	5	--	1	--	--	--	6	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 7 अनु. जाति-ए, 6 अनु. जाति-बी के पद खाली रहे
5.	वनस्पति विज्ञान	6	2	2	--	--	--	10	6	1	2	--	--	--	9	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1 अनु. जाति-ए का पद खाली रहा
6.	मनोविज्ञान	10	4	3	2	1	--	20	10	2	2	2	--	--	16	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 2 अनु. जाति-ए, 1 अनु. जाति-बी तथा 1 भू.पूर्व.सै. के पद खाली रहे

क्र.सं.	विषय	वर्गवार रिक्तियों का विवरण							वर्गवार सिफारिशों का विवरण							टिप्पणी
		सामा.	अनु. जा. -ए	अनु. जा. -बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विकलांग	योग	सामा.	अनु. जा. -ए	अनु. जा. -बी	पिछड़ी जाति	भू.पू.सै.	विक-लांग	योग	
7.	दर्शन शास्त्र	2	1	--	--	--	--	3	2	1	--	--	--	--	3	
8.	अंग्रेजी	28	13	13	4	2	1	61	28	1	4	4	--	1	38	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 12 अनु. जाति-ए, 9 अनु. जाति-बी तथा 2 पद भू.पूर्व.सै. के पद खाली रहे
9.	सैन्य विज्ञान	7	1	1	1	--	--	10	7	--	--	1	--	--	8	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1 अनु. जाति-ए, 1 अनु. जाति-बी के पद खाली रहे
10.	गृह विज्ञान	--	1	1	--	--	--	2	--	1	--	--	--	--	1	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1 अनु. जाति-बी का पद खाली रहा
11.	इतिहास	--	1	1	--	--	--	2	--	1	1	--	--	--	2	
12.	राजनैतिक विज्ञान	--	2	1	--	--	--	3	--	2	1	--	--	--	3	
13.	भौतिक विज्ञान	--	1	1	--	--	--	2	--	--	1	--	--	--	1	उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण 1 अनु. जाति-ए, का पद खाली रहा
योग		**75**	**38**	**34**	**9**	**4**	**1**	**161**	**75**	**14**	**16**	**9**	**--**	**1**	**115**	**46 पद खाली रहे।**

12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

MR. SPEAKER : I read out the following directive dated 29th July, 2003 from the President of India received through the Secretary to Governor of Haryana Chandigarh :—

Directive by the President of India

"I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, having considered the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1996, which was reserved for my consideration under the provisions of Article 200 of the Constitution of India, do hereby direct, in pursuance of the proviso to Article 201 of the Constitution, that the Bill be returned to the Legislature of State of Haryana, together with a message to re-consider it and incorporate the following provision in the Bill :—

No person shall erect or re-erect any building or make or extend any excavation or lay out any means of access to a road within 30 metres on either side of the road reservation of a bye-pass or any scheduled road, provided that in case of National Highways the minimum distance from centre of the road reservation upto the point of erecting or re-erecting any building or making or extending any excavation or laying out by any means or access shall not be less than 60 metres."

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, मैंने और डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान ने एक काल अटैंशन मोशन रिगार्डिंग मिसिंग आफ श्री कर्ण सिंह दलित सरपंच, विलेज पहरावर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के बारे में दिया था, उसका क्या फेट है ? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपका यह काल अटैंशन मोशन मुझे मिल गया है और वह अंडर कन्सीडेशन है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काल अटैंशन मोशन रिगार्डिंग बर्थ एण्ड डैथस आफ न्यू बोर्न बेबीज इन हरियाणा के बारे में था। उसका क्या हुआ है ? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, वह अभी अंडर कंसीडेशन है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मेरा भी एक काल अटैंशन मोशन रिगार्डिंग बर्थ एण्ड डैथस आफ न्यू बोर्न बेबीज इन हरियाणा के बारे में था। उसका क्या फेट है ? (शोर एवं विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : आपका वह मोशन अन्डर कंसीडेशन है। (शोर एवं विघ्न) आप सभी बैठिए।

श्री शादी लाल बत्तरा : स्पीकर साहब, मैंने भी आपकी सेवा में एक मोशन दिया था। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा जी, आप बैठिए। आपने लिखकर कुछ नहीं दे रखा। (शोर एवं विघ्न) जबानी कुछ नहीं चला करता। आपने जो देना है लिख कर दें। अब आप बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। (शोर एवं विघ्न) कैप्टन साहब की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। (शोर एवं विघ्न)।

श्री शादी लाल बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रूलिंग की कोई बात नहीं है जब कोई ईशू उठाएंगे तो मैं अपना जवाब दूंगा। बत्तरा जी आपने कोई ईशू के बारे में लिखकर ही नहीं दिया हुआ तो फिर आपके पूछने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। (विघ्न एवं शोर) कोई भी बात जुबानी नहीं होती है। जब तक कोई लिखकर नहीं देगा मुझे क्या मालूम कि वह क्या इन्फर्मेशन चाहता है ? जिन दो मैम्बर्ज ने लिखकर दिया था उन्होंने उसके बारे में जानकारी चाही है और वह मैंने उनको बता दिया है। (विघ्न एवं शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रोटैक्शन चाहता हूँ आप इन माननीय सदस्यों को बिठाएं। जब ये बैठेंगे मैं तभी बोलूंगा।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप बैठें। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, * * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठें। कादियान साहब की कोई भी बात रिकॉर्ड न करें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलने के लिए खड़ा हूँ लेकिन जब तक ये नहीं बैठेंगे मैं कैसे बोलूंगा ? आपसे निवेदन है कि आप इन लोगों को बिठाएं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ट्रिब्यून में यह खबर छपी है और इसके बारे में मैंने एक कॉलिंग अटैंशन मोशन आपकी सेवा में दिया है आप उसको भी कल के लिए ऐडमिट करने की मेहरबानी करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हरियाणा राज्य में तथा विशेषकर फरीदाबाद में मुँह तथा खुर की बीमारी फैलने संबंधी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a calling attention notice from Sarvshri Karan Singh Dalal and Jagjit Singh, MLAs regarding a disease of mouth and foot in cattle is spreading in the district Faridabad in particular and in

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[Mr. Speaker]
the State of Haryana in general. I admit it. Now, Shri Karan Singh Dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं इस महान सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आमतौर पर हरियाणा राज्य में तथा विशेषकर जिला फरीदाबाद में पशुओं में मुँह तथा खुर की बीमारी फैल रही है। इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों पशु मर रहे हैं तथा पशु पालन विभाग इस संबंध में कुछ नहीं कर रहा है।

इसलिए वे सरकार से निवेदन करते हैं कि वह इस संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

Mr. Speaker : Now, a Minister will make a statement.

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : श्रीमान् जी,

राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन के योगदान के व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा को विश्व प्रसिद्ध मुर्राह नस्ल की भैंसों एवं देसी नस्ल की गायों 'साहीवाल' व 'हरियाना' का घर होने पर गर्व है और इसे भारत के 'दूध के भण्डार' के रूप में सही जाना जाता है।

राज्य के अस्तित्व में आने के बाद दुग्ध उत्पादन में अत्यन्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय दुग्ध उपलब्धता 226 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति 656 ग्राम है और यह पंजाब के बाद देश में उच्चतम है। यद्यपि प्रगति उल्लेखनीय है, फिर भी सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है और इसीलिये राज्य सरकार ने पशुधन उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

यह कहना अनुचित है कि मुँह-खुर बीमारी के कारण राज्य में आम तौर पर और जिला फरीदाबाद में विशेष रूप से सैंकड़ों पशु मर रहे हैं। निस्सन्देह हम मुँह-खुर बीमारी से मुक्त नहीं हैं और यही कारण है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए हरियाणा राज्य ही शायद प्रथम राज्य था जिसने इस दिशा में एक विस्तृत प्रस्ताव बना कर प्रभावी कदम उठाये जो कि न केवल राज्य के लिये ही अपितु पूरे देश के लिये महत्वपूर्ण है। हमें यह बताते हुए अति हर्ष होता है कि पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के इस प्रस्ताव के आधार पर ही पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, भारत सरकार ने अन्ततः "FMD-CP" (मुँह-खुर बीमारी नियन्त्रण कार्यक्रम), को अनुमोदित किया जो कि पूरे देश के लिए अनुमोदित कुल 54 जिलों में से, आरम्भिक चरण में राज्य के आठ जिलों जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा जिला भिवानी में तोशाम से 23-1-2004 को किया गया था और इसका प्रथम चरण पूर्ण होने जा रहा है और इस कार्यक्रम हेतु गठित की गई 400 टीमें चौबीस घन्टे कार्य करती रहती हैं। मुझे यह बताते हुए और भी हर्ष होता है कि बाकी 11 जिलों के लिये भी राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है

और यह कार्यक्रम शीघ्र ही आरम्भ किया जावेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरुकता अभियान चलाया गया। सारे कार्यक्रम पर वर्तमान वित्त-वर्ष में लगभग 12 करोड़ रुपये की राशि व्यय होनी सम्भावित है, कार्यक्रम दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगा।

संक्षेप में, यही नहीं, पशु उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं जो निम्न अनुसार हैं :--

1. हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान, हिसार को पी.पी.आर. टीके के उत्पादन हेतु पूरे देश के छः केन्द्रों में से एक के रूप में अनुमोदित किया गया है।

2. वर्ष 2002-03 में सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए सम्पूर्ण राज्य में 9184 विशेष स्वास्थ्य सुधार कैम्पों का आयोजन किया गया जिसका इस माननीय सदन में भारी स्वागत किया गया था।

3. जिला अस्पतालों को चरणबद्ध रूप से पोलीक्लीनिक में बदलने के लिए एक योजना नाबार्ड के विचाराधीन है।

4. एक विस्तृत प्रभावी स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें बांझपन प्रबन्धन भी शामिल है, 2500 गांवों, विशेषकर जिनमें पशु संस्थाएँ नहीं है, में शीघ्र ही चलाया जाएगा।

5. राज्य में मुर्राह नस्ल को बढ़ावा देने के लिए 321.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि पिछले तीन सालों के दौरान दी गई है।

6. राज्य की सभी पशु संस्थाओं में उत्तम हिमकृत वीर्य उपलब्ध है।

7. नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान को और बढ़ावा देने के लिए राज्य में काफ रैलीज काफ हैल्थ कैम्प नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस वित्त वर्ष के अन्त तक ऐसी 200 काफ रैलियाँ लगाई जाएँगी।

8. वर्ष 2001-02 से अब तक 547.71 लाख रुपये की राशि गोशालाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है।

9. हरियाणा पशुधन बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य है जहाँ 50% प्रीमियम राज्य द्वारा वहन किया जाता है। अब तक 6713 पशुओं का बीमा करवाया जा चुका है।

10. उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता प्राप्त 353 मुर्राह सांड 2000 रुपये प्रति सांड की रियायती दर पर प्रजनन हेतु ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाये गये हैं।

11. राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड तथा भारतीय ऐग्रो इण्डस्ट्रीज जैसी राष्ट्र स्तर की प्रसिद्ध संस्थाओं को 38 मुर्राह झोटे दिये गये हैं जो तीन वर्ष की छोटी सी अवधि में प्राप्त की गई हमारी सफलता के मुंह बोलते प्रमाण हैं।

12. पूरे राज्य में नई पशु संस्थाओं के खोलने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और कई अन्य विचाराधीन हैं।

[श्री राम पाल माजरा]

13. 204 पशु चिकित्सक, 358 पशुधन विकास सहायक भर्ती किये गए हैं। और तो और पशुधन की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 30 पशु चिकित्सालयों तथा 200 पशु औषधालयों के लिए भी अमला वर्तमान सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो कि वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 से बिना अमले के कार्य कर रही थी।

14. विश्व बैंक की सहायता से (जहां पर विभागीय अमले को प्रशिक्षित करने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है) एक पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में स्थापित किया गया है। अब तक 1882 विभागीय कर्मचारियों को 5/2001 को इसके अस्तित्व में आने के बाद प्रशिक्षित किया जा चुका है।

15. 2111 महिलाओं को पशुपालन पद्धतियों में प्रशिक्षण देने के लिये 3.88 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

16. इसके अतिरिक्त, 93 शिक्षित बेरोजगार युवा उद्यमियों को भी हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान, हिसार में प्रशिक्षित किया गया है जिससे वे एक ओर सफलतापूर्वक अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं तो दूसरी ओर उन गावों में जहां कोई पशु चिकित्सा संस्था नहीं है, के पशुपालकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

17. "पशुधन भवन" जिसे गत दिनों 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और जिसमें वर्तमान हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड एवं पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के कार्यालय चल रहे हैं, के प्रांगण से शीघ्र ही "एडवांसड ट्रेनिंग इन एनिमल ब्रीडिंग" में प्रशिक्षण आरम्भ किया जायेगा।

18. विभाग को न केवल मानव संसाधन विकास सुविधाएं प्रदान करके, अपितु भ्रूण स्थानान्तरण तकनीक व उत्तम वीर्य उत्पादन के लिये प्रयोगशालाओं को स्टेट ऑफ दी आर्ट के रूप में सुदृढ़ किया गया है।

19. लगभग 20 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से बनने वाला एक आधुनिक पशुशाला (Dairy Complex) हिसार में शीघ्र ही कार्यरूप में आ जाएगा।

20. हमारे द्वारा विकसित, "पशुधन" नामक एक अद्वितीय "मैनेजमेंट इनफारमैशन सिस्टम" (MIS), की भारत सरकार द्वारा प्रशंसा की गई है तथा इसे पूरे देश के लिये एक माडल के रूप में चुना गया है।

21. दाना उत्पादन की गुणवत्ता और इसकी किसानों को उपलब्धता के लिये एक विशेष अभियान चलाया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, इनको इस बारे में मालूम है कि यह जो बीमारी प्रदेश में फैली हुई है और मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. साहब से जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हैं। अगर ये इस बारे में बता देंगे तो प्रदेश के किसानों को पता चल जाएगा कि यह बीमारी क्यों फैल रही है और वे उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इन्होंने अभी जो जवाब पढ़ा है उसमें इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसके अलावा स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना

चाहता हूँ कि इस बीमारी की वजह से जो पशु मर गए हैं, क्या उन पशुओं के मालिकों को यह सरकार कोई अनुदान देने के बारे में विचार करेगी ? स्पीकर सर, आपको भी पता है कि वे किसान गरीब होते हैं और 30,000 या 40,000 रुपए से कम का आज की तारीख में कोई भी पशु नहीं आता है। इसके साथ ये यह भी बताएं कि किस की लापरवाही की वजह से यह बीमारी प्रदेश में फैली है और इस बीमारी के फैलने के कारणों के बारे में इन्होंने पूरे आंकड़े नहीं दिए हैं खासकर मेवात और हमारे फरीदाबाद जिले के बारे में। हमारे फरीदाबाद जिले में जितनी भी नहरें और रजवाहे चलते हैं उनमें तो वैसे ही बहुत गंदा पानी चलता है इसलिए उनका पानी पीकर भी पशु बीमार रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो इस बारे में डी.सी., फरीदाबाद को भी फोन किया था, विभाग के अधिकारियों को भी फोन किया और अखबारों में भी अपना इस बारे में बयान दिया कि यह बीमारी फैली हुई है इसलिए अधिकारियों को गांवों में जाना चाहिए लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं सप्लीमैंट्री ही पूछ रहा हूँ। स्पीकर सर, इनके विभाग के अधिकारियों ने सरकार से मिली हुई दवाईयां उन किसानों और मजदूरों को मुहैय्या नहीं करवायीं। चूंकि उन लोगों ने अपने घर से पैसा लगाया है और इनके विभाग ने पशुओं की दवाई और इलाज के लिए किसानों और मजदूरों से पैसे वसूले हैं तो क्या उन किसानों और गरीब मजदूरों को सरकार अपनी तरफ से अनुदान देने पर विचार करेगी ? इसके अलावा मेरी आखिरी सप्लीमैंट्री आपके माध्यम से यह है कि सरकार ने हमारे जिले के लोगों को तो दरकिनार किया ही हुआ है उनकी कोई परवाह नहीं हो रही है तो क्या हमारे जिले के पशुओं की तरफ भी इन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया है क्योंकि जो इस बारे में स्कीम इन्होंने लागू की है जिसका जिक्र इन्होंने अभी किया है कि 6 जिलों में यह स्कीम लागू की गयी है लेकिन इन 6 जिलों में इन्होंने हमारे फरीदाबाद जिले को शामिल नहीं किया है जबकि यह बीमारी सबसे ज्यादा फरीदाबाद और मेवात के इलाके में ही फैली हुई है। इनको हमारे फरीदाबाद जिले को भी इस स्कीम में शामिल करना चाहिए था। हमें दुःख इस बात का है कि इस विभाग का मंत्री भी उसी इलाके का रहने वाला है और उसके इलाके में सबसे ज्यादा यह बीमारी भी है फिर भी उस जिले को इस स्कीम में शामिल क्यों नहीं किया गया है ? इसलिए मेरा कहना है कि क्या सरकार इस स्कीम के तहत हमारे फरीदाबाद जिले को और जहां-जहां पर यह बीमारी फैली है उनको भी इसमें शामिल करने पर विचार करेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित साथी का ध्यान इस तरफ अवगत करवाना चाहूँगा कि इन्होंने जो अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ा है उसमें इन्होंने दो बीमारियां दर्शायी हैं जबकि ये दो बीमारियां नहीं हैं। (विघ्न) इन्होंने दो बीमारियां कही हैं जबकि है एक ही। यह मुँहखुर की बीमारी है लेकिन इन्होंने पढ़ते वक्त मुँह तथा खुर पढ़ा है। ये दो बीमारी नहीं हैं एक ही है। इनको तो कई बीमारियां हैं लेकिन पशुओं की यह एक ही बीमारी है और जैसा इसके लिए बताया गया है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से सतर्क है। इसकी पेशबंदी के लिए 23 तारीख को पूरे प्रदेश के स्तर पर लोशाम में टीकाकरण की व्यवस्था शुरू की गयी है सरकार हर पशु को टीका लगा रही है इसलिये यदि कोई पशु मरा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस किसान की लापरवाही हुई। क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने तो बीमा स्कीम के तहत पहले से भी घोषणा की हुई है कि सरकार ने पशुधन को बचाने के लिए एक बीमा योजना लागू की है जिसमें आधा पैसा सरकार वहन करेगी और

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

आधा पैसा किसान का लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते हैं कि किसान का पशु बहुत कीमती है क्योंकि आज गाय, भैंस और बैल चालीस-चालीस या पचास-पचास हजार रुपये में आम बिकते हैं। हमारा प्रदेश एक दूध उत्पादक प्रदेश है। अगर किसान का परिवार बढ़ेगा तो जमीन की जोत घटनी स्वाभाविक है इसलिए जिंदगी की जरूरी अखराजात पूरी करने के लिए हमने पशुधन को बढ़ावा देने के हिसाब से ही एक पशुधन विकास बोर्ड का भी गठन किया हुआ है। हम तो दुधारू पशु को ईनामात भी देते हैं और अगर कोई बेरी के पशु मेले से जो अच्छा गधा भी बिकता है तो उसकी भी सरकार पूरी देखभाल करती है। समय-समय पर अगर कहीं चूक भी कर जाते हैं तो उनको पुनःअवसर प्रदान किया जाता है। इस तरह से सरकार हर वर्ग का पूरा ख्याल करती है। पशुधन इसलिए भी जरूरी है कि आज भारत विश्व में से सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रदेश हैं उनमें हरियाणा दूसरे नम्बर पर है इसलिए हम तो चाहते हैं कि हरियाणा डेनमार्क को भी बीट करें ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और किसान आर्थिक तौर पर समृद्ध हो, सम्पन्न हो। यह सरकार की नीति है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, बेरी में जो गधे बिकते हैं वह बाहर से आते हैं इसलिए इनको यह भी तो बताना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आपको क्यों इतना असर हो रहा है ? मैं भी तो यहां बैठा हूँ। आप क्यों इस पर परेशान हो रहे हैं ? (विघ्न)

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी में जिलेवार कितने पशु मरे हैं और हरेक डिस्ट्रिक्ट में कितने-कितने पशु सारे हरियाणा में मरे हैं ? अकेले मुंहखुर रोग के ऊपर हरियाणा के अंदर सारे जिलों में कितने पैसे दवाइयों के ऊपर खर्च किए हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक माननीय साथी ने यह जानना चाहा कि यह जो आउटब्रेक हुए इससे कितने पशु मरे। जहां तक जिलेवार बताने की बात है फरीदाबाद जिले में कोई पशु नहीं मरा, सिरसा में कोई नहीं मरा, फतेहाबाद में कोई पशु नहीं मरा। हिसार में 1 हजार इफैक्टेड हुए हैं और 93 की डैथ हुई है। भिवानी जिले में 2003-04 में आउटब्रेक 6 हुई, 169 इफैक्टिड हुए, कोई डैथ नहीं हुई। महेन्द्रगढ़ में कोई डैथ नहीं हुई, रिवाड़ी में भी कोई डैथ नहीं हुई। गुड़गांव में 2 आउटब्रेक 45 इफैक्टिड, डैथ कोई नहीं। फरीदाबाद में 2 आउटब्रेक, 80 प्रभावित हुए, डैथ कोई नहीं, झज्जर में 4 आउटब्रेक, 23 इफैक्टिड, कोई डैथ नहीं, रोहतक में 6 आउटब्रेक, 293 इफैक्टिड, डैथ कोई नहीं। इसी प्रकार से सोनीपत में कोई डैथ नहीं, पानीपत में कोई डैथ नहीं, जींद में कोई डैथ नहीं, करनाल में 7 आउटब्रेक, 1580 इफैक्टिड, डैथ कोई नहीं, कैथल में 6 आउटब्रेक, 2132 प्रभावित, 28 की डैथ हुई, कुरुक्षेत्र में 2 आउटब्रेक, 24 इफैक्टिड और डैथ कोई नहीं, अम्बाला में 4 आउटब्रेक, 195 इफैक्टिड और 5 की डैथ हुई और कुल मिलाकर 47 आउटब्रेक, 5276 इफैक्टिड और 126 की डैथ हुई। स्पीकर सर, प्रदेश में 1 करोड़ 19 लाख पशु हैं आप मेजरमैंट करें, इसका अंदाजा लगाएं तो यह संख्या नगण्य है। इसमें इतना ही नहीं माननीय साथी कह रहे थे इनको तो खुशी होनी चाहिए कि भिवानी से, तोशाम से इस बीमारी की रोकथाम की शुरुआत की गई है। सम्मानित साथी श्री कर्ण सिंह दलाल कह रहे थे कि हमारे जिले को शामिल नहीं किया गया।

मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसकी अगली योजना में मंजूरी मिली है। 11 जिलों में इस योजना को मंजूर कर दिया गया है अब वहां से इस रोग की रोकथाम शुरू होगी। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पशु मेले लगाए जाते हैं, लोगों को चिकित्सा दी जाती है और यह प्रोग्राम 3 वर्ष तक चलेगा। एक दिन में यह बीमारी खत्म नहीं होती है तोशाम से यह बीमारी तीन साल में खत्म करने का जनांदोलन चलाया है।

(इस समय श्री राम पाल माजरा ने मुंहखुर बीमारी के बारे में सदन में एक पम्फलेट दिखाया।)

स्पीकर सर, यह पम्फलेट देखकर खुशी होगी कि इसके अन्दर यह दिया हुआ है कि बीमार पशुओं को 6 महीने के अन्तराल में टीके लगाये जाते हैं, फिर 9 महीने में लगाये जाते हैं और फिर एक साल में लगाये जाते हैं। स्पीकर सर, सारे बीमार पशुओं के लिए बाकायदा एक कार्ड दिया गया है और इस बारे में पूरा प्रचारित किया गया है और इस पम्फलेट में सारी जानकारी दी हुई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठिये। यह पम्फलेट तो मंत्री जी के जवाब का हिस्सा है इसलिए सदन में दिखाया है। जो मैम्बर बिना इजाजत हाउस में खड़े हैं उनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, * * * *

श्री शादी लाल बत्तरा : स्पीकर सर, * * * *

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * *

श्री राम पाल माजरा : इसकी वजह से इस पम्फलेट को राष्ट्र स्तर पर भी निकाला गया है। पूरे देश में इस बीमारी से 54 जिले प्रभावित हैं जिनमें आठ जिले हरियाणा के हैं। जैसा कि कर्ण सिंह दलाल ने कहा है कि हमारी सरकार ने इस बारे में क्या किया। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के एनिमल हस्बैंड्री के कमिश्नर ने हमें इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है उसको मैं सदन में पढ़कर सुना देता हूँ :--

'I am glad to inform you that keeping in view the comprehensive functional coverage, simplicity, easy data entry protocol and user-friendly interface of the MIS developed by Haryana, it has been found to be most suitable and, therefore, chosen as a model for replication in the entire country. We appreciate the efforts of your dedicated team responsible for evolving such a beautiful system code named PASHUDHAN.'

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ।****

वाक-आउटस

श्री अध्यक्ष : आपकी सप्लीमैंट्री हो चुकी है आपको दूसरे प्रश्न की इजाजत नहीं है इसलिए अब आप बैठ जाइये। आपका जवाब दिया जा चुका है। इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ***

श्री अध्यक्ष : आपकी सप्लीमैंट्री भी हो चुकी है दूसरे प्रश्न की इजाजत नहीं है आप बैठ जाइये। आपका जवाब दिया जा चुका है। इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के एक मात्र सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल सदन से वाक आउट कर गये)

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे भी बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूँ।

(इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री जगजीत सिंह सदन से वाक आउट कर गये)

विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना

(i) अधीनस्थ विधान समिति की 34वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Vaid Kapoor Chand, Chairperson, Committee on Subordinate Legislation will present the Thirty Fourth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2003-2004.

वैद्य कपूर चन्द (चेयरपर्सन, अधीनस्थ विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2003-2004 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 34वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) सरकारी आश्वासन समिति की 34वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Nafe Singh Jundla, a Member of the Committee on Government Assurances, will present the Thirty Fourth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2003-2004.

Shri Nafe Singh Jundla (A Member of the Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Thirty Fourth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2003-2004.

(iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए बनी समिति की 28वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Nishan Singh, Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty Eighth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2003-

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

2004.

Sardar Nishan Singh (Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes) : Sir, I beg to present the Twenty Eighth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2003-2004.

(iv) लोक लेखा समिति की 56वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Krishan Lal Panwar, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2003-2004 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999 (Civil).

Shri Krishan Lal Panwar (Chairperson, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Fifty Sixth Report of the Committee on Public Accounts for the year 2003-2004 on the Report of the Comptoller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1999 (Civil).

(v) लोक उपक्रम समिति की 51वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Rajinder Singh Bisla, Chairperson, Committee on Public Undertakings, will present the Fifty First Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2003-2004 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 1998-1999 & 1999-2000 (Commercial).

Shri Rajinder Singh Bisla (Chairperson, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Fifty First Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2003-2004 on the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the years 1998-1999 & 1999-2000 (Commercial).

(vi) प्राक्कलन समिति की 35वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Dr. Malik Chand Gambhir, Chairperson of the Committee on Estimates will present the Thirty Fifth Report of the Committee on Estimates for the year 2003-2004 on the Budget Estimates for the year 2003-2004 (Environment Department).

Dr. Malik Chand Gambhir (Chairperson, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Thirty Fifth Report of the Committee on Estimates for the year 2003-2004 on the Budget Estimates for the year 2003-2004 (Environment Department).

वर्ष 2004-05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : दिनांक 13-02-2004 को बजट पर काफी लम्बी बहस हुई। मैंने सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। उस दिन हाउस एडजोर्न करने से पहले भी

माननीय सदस्यों को, जो बोलना चाहे, बोलने के लिए कहा और जब कोई भी सदस्य बोलने के लिए तैयार नहीं था तब हाउस आज तक के लिए एडजोर्न कर दिया था और आज माननीय वित मंत्री जी ने बहस का जवाब देना है। अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे रिप्लाई दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शादी लाल बनेरा : अध्यक्ष महोदय, . . . (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री जी अपना रिप्लाई देंगे। प्लीज, आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, . . . (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी बहुत ही सीनियर मैंबर हैं और यह वित्त मंत्री भी रहे हैं। अगर ये बजट पर बोलना चाहते हैं तो आप इन्हें बोलने के लिए 10 मिनट का समय दे दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनको 10 मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, 13 तारीख को हाउस सवा चार बजे के करीब एडजोर्न हुआ था। उस दिन मैंने सभी मैंबरों को बोलने के लिए पूरा अवसर दिया था। आपकी तरफ से तीन-चार बार बोलने के लिए लिस्ट आई थी। जिस समय हाउस ऐडजार्न हुआ उस समय आपकी तरफ से कोई नहीं बोलना चाहता था। प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उस दिन गुप्ता जी बीमार थे इसलिए नहीं बोले। गुप्ता जी वित्त मंत्री रहे हैं से सरकार को अच्छे सुझाव भी देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें। अब वित्त मंत्री जी अपना जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकार चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन चौधरी भजन लाल जी सदन में नहीं थे। आपकी तरफ से गुप्ता जी को कहा गया था कि गुप्ता जी आप बोलना चाहते हैं तो बजट पर बोलें। हम भी यह समझते थे कि गुप्ता जी वित्तमंत्री रहे हैं और अच्छे सुझाव देंगे लेकिन इन्होंने बोलने में असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अध्यक्ष महोदय, हम तो चौधरी बंसी लाल जी का भी इंतजार कर रहे थे कि उनको भी बोलने का अवसर दिया जायेगा आज वे हाजरी लगाने के लिए आये थे लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको समय का भी ध्यान रखना है। जिस समय वित्तमंत्री जी रिप्लाई दें उस समय गुप्ता जी बीच-बीच में सुझाव दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब गुप्ता जी वित्तमंत्री थे और हम अपोजिशन में थे तब हम सदन का समय बचाने के लिए इनको कहते थे कि आप जो बजट पढ़ रहे हैं उसे हम बिना पढ़े ही पढ़ा हुआ मान लेते हैं और इनको कहते थे कि आप बैठ जायें ताकि सदन का समय बचे।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको बजट पर बोलने के लिए 10 मिनट का समय दिया जायेगा तो ये सरकार को अच्छे सुझाव भी देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, गुप्ता जी डिमांडज पर बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, उस दिन गुप्ता जी का गला खराब था इसलिए ये नहीं बोले।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इनको आज बोलने का अवसर दिया जाए। ये सरकार को अच्छे सुझाव देंगे और इससे प्रदेश को लाभ होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपका कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। आप किस बात के लिए प्वायंट ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बजट पर बोलने न देना लेकिन प्वायंट ऑफ आर्डर पर तो बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, 13 तारीख को करीब सवा चार बजे तक हाउस चला और आपको बोलने के लिए भी कहा गया लेकिन आप नहीं बोले। अब आप प्वॉट्स पर बोल लेना। प्लीज, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपसे बजट पर बोलने की इजाजत नहीं मांग रहा। मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपका किस बात के लिए प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि बी.ए.सी. के अनुसार आज के लिए जो प्रोग्राम बना है जो हमें दिया गया है उसके अनुसार आज पहले बजट पर डिस्कशन होगी और उसके बाद वित्त मंत्री जी की रिप्लाई होगी। यह इस प्रोग्राम में लिखा हुआ है। इसीलिए स्पीकर सर, आपने शुक्रवार को बोलने के लिए कहा था लेकिन हमने कहा कि हम नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप डिमांडज पर बोल लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये हर डिमांड पर बोल सकेंगे ये इनका अधिकार है। ये डिमांड्ज पर बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हाउस आपने चलाना है। किसने कब बोलना है यह आपने देखना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, हाउस सदन के नेता और विपक्ष के नेता यानि कि सभी सदस्यों से मिलकर चलाया जाता है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हाउस तो आपके उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए। बी.ए.सी. की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आज पहले बजट पर डिस्कशन होगी उसके बाद वित्त मंत्री जी रिप्लाई देंगे।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आज वित्त मंत्री जी जो रिप्लाई देंगे वह भी इसी का हिस्सा है। (शोर एवं व्यवधान) वित्त मंत्री जी जवाब नहीं देंगे क्या ? वह भी डिस्कशन का हिस्सा है। प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप गुप्ता जी को 10 मिनट का समय दे दें, उसके बाद वित्त मंत्री जी अपना जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, शुक्रवार को आपसे तीन लिस्टें आई थीं और आपके सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया गया था तथा बाद में भी पूछा गया था कि और कोई सदस्य आपकी तरफ से बोलना चाहता है तो बोले। प्लीज, अब आप बैठें।

चौ० भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, या तो आप मांगे राम गुप्ता जी को बजट पर बोलने के लिए समय दें, नहीं तो हम सदन से वाक-आउट करके चले जायेंगे। हम वित्त मंत्री जी की रिप्लाई नहीं सुनेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने तय कर लिया है कि इनको जवाब सुनायेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। इसलिए गुप्ता जी को बोलने के लिए समय दे दिया जाये। पहले हम गुप्ता जी को सुनेंगे उसके बाद वित्तमंत्री जी अपना जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आपको बजट पर बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है। आपके बाकी सभी साथी तो शुक्रवार को बोल चुके हैं आप उस दिन मौका चूक गये। (शोर एवं व्यवधान) आपने हाउस के पांच सात मिनट खराब कर दिए हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद) : स्पीकर साहब, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी भी हाउस का एक मिनट का भी समय बर्बाद नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपने 5-7 मिनट खराब कर लिए। मैं तो उसी दिन आपको बुलवाना चाहता था चाहे आप उस दिन एक घण्टा बोलते। चलो अब आप बोलिये।

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 2004-05 का जो बजट हाउस में पेश किया उसमें बड़े हौंसले से यह बात लिखी कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया और बजट को 439 करोड़ रुपये के घाटे के साथ पेश कर दिया। वित्त मंत्री जी ने अपना यह 5वां बजट पेश किया है। इससे पहले भी 4 बजट जो पेश किये क्या उनमें कभी हाउस के अन्दर कोई टैक्स लगाया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पिछले 4 साल के दौरान हरियाणा की जनता पर टैक्स नहीं लगे। कमाल की बात है, यह जो वैट प्रणाली लागू की गई क्या इससे जनता पर टैक्स नहीं लगा था इसको आप टैक्स नहीं मानते। वाटर चार्जिज, सीवरेज चार्जिज, इलैक्ट्रीसिटी चार्जिज, बसों का किराया आदि जो बढ़ाया गया है क्या उससे जनता पर टैक्स नहीं लगा। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : यह तो हमने लोगों को सर्विसिज दी हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : नो नो दिस इज आलसो टैक्सिज। (विघ्न)

श्री राम कुमार नगूरा : ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर। स्पीकर साहब, जब यह वित्त मंत्री होता था तो उस वक्त बजट लीक हुआ करता था। या तो यह जीभ काढ़ कर बात कर ले या बजट पर कोई ठीक बात कह लें। इसके बारे में मेरी बुआ मुझे सारी बातें बताया करती है।

श्री मांगे राम गुप्ता : कटवाल साहब, रिश्तेदारी की तो कुछ लिहाज कर लो। तेरी बुआ फिर तेरे कान खींचेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले 4 साल के बारे में वित्त मंत्री जी ने यह ढिंढोरा पीटा है कि हमने जनता पर कोई बजट में टैक्स नहीं लगाये। ये कहते हैं कि हमने साहस जुटा कर बहुत साधन जुटाए हैं और आज खजाना लबालब भरा हुआ है और 44 हजार काम कर दिए जो एक रिकॉर्ड है। हमने इतने काम किए हैं कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले 4 प्लॉन पेश किए, इन्होंने बड़ा जोर मारा और फर्जी आंकड़े तैयार करके हाउस में रख दिए। प्राप्तियों के इन्होंने दो-दो हजार करोड़ रुपये के आंकड़े फालतू दिए। (विघ्न) आपने बहुत कोशिश की कि आप दो हजार का आंकड़ा पार कर जाएं। (विघ्न) पहले 2100 का प्लॉन बनाया फिर पौने 2200 का बनाया। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मांगे राम गुप्ता जी ने कहा है कि 2-2 हजार करोड़ के आंकड़े फालतू दिखा रखे हैं, मैं इनकी इस बात का जवाब तो बाद में दूंगा लेकिन ये यह जरूर बता दें कि किस-किस चीज में आंकड़े फालतू हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप स्पैसिफिकली और ईयरवाईज बताएं कि कहां-कहां पर आंकड़े बढ़ा कर दिखाए गए हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राप्ति के बारे में कह रहा हूँ। आपने मुझे पांच मिनट का समय अपनी बात कहने के लिए दिया है अगर आप मुझे मेरी मर्जी से बोलने की छूट दें तो मैं सारी बात बताऊंगा। यह किताबों का जो पोथा आप देते हैं यह पांच मिनट में पढ़ कर नहीं सुनाया जा सकता है। बजट तैयार करने में सरकार को छः महीने का समय लगता है बजट वैसे थोड़े ही बन जाता है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : छः महीने तो इनको लगते हैं आपको तो 15 दिन ही लगते थे। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमने देख लिया इन्होंने जोर लगा लिया 2100, 2200 और फिर 2300 करोड़ का बजट बना लेकिन आप 1700 साढ़े 1700 सौ करोड़ से फालतू पैसा खर्च करने के लिए साधनों से जुटा नहीं सके और अगर प्लॉन में ऐसा किया है तो मुझे बताइये। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने सारे प्लॉन में गलत आंकड़े देकर पास करवाने की कोशिश की है और गलत आंकड़े हाउस में दिये हैं इस तरह से ये हाउस को गुमराह क्यों कर रहे हैं ? (विघ्न) वित्त मंत्री जी, जो मैंने बात कही है आप इसका जवाब दे देना। अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में वित्त मंत्री जी रिसोर्सिज का जिक्र कर रहे हैं और उसमें 38.87 करोड़ रुपये स्टेट का खर्च चलाने के लिये कर्जा लेते हैं। कर्जा छिपाने के लिए जो कर्जा लिया रिसोर्सिज के लिए कर्जा चुकाने का वह क्या होगा, ये जो रिसोर्सिज में दिखा रहे हैं इनकी जो प्राप्तियां हैं 38.87 हजार करोड़ रुपये कर्ज़ा ले कर वर्ष 2004-05 में खर्च करेंगे। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, 29.58 करोड़ रुपये की तो किश्त देंगे और 14.66 करोड़ रुपये उस पर ब्याज देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 44.24 करोड़ रुपये का तो कर्जा चुकाएंगे जो ये प्लॉन में खर्चा दिखा रहे हैं। इस प्लॉन में 44.24 करोड़ रुपये इन्होंने कर्जा वापिस कर दिया और इनके पास 55% रिसोर्सिज बकाया रह गए। वित्त मंत्री महोदय, आप कृपया यह देखना कि इतने कम बजट में विकास के क्या कार्य होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश को एक कृषि प्रधान प्रदेश कहते हैं। वित्त मंत्री महोदय, आप जरा देखना कि आपने सिंचाई पर पिछले साल कितना खर्च किया था क्या इस साल

[श्री मांगे राम गुप्ता]

उस खर्च से आपने कुछ कम खर्च नहीं किया है और इसके साथ ही कृषि के अदायरों में और कृषि पर आपने पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम पैसा अलॉट किया है और इतने कम पैसे से आप किसान का क्या भला करेंगे। किसान के लिए सिंचाई जरूरी है और उसके बारे में आप यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं और उसमें कितने कम पैसे की अलॉटमैंट आपने की है। आप कृषि और सिंचाई के लिए पूरा पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं यही कारण है कि आपके प्रदेश में अन्न का उत्पादन कम हो रहा है। (विघ्न) मैं किसी के घर की बात नहीं कर रहा हूँ प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल जी ने प्रदेश में शराब बन्दी की थी और उससे स्टेट को 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था लेकिन वह कॉज अच्छा था इसलिए हरियाणा के लोगों ने उसको बर्दाश्त किया था। हरियाणा की जनता चिल्लाई, हरियाणा का विरोधी पक्ष चिल्लाया लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दो सालों में हरियाणा का भट्ठा ही बिठा दिया और शराब भी बन्द नहीं हुई। (विघ्न) इसी तरह से मौजूदा सरकार ने वेट टैक्स लागू किया। सारे हिन्दुस्तान के सभी राज्यों की केन्द्र सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ था कि टैक्स के सिस्टम को बदला जाएगा और यह भी बात आई थी कि सारे हिन्दुस्तान में एक ही समय में यह लागू हो। लेकिन वही शराब बंदी वाली बात की तरह मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिद पकड़ रखी थी, अपने नम्बर बनाने की चिन्ता थी, इन्होंने अपनी जिद में स्टेट में वैट प्रणाली लागू कर दी। जिस प्रकार एक ही स्टेट में शराब बंदी लागू नहीं हो सकती, उसी तरह से वैट प्रणाली भी एक ही स्टेट में कामयाब नहीं हो सकती जबकि बाकी स्टेट्स भी उसको लागू न करें। लेकिन इन्होंने अपनी जिद की वजह से वह हरियाणा में लागू कर दी, इन्होंने अपनी जिद तो पूरी कर दी लेकिन उससे लाभ क्या हुआ है ? उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये पूरी तरह से स्टडी करें तो धान के बेचने में इनको 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब तक दूसरे प्रदेशों में बराबर का वैट टैक्स न हो तब तक इसका कोई लाभ नहीं हो सकता है। (विघ्न) मुख्यमंत्री जी इस बारे में जायजा लेने के लिए गए थे, तो उनका क्या हाल हुआ था। किसानों ने काले झण्डे दिखाए थे और न ही इस बारे थैलियां दी गई थीं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश में एक साथ वैट लागू होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक प्रणाली तभी कामयाब होती है जब पूरे देश में वह एक साथ लागू हो। मेरी मुख्यमंत्री जी को यह सलाह है कि अगर वे प्रदेश में किसान वर्ग का और व्यापारी वर्ग का फायदा चाहते हैं तो ये वैट टैक्स प्रणाली को विदड्रा कर लें। अगर नहीं विदड्रा करते हैं तो जिस तरह से बंसी लाल जी को सरकार भी छोड़नी पड़ी और शराब भी बंद नहीं हुई, वही हालत आपकी न हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आपके 10 मिनट होने वाले हैं। (विघ्न) जगजीत सिंह जी, आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं। आपको तो बोलने का समय दिया जा चुका है। गुप्ता जी, आप प्वायंट पर ही बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उद्योग की बात करना चाहता हूँ कि उद्योग लगाने के लिए बहुत इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। इसके अलावा सबसे पहले जो जरूरत होती है तो वह प्रदेश में अमन और सुख-चैन की होती है ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लग सकें। व्यापारी तो पैसा हरियाणा में लगाने के लिए तैयार हैं अगर यह सरकार उसको प्रदेश में जान-माल की सुरक्षा देने का वायदा करे। आज उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा से रोज इन्डस्ट्रीज भाग रही हैं, व्यापारी इन्डस्ट्रीज बंद करके हरियाणा से जा रहे हैं। अब यह सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम हरियाणा में इतने उद्योग लगा रहे

हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में कौन सी चीज में महंगाई कम हुई है, इस बारे में भी ये बता दें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप दो मिनट में वाईड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आज इनके राज में यूरिया के खाद का कट्टा सवा सौ रुपये से बढ़कर 250 रुपये हो गया है (विघ्न) गरीब आदमी के लेने की या खाने की कोई भी चीज हो जैसे चाहे घी हो, गुड़ हो, शक्कर हो, चाय हो, लोहा हो, या सीमेंट हो यानी सभी चीजों के दाम बढ़े हैं और मंहगाई ने गरीब आदमी को मार दिया है। इसी तरह से इनके राज में बेरोजगारी बढ़ी है और आज नौजवान के पास लूट खसोट के सिवाए कोई धंधा नहीं है। आज चोरी डकैती इसलिए बढ़ रही है क्योंकि नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था न हो, बेरोजगारी हो और प्रदेश में मंहगाई बढ़ रही हो, कर्जा बढ़ रहा हो तो यह बड़ी चिन्ता की बात है। मुझे तो इसके लिए शर्म आ रही है। साधन हैं नहीं तो आप क्या करोगे ? किस बात पर आप खुशी मना रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1966 से लेकर 1997 तक जब हम सरकार छोड़कर गये थे, आठ हजार करोड़ रुपये का प्रदेश पर कर्जा था लेकिन आज वह इनके पांच सालों के राज के दौरान 38 हजार करोड़ रुपये हो गया है। कर्जा ले कर्जा लेकिन इनकी आमदनी तो है नहीं जबकि खर्चा इनका बढ़ रहा है। अगर आज 38 हजार करोड़ रुपये का कर्जा न हो गया हो तो ये हमें बता दें। जो बैंक गारंटी है या जो लोन देना है क्या वह सब इनकी देनदारी नहीं है वह कौन देगा ?

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठें।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, तरीके से समाप्त करने के लिए आप उन्हें कम से कम पांच मिनट तो और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, आप दो मिनट में वाईड अप करें। (विघ्न)

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ। वित्त मंत्री जी ने घाटे का बजट पेश किया है और इन्होंने अनुमान दे दिया कि अगले साल में इसको पूरा करने का प्रयास ये करेंगे ताकि यह घाटा पूरा हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार सालों में इन्होंने अपने बजट का घाटा पूरा किया है ? इस तरह से ये कब तक घाटा चलाएंगे ? इनकी कोई भी योजना पूरी क्यों नहीं हो रही है क्योंकि इनके पास साधन ही नहीं हैं। जब साधन होंगे तभी योजनाएं पूरी होंगी। 2100 करोड़ रुपये के बजट में भी आप योजना नहीं बना सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नाकामियां इन्हीं बातों में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी, आपको बोलने के लिए समय इसलिए दिया गया था ताकि आप कोई नयी चीज बताएंगे, रिपीटिशन नहीं करेंगे लेकिन आप तो कोई नयी बात नहीं बता रहे हैं बल्कि आप तो रिपीट कर रहे हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, नयी चीज आप बताएं कि क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, जो बात आप कह रहे हैं वह तो लगभग सभी सम्मानित सदस्य कह चुके हैं इसलिए अगर कोई अलग बात हो तो आप उसको बताएं।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अलग बात यह है कि वैट टैक्स खत्म करना चाहिए क्या आप खत्म कर दोगे ?

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। गुप्ता जी, सुझाव दे रहे हैं ताकि मैं अपना जवाब देते वक्त उन पर गौर कर सकूं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वैट टैक्स क्या है और इसके लागू होने के बाद इससे क्या फर्क पड़ा है क्योंकि ये वाणिज्य परिवार से हैं और काफी लम्बे समय तक वित्त मंत्री भी रहे हैं इसलिए मैं इनसे यह जानना चाहूँगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : वैट टैक्स यह था कि (विघ्न)

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि अभी हमारी बहन सरिता नारायण मुझे यह बताकर गयी हैं कि जो जीभ निकालने वाला आदमी होता है वह बहुत खतरनाक होता है।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई प्रणाली लागू नहीं की है जिसमें कोई वैट हो। वह तो वैट सिस्टम लागू किया है लेकिन ये वैट की बात कर रहे हैं। यह वैट सिस्टम अलग है तो यह हमें बता दें।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो वैट टैक्स है इसका तरीका यह था कि एक दुकानदार जो बाहर से किसी स्टेट से परचेज करके जाएगा और उस पर वे टैक्स लगा देंगे और वह हरियाणा स्टेट में जाकर बेचेगा और उस पर जितना प्रोफिट लेगा वह वैल्यू ऐड करके वह टैक्स लगाकर इन्होंने अपनी स्टेट में लागू कर दिया और वह दूसरी स्टेट्स में लागू नहीं हुआ। दूसरी स्टेट्स में पूरा टैक्स लगकर माल आ रहा है यह कंज्यूमर के ऊपर बड़ी जबरदस्ती की है, बड़ा जुल्म किया है।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अरोड़ा साहब ऐक्सपोर्ट के बारे में कह रहे हैं। आज जो जीरी के ऐक्सपोर्टर हैं, उन्होंने सरकार से बार-बार रिक्वैस्ट की। बार-बार इनसे मिलने डैपुटेशन आए कि इस वैट टैक्स में हमें बड़ी प्रौब्लम आ रही है दुकानदार जो कच्चा आढ़ती है जो किसान की जीरी बेचता है। डीलर वैट लगाए बगैर जीरी नहीं देता। वह तब तक जीरी सेल नहीं करता जब तक कि 4 परसेंट वैट टैक्स न लगा दिया गया हो जबकि हिमाचल और पंजाब जैसे पड़ोसी प्रदेश में 4 परसेंट वैट टैक्स नहीं लगता। इस बात पर उपाध्यक्ष महोदय हमारा और आपका चैलैंज है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है हरियाणा के किसान को बासमती का क्या भाव मिला है यह वैट का नतीजा है।

कृषि मंत्री (सरदार जलविंद्र सिंह संधू) : उपाध्यक्ष महोदय, देवीगढ़ (पंजाब) की जीरी पेहवा में आकर बिकती है।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हाउस में अपनी बात कह रहा हूँ कि

ऐक्सपोर्ट ने बहुत प्रयास किए लेकिन रजामंदी नहीं हो सकी और उनको टैक्स की एग्जैम्पशन नहीं मिली उन पर चार परसैंट वैट टैक्स लगाया है। कच्चा आढ़ती जो है वह रिस्क क्यों ले उसे सरकार पर विश्वास नहीं है। ऐक्सपोर्टर्ज कह रहे थे कि दुकानदारों ने यह कहा कि इस सरकार पर विश्वास नहीं है हम चार परसैंट का टैक्स अपने घर से क्यों देंगे इसलिए सबने चार परसैंट टैक्स लगाकर बेचा जिससे किसान की जीरी 100 रुपये प्रति क्विंटल कम पर बिकी।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठिए। अब वित्तमंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी, जवाब देंगे।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 12 फरवरी, 2004 को वर्ष 2004-05 के बजट अनुमान इस सदन में प्रस्तुत किए और इस पर माननीय सदस्यों से मुझे बहुत उम्मीद थी कि चर्चा करेंगे और चर्चा में बहुत अच्छे सुझाव भी आएंगे। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिए भी हैं, कुछ ने सराहा भी है और कुछ ने राजनीतिक तौर पर आलोचना करनी थी इसलिए आलोचना की है। बहुत अच्छा होता कि सभी सदस्यों के अच्छे सुझाव आते तो मुझे बहुत खुशी होती और विशेष तौर पर मांगे राम गुप्ता जी मेरे से बहुत सीनियर रहे हैं और मेरे से पहले 5 वर्ष तक वित मंत्री रहे हैं। मैं काफी कोशिश करता हूँ इनके समय की बजट स्पीचेज निकालकर कि कहीं न कहीं मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी व स्वयं मैं इस बात का दावा नहीं करते कि हम कोई अर्थशास्त्री हैं, हम कोई स्पैशलिस्ट हैं। हां, इतना दावा जरूर करते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान आपकी मेहरबानी से और चौधरी देवीलाल जी के विश्वविद्यालय से सीखा है और उस व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर आज सरकार मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं और वित्त विभाग का प्रबन्धन मैं देख रहा हूँ और उस व्यवहारिक ज्ञान के कारण मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज जो वित्तीय स्थिति हरियाणा प्रदेश की है, यह मैं नहीं कहता कि सब से अच्छी है लेकिन that is at number one in India यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह प्लानिंग कमीशन कह रहा है और फाईनैंस कमीशन कह रहा है। मैं खुद कहता तो कहते कि अपने मुंह से बड़ाई कर ली। उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि आपके वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति सबसे बढ़िया है। डिप्टी स्पीकर सर, यह बजट अनुमान तैयार करने से पहले आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितना दिमाग पर बोझ रहा होगा क्योंकि जो फाउंडेशन आपको मिलता है उसी पर ही आप अपना घर बनाते हैं, वह चाहे सरकार हो चाहे कोई संस्था हो। आपको एक बार चार्ज प्रबन्धन जो मिलता है उससे पहले क्या व्यवस्था थी। यह सरकार बनने से पहले क्या स्थिति थी और वित्तीय व्यवस्था की क्या स्थिति थी, यह आपके सामने है जो मूलभूत संरचना थी और प्रदेश का इन्फ्रास्ट्रक्चर था सारे हरियाणा प्रदेश का, वह आलमोस्ट समाप्त हो गया था। रोड्स की कंडीशन चौधरी भजनलाल जी हमारे सामने बैठे हैं वे बता देंगे कि जब इस सरकार ने सत्ता सम्भाली थी उस समय क्या थी, नहरों की स्थिति क्या थी ? डिप्टी स्पीकर सर, बिजली की स्थिति उस समय क्या थी, ट्रांसपोर्ट और रोडवेज की स्थिति क्या थी, उस समय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी और न ही उनके लिए कमरे थे और न ही उन कमरों के फर्श थे उनकी पोजीशन क्या थी ? (विघ्न)

चौ० भजनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर। वित्त मंत्री महोदय, यह भी बता दें कि जब हमारी सरकार थी उस वक्त उत्पादन क्या था और आज उत्पादन कितना है और उस समय खर्चा कितना था और आज खर्चा कितना है ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बीच में इन्टरप्शन न करे जो भी सदस्य बिना इजाजत बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विघ्न)

Prof. Sampat Singh : I will respond.

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य बीच में इन्टरप्शन न करे सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा चुका है जो भी सदस्य बिना इजाजत बोल रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये। (विघ्न)

Prof. Sampat Singh : They have spoken like anything. मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे बीच में इन्टरप्ट न करें अगर फिर भी करते हैं तो करें। मैं यह कह रहा था कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, कौन से विभाग को कहूँ। इस देश में सबसे ज्यादा जो कन्ट्रीब्यूशन है वह है किसानों की। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कोई सदस्य रनिंग कोमैन्ट्री न करे।

प्रो० सम्पत सिंह : इस देश में सबसे ज्यादा जो कन्ट्रीब्यूशन है वह है किसानों का, मजदूरों का, सबसे ज्यादा अगर आज किसी को जरूरत है तो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जरूरत है। उन लोगों की उस वक्त क्या पोजीशन थी ? चाहे वे ओल्ड ऐज हों, चाहे वे हैंडीकैप हों, चाहे वे बिलो पावर्टी लाईन के लोग हों, चाहे वे विडोज हों उनकी पोजीशन क्या थी। डिप्टी स्पीकर सर, इसी तरह से यूथ जो नौजवान हैं उनकी हालत उस समय क्या थी ? चौधरी भजन लाल जी और हुड्डा साहब जानते हैं कि वैल आरगेनाइज्ड और वैल प्लान्ड वे में इन यूथ को एक्सप्लायट किया जाता था और किस बात के लिए किया जाता था चन्द एक लोगों की जेबें भरने के लिए शराब माफिया सारे हरियाणा प्रदेश में छाया हुआ था। (विघ्न) At the helm of affairs जो लोगों के थे वे कमा रहे थे at the cost of youngsters. उन यंगस्टर्ज के भविष्य के ऊपर कमा रहे थे। (विघ्न)

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, फौजी साहब, आप भले आदमी हो आप इनके चक्कर में क्यों आ रहे हो।

Prof. Sampat Singh : I have not named anybody. मैं कह रहा हूँ कि यह हालात थे उन लोगों के उनको ऐक्सप्लॉयट किया जाता था जबकि यूथ को इनकरेज करना चाहिये उनका उत्साह बढ़ाना चाहिये। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर सर, इस तरह की पोजीशन उस समय थी। अगर वही स्थिति ज्यों की त्यों रह जाती तो पता नहीं यह प्रदेश किस दिशा में जाता। जैसे कई बार कहते हैं कि जो परमात्मा करता है वह ठीक करता है, अगर कोई कानून की नजरों से बच जाता है तो परमात्मा की नजरों से नहीं बचता और ऐसा ही हुआ। परमात्मा की नजर से ये लोग नहीं बचे और इनकी सरकार चली गई। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार के समय में डेढ़ लाख से ऊपर बच्चों पर केसिज बने हुए थे, इनके जाने के बाद स्थिति में सुधार आया है, पूरी तरह सुधार आने में समय लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि उस समय परमात्मा ऐसा नहीं करता तो पता नहीं कहां हम जाते और कहां हमारी सोसायटी जाती ? उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में बच्चों का ही मिसयूज नहीं हो रहा था बल्कि महिलाओं का भी मिसयूज हो रहा था। उस समय बॉर्डर के एरियाज में बच्चों को औरतों को शराब के बस्ते पकड़ा दिए जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 200 या 250 रुपये घर बैठे किसी को मिल जायें और वह लालच में आ जाये, लालच में आकर गैर कानूनी काम करे और वह गैर कानूनी काम चला रहे थे ये लोग। यदि और लम्बा चल जाता तो पता नहीं हमारे प्रदेश का क्या होता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय. . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राम किशन जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। वित्त मंत्री जी हमारी तरफ से जो कहा गया है उसका जवाब दें। आधे घंटे के करीब तो इन्होंने शराब पर ही लगा दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आधा घंटा हो गया क्या ?

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट तो हो गये हैं और 15 मिनट से ये शराब पर ही बोल रहे हैं जोकि इररैलेवैंट बातें हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह से लोगों को गुमराह करके गैर कानूनी काम करवा रहे थे यदि उसी तरह वह काम चलता रहता तो अनैतिकता और बढ़ने में देरी नहीं होती। अगर हम अनैतिकता की तरफ बढ़ जाते तो यह सारी की सारी सोसायटी खत्म हो जाती। इन हालातों में हमारी सरकार ने सत्ता संभाली और उसके बाद जिस किस्म के हालात हरियाणा प्रदेश के बने हैं विशेषतौर पर आर्थिक विकास के, वे सबके सामने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विपक्ष के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ये बैठे रहें और मेरा जवाब सुनते रहें। सबको जवाब मिलेगा यदि किसी को जवाब नहीं मिले मेरे से स्लिप हो जाये तो मुझे बता दें मैं सबको जवाब दूंगा। अब चौधरी भजन लाल जी की बात पर आता हूँ।

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। * * *

श्री उपाध्यक्ष : राम किशन जी जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। राम किशन जी, प्लीज आप बैठें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। वित्त मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं और सदन में न तो स्पीकर साहब उपस्थित हैं और न ही मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : उपाध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ आर्डर पर प्वायंट ऑफ आर्डर थोड़ी होता है।

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर साहब, क्या आप चेयर से संतुष्ट नहीं हैं। प्लीज आप बैठिये। यह कोई तरीका नहीं है। आप हर बात पर खड़े हो जाते हैं। प्लीज आप बैठें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, हम कोई बात कहें तो आप खड़े हो जाते हैं।

श्री बांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डॉक्टर साहब, क्या आप डिप्टी स्पीकर से संतुष्ट नहीं हैं।

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री बीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथी जो

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

यह माहौल पैदा करना चाहते हैं इस बारे मेरी आपके माध्यम से इनसे गुजारिश है कि विपक्ष के कहने पर अध्यक्ष महोदय ने मांगेराम गुप्ता जी को बोलने का समय दिया। अब वितमंत्री जी जवाब दे रहे हैं ये ध्यान से सुनें। चौधरी भजन लाल जी, गुप्ता जी और डॉक्टर साहब सब सीनियर मैंबर हैं और दो बार अपनी बातें कह चुके हैं वित्तमंत्री जी जवाब दे रहे हैं पता नहीं क्यों इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये मेहरबानी करके सुनने का कष्ट करें।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दुबारा बजट स्पीच का जवाब शुरू कर रहा हूँ। (विघ्न) मैं यह कह सकता हूँ कि यह बजट एक संतुलित बजट है, हर क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विशेष करके बिजली, पानी और सड़कों की जो मूलभूत संरचना होती है उसको पूरा करता है यानि इन चीजों का विशेषकर ध्यान इसमें दिया गया है। औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्रों के बारे में भी इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है इसलिए मैं इस बजट को चहुंमुखी बजट कहता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहब, आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए क्या-क्या मापदण्ड होने चाहिएं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इब्राहिम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र में सरकार का मतलब है कि Government of the people, for the people and by the people. यही बात चौधरी देवी लाल जी कहा करते कि राजनीति जन सेवा का एक माध्यम है जो कि कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। सरकार की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सब का एक उद्देश्य होता है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं सरकार कितनी जुटा पाती है। मैं कुछ इन्डीकेटर आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला इन्डीकेटर होता है कि प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी है, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कितनी है और इसी तरह से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कितनी है, प्रति व्यक्ति दूध कितना उपलब्ध है, प्रति व्यक्ति फल और सब्जी कितनी उपलब्ध है, साक्षरता की दर क्या है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्या है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च क्या है, प्रति व्यक्ति भवनों की उपलब्धता क्या है, ला एण्ड आर्डर, राजनैतिक स्थिरता और यूथ एण्ड फैस्टिवल एक्स्ट्रा आदि सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही मापदण्ड निर्धारित किए जाते हैं। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास इनकी हर बात का जवाब है। मैंने जो मापदण्ड अभी आपके सामने रखे हैं उनका मैं पहले थोड़ा सा जवाब देना उचित समझता हूँ। सबसे पहले मैं राजनैतिक स्थिरता की बात करना चाहता हूँ। कोई भी देश या प्रदेश हो उसकी इकोनोमिक स्थिति उसकी राजनैतिक स्थिरता पर बहुत निर्भर करती है। अगर आपके यहां पर आना-जाना चलता रहे यानि आया राम गया राम चलता रहे तो उस देश या प्रदेश की आर्थिक स्थिति कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती और अगर राजनैतिक स्थिरता न रहे तो उस प्रदेश की इकोनोमिक स्थिति बैठ जाती है। हमारे यहां सबसे बड़ी उपलब्धता तो यह रही है हरियाणा सरकार में राजनैतिक स्थिरता रही है जिस वजह से निष्कण्ट सरकार जो है यानि आपको यह सरकार जो वर्ष 2000 में बनी थी तब से लेकर आज तक कोई भी आदमी प्रदेश की राजनैतिक स्थिरता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हालांकि हमारे सहयोगी साथी भी रहे हैं, जहां उनका योगदान राजनैतिक स्थिरता के बारे में रहा, वह अलग बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस हाउस के अन्दर 12 फरवरी को मैंने बजट पेश किया था और इस बारे में 14 फरवरी को बिजनैस स्टैण्डर्ड न्यूज पेपर में बजट के बारे में छपा है। (विघ्न) यह कोई इस अखबार की खबर नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से इस अखबार में जो छपा है उसके दो-चार पैराज आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ कि राजनैतिक स्थिरता क्या होती है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यह इस अखबार की खबर नहीं है बल्कि

किसी का राईट अप है। (विघ्न) आप सभी साथी बैठिये। मैं हरेक माननीय सदस्य की बात का जवाब दूंगा। स्पीकर सर, इस अखबार में लिखा है :--

"When Om Parkash Chautala became Chief Minister in 2000, he inherited a huge Bansi Lal legacy in the liquor mafia. Remember the days when, during Bansi Lal's Chief Ministership, prohibition was declared in Haryana. When Bansi Lal saw the way the law was being subverted--through smuggling of alcohol, evasion of excise, etc. — he lifted the prohibition. But what he was unable to desmantle was the liquor mafia.

Margins in the sale of alcohol in Haryana are huge and the network that used to function underground had now come overground. Everyone powerful had something to do with the liquor mafia. During Bansi Lal's days the government registered cases against a number of prominent politicians including relatives of leading BJP politicians -- Krishan Pal Gujar, for one. The government's case was that buses owned by Gujar were used to transport alcohol illegally. Gujar's argument was that it was a false, trumped up case.

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, आप का प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है ?

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि वित्त मन्त्री महोदय जिस प्रकार से अखबार पढ़ रहे हैं क्या वे इस प्रकार से हाउस में अखबार पढ़ सकते हैं ? यह बात ठीक है कि वे कोई रैफरैंस दे सकते हैं और अखबार का हवाला दे सकते हैं लेकिन अखबार में जो लिखा है उसका पूरा पेज ये पढ़ रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, ये लिक्कर पर पहले ही बोल चुके हैं और इन्होंने स्टार्ट भी वहीं से किया था और अब फिर इन्होंने उसी बात को शुरू कर दिया। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपने अपनी बात कह ली है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) जब आपका मौका था तब आप खूब बोल लिए अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी को याद करवाना चाहूंगा कि इन्होंने इस सदन के अन्दर 50 मिनट का समय जाया किया था और अखबार का पूरा का पूरा पेज पढ़ा था। इन्होंने टोटल पेपर पढ़ा था और उसमें एक भी शब्द इनकी अपनी जानकारी का नहीं था। इन्होंने टोटल अखबार की बात पढ़ी थी और वित्त मन्त्री जी तो केवल रैफरैंस दे रहे हैं इसलिए इनको सुनना चाहिए।

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरे का पूरा अखबार नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, आपको सुनना चाहिए और अगर आप लोग इंट्रप्ट करेंगे तो इससे सदन का समय खराब होगा। ये रैफरैंस दे रहे हैं और अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं इसलिए आपकी और मेरी समझ की बात नहीं है। अंग्रेजी आपके और मेरे बस की बात नहीं है इसलिए आप इस झमेले में क्यों पड़ते हैं ?

चौ० भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, अब आप बैठें। आपने अपनी बात रख दी है (विघ्न) आप अब बैठ जाएं।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अखबार के अन्दर छपी खबर, छपा हुआ कोई लेख या पब्लिक ओपीनियन का जिक्र हाउस में क्यों नहीं कर सकते हैं (विघ्न) ये लोग खुद भी ऐसा करते रहे हैं और आज भी अखबार का जिक्र किया गया था और उस वक्त मैंने कहा था कि उसका बाद में मैं जवाब दूंगा।

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी, इस वक्त कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है, इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

वाक-आउट

चौ० जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बार-बार अनुरोध करने पर भी आप मुझे प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं इसके विरोध में हाउस से वाक-आउट करता हूँ। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश बरवाला सदन से वाक-आउट कर गए)

वर्ष 2004-05 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : प्रो० साहब, आप कॉन्टीन्यू करें। (विघ्न)

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Deputy Speaker Sir, I again read out the next para of this article—

"The Lok Sabha election will also be a test of Chautala's stewardship of his party which has performed spectacularly (considering its size) in the Rajasthan Assembly elections. The INLD fielded candidates in 40 assembly seats in Rajasthan. Although it won just four seats, for a first time performance, it was not bad at all. This has given rise to speculation that if INLD performs well in the Lok Sabha, Chautala could emerge as yet another power-broker in a hung Lok Sabha.

In a State where transfers and postings used to be an industry and could make and unmake ministers, Chautala rule with an iron hand and -- yes, he is not afraid to say it - Fear. He has the smallest Cabinet in the country..."

It says that he is doing just like Sardar Patel.

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इनका यह क्या तरीका है (विघ्न एवं शोर)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। अभी मांगे राम गुप्ता जी ने क्या कहा। मांगे राम जी ने सारी बातें कही और वित्त मन्त्री जी उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने यूं ही अखबार से पढ़ कर रिप्लाई देना है तो हम वह सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। (विघ्न एवं शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : इसका मतलब यह है कि आप लोग वाक-आउट करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप वाक-आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं (विघ्न एवं शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, **** **** **** (विघ्न एवं शोर)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, **** **** **** (विघ्न एवं शोर)

आई०जी० (रिटायर्ड) शेर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, **** **** **** (विघ्न एवं शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, **** **** **** (विघ्न एवं शोर)

श्री उपाध्यक्ष : चेयर की परमिशन के बिना जो भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारा दिन इनकी पूरी बातें सुनी हैं और मैं इनकी बातों का अब जवाब दे रहा हूँ तो इन्हें आराम से बैठकर सुनना चाहिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री उपाध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) कोई भी रैफरैंस दिया जा सकता है (विघ्न एवं शोर) इसमें ऐसी कोई बात नहीं है इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

चौ० भजन लाल : डिप्टी स्पीकर सर, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम वाकआउट करेंगे। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : भजन लाल जी, आपने खुद ही विशेषतौर पर यह कहा था कि आप हाउस छोड़ कर नहीं जाएंगे लेकिन आप भी वाकआउट करके जाना चाहते हैं (विघ्न एवं शोर) आप लोगों के बीच में जाकर क्या करेंगे। आप लोग न तो खुद बोल सकते हैं और न ही किसी की बात सुन सकते हैं तथा न ही लोगों की दिक्कत को प्रस्तुत कर सकते हैं। (विघ्न एवं शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वाक-आउट

श्री उपाध्यक्ष : आप डिसिप्लीन रखें। (विघ्न) आपकी पार्टी में डिसिप्लीन कहां पर है। आई.जी. साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। पहले आपकी पार्टी के जय प्रकाश जी वाकआउट करके चले गए और अब आप लोग बिना इजाजत के बोल रहे हैं। क्या आप भी वाकआउट करना चाहते हैं। (विघ्न) आपकी पार्टी में कहां पर डिसिप्लीन है, जय प्रकाश जी के बाद क्या अब आप सारे वाकआउट करना चाहते हैं। आप सदन में बैठें और जवाब सुनें। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वित्तमंत्री जी सदन में अपनी रिप्लाई के दौरान इस तरह से अखबार नहीं पढ़ सकते हैं। यदि यह ऐसा करते हैं तो हम इसके विरोध में सदन से वाकआउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वाकआउट कर गए।)

वर्ष 2004-05 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब वर्ल्ड बैंक के कर्जे की बात मैं यहां पर न करूं, उसकी सैंक्शन की बात मैं क्या यहां पर न करूं, बजट के बारे में कुछ जवाब देना है तो क्या मैं वह भी सदन में न दूं। दोनों के बारे में अगले पैरा में बात आ रही है।

"Haryana embarked on ambitious power sector reforms but the World Bank threatened to stop its Rs. 270 crore loan to the state on the grounds that it had managed to unbundled utilities but was unable to take the next step of privatising them. The State has an autonomous regulator who has recommended two tariff hikes in the last four years. Chautala is clear about power---everyone has to pay for it."

ये कहते हैं कि मुफ्त देंगे। Don't forget that these are the words of Mr. Chautala.

"Don't forget that I was blunt in refusing free power to the farm sector. We did promise this at one time, but later realised. It would not be possible", he told reporters. The power situation in Haryana has improved although Chautala accepts that it is still not good enough.

Again Mr. Deputy Speaker Sir,

"The States's finances have improved. Although Haryana presented a budget with a deficit of around Rs. 400 crore this year, the chronic overdraft panic doesn't keep the finance secretary awake in the nights any more."

हर जगह रात-रात भर फाईनांस सैक्रेटरी फिरते रहते हैं जिसकी वजह से ओवर ड्राफ्ट हो जाता है। अब ये कहते हैं कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ये सुनना नहीं चाहते हैं कि (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker Sir,

"There was a time when the police and the education department used to get salaries on the 15th of every month and municipal employees would be paid six months salaries at once. Not any more."

आजकल नहीं है, पहले था। Mr. Deputy Speaker Sir, what is bad in this.

Again Mr. Deputy Speaker Sir,

"The Government is clear that farmers are its biggest constituency and has undertaken aggressive market intervention in conditions of glut production. 90 per cent produce of farmers gets picked up by the State."

90 प्रतिशत अनाज मार्किट में जो आया था, उसको हमने उठाया है तो भी इनके पेट में दर्द होता है।

"Where earlier, private sector grain merchants used to form cartels to drive down prices."

"पहले वे लोग अपना समझौता करके प्राईस को डाउन कर देते थे। अब इस बारे में मैं नहीं कहूँगा तो कब कहूँगा। इसी प्रकार से --

> "Roads have improved–some years ago, those living in Haryana would prefer to drive through Punjab rather than take the pot–holed Haryana Roads."
>
> "But despite all this, Haryana is known never to vote the same party in twice in succession and observers say this is the biggest problem Chautala is going to face both in the Lok Sabha and in the assembly election due in a year. He has an answer for this. The Supreme Court has given a verdict in the Sutlej Yamuna Link Canal case in Haryana's favour and the only issue now is which agency will build the canal."

अब एक ही बात रह गई है कि कौन एजैन्सी बनाएगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुका है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है।

> "If Chautala can bring water to south Haryana---Rewari, Narnaul, Jind, etc. he is assured of victory."

उपाध्यक्ष महोदय, फाईनांस सिस्टम मैनेजमेंट के बारे में, एस.वाई.एल. के बारे में और सीवरेज के बारे में हम यहां पर नहीं कहेंगे तो कहां पर कहेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां पर माप-दण्ड के बारे में भी कहा गया है, राजनीतिक स्थिरता के बारे में कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूँगा कि पहले पर कैपिटा इन्कम 19,340 थी और अब यह बढ़कर 26,632 हो गई है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

यह क्या इंडीकेटर है ? सरकार के सत्ता संभालने के बाद दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो पहले 626 ग्राम थी वह अब बढ़कर 676 ग्राम हो गयी है। जब हमने सत्ता संभाली तो बिजली की खपत प्रति व्यक्ति 450 यूनिट थी जो अब बढ़कर 530 यूनिट प्रति व्यक्ति हो गयी है। उद्योग में बिजली की खपत पहले 19337 लाख यूनिट थी जो अब बढ़कर 27853 लाख यूनिट हो गयी है। इसी तरह से हरियाणा में पहले 1 लाख 74 हजार टन पैट्रोल की खपत होती थी वही अब बढ़कर 2 लाख 5 हजार टन हो गयी है। इसी तरह से डीजल की खपत जहां पहले 17 लाख 49 हजार टन थी वहीं अब बढ़कर 22 लाख टन हो गयी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि ये जो हरियाणा के बारे में बता रहे हैं तो यह तो हमने पढ़ा है। यह तो इन्होंने उस दिन भी बताया था इसलिए अब इसको बताने की क्या जरूरत है? मैंने यह कहा है कि जो हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है अब उससे तुलना करके बताएं कि हम कहां पर हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है और उनके मुकाबले हरियाणा के एक आदमी को प्रति व्यक्ति कितना दूध मिलता है ?

Prof. Sampat Singh : I will tell you about Punjab. What is financial position there ? You know better than I. इसी तरह से डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की बात है, मांगेराम जी ने सरसरी तौर पर एक सैंटेन्स को छोड़कर कुछ भी नहीं कहा है। आपका असैम्बली का रिकार्ड पड़ा है आप देख सकते हैं कि बजट के ऊपर किसी भी मैम्बर ने एक सैंटेन्स नहीं कहा है अगर कहा हो तो सरकार उनकी बात को मानेगी। एक आदमी ने भी नहीं कहा। इसका मतलब क्या है You are not concerned about law and order. Either you are satisfied या आपका इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप संतुष्ट हैं तो इसका मतलब सारी की सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है जहां तक यूथ वैलफेयर की बात है, पहले इनके हालात क्या थे यह आपको भी पता ही है। लेकिन अब इनके लिए एक स्पोर्टस पोलिसी जिसमें आपका भी बड़ा भारी योगदान है, बनाकर इनको सही रास्ते पर लाया गया है। पहले जहां यूथ क्रिमिनल था वहीं आज वह खेलों में, उत्सवों में भाग लेता है। वैसे ज्यादा तो इस बारे में मैं पॉलिसी के टाईम में बताऊंगा लेकिन अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हालांकि बाईचांस कर्णम मल्लेश्वरी हरियाणा में पैदा नहीं हुई थी वह केवल हरियाणा की रहने वाली थी लेकिन चौधरी साहब की कमिटमैन्ट थी इसलिए उन्होंने उसको 25 लाख रुपये दिए वरना हरियाणा से पैदा होने वाले ने अभी तक ओलम्पिक में रिप्रेजेन्ट नहीं किया है लेकिन अब यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है कि अब जो ओलम्पिक होने जा रहे हैं उनमें हिन्दुस्तान से केवल 6 लोग भाग लेने जाएंगे और उनमें से पहली बार तीन रेशनल्ज हरियाणा के होंगे। This is the first time in the country for sports policy. इस तरह से कितने साल देश को आजाद हुए हो गये हैं 57 साल हो गये हैं। एक भी नेशनल यूथ फेस्टिवल हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट टाईम नेशनल यूथ फेस्टिवल हरियाणा में हुआ और वह भी कैपीटल हैड क्वार्टर पर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर हुआ। इसका मतलब है कि यूथ के प्रति सरकार कितनी चिंतित है। डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं इन भाईयों ने जिन बातों का जिक्र किया है, उन सब पर आता हूँ। जी.एस.डी.पी. एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अर्थव्यवस्था के बारे में। वर्तमान मूल्यों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2001-02 में 60212 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर

65387 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें इंक्रीज है 9.3 परसैंट की। इस तरह से ये अच्छी अर्थव्यवस्था के इंडीकेटर हैं। स्थिर मूल्यों में जहां पहले यह 35 हजार 62 करोड़ रुपये था वहीं अब बढ़कर 36 हजार 86 करोड़ रुपये हो गया है इस तरह से यह वृद्धि 5.2 प्रतिशत की है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि केवल चार प्रतिशत की है। We are better than national average. इसी तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने ज्ञान के अभाव की वजह से प्राईमरी, सैकेंडरी और टरशियरी सैक्टरों के बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर का कंट्रीब्यूशन सैकेंडरी सैक्टर के मुकाबले में गिर रहा है जो कि चिंता का विषय है। इस तरह की बातें इन्होंने कही लेकिन यह चिंता का विषय नहीं है बल्कि यह गौरव का विषय है। पहले इकोनोमी में कंट्रीब्यूशन का भार अकेले कृषि पर ही था। अकेले ऐग्रीकल्चर सैक्टर पर था इसका मतलब आमदनी के साधन और कोई नहीं थे। आप सौ रुपये कमाते थे और 100 के 100 रुपये ऐग्रीकल्चर सैक्टर कमाता था आज उस बोझ को ट्रेड, इण्डस्ट्री और सर्विसेस ने शेयर किया है और जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से ऐग्रीकल्चर सैक्टर की ग्रोथ रुकी नहीं है, उत्पादन कम नहीं हुआ है। इसमें कंट्रीब्यूशन ट्रेड और इण्डस्ट्रीज का है आपका व्यापार, उद्योग बढ़ा, सर्विसेस बढ़ी और इन वजहों से कंट्रीब्यूशन बढ़ा है इस बात के लिए तो इनको गर्व महसूस करना चाहिए था। प्राथमिक क्षेत्र में कितना बढ़ा है इसमें कृषि क्षेत्र शामिल है यह 29.4 हुआ है, द्वितीयक सैक्टर में 28 प्रतिशत और तृतीयक सैक्टर में 42.6 प्रतिशत इसका मतलब यह है कि अब अकेले कृषि पर बोझ नहीं रहा। दूसरी चीजों में भी प्रगति की है। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : कृषि पर घटा है वह क्यों घटा है यह तो बताएं ?

प्रो० सम्पत सिंह : मैं वही बात कह रहा था आप यहां थे नहीं तो मैं क्या करूं। अकेले ऐग्रीकल्चर सैक्टर पर था इसका मतलब आमदनी के साधन और कोई नहीं थे। आप सौ रुपये कमाते थे और 100 के 100 रुपये ऐग्रीकल्चर सैक्टर कमाता था अब 100 रुपये जी.एस.डी. है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले 100 का 100 रुपया ऐग्रीकल्चर सैक्टर से आता था बाद में 90 हुआ, 80 हुआ, 70 हुआ, 60 हुआ। यह क्यों हुआ, यह भी बता देता हूँ यह नहीं है कि उत्पादन घटा है, उत्पादन बढ़ा है लेकिन मैं कह रहा था कि ट्रेड, इण्डस्ट्री और सर्विसेज इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है हम प्रोग्रेसिव इकोनोमी की तरफ जा रहे हैं डॉ० साहब यह आपको सोचना चाहिए। सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है that is a great achievement. और उपाध्यक्ष महोदय, वार्षिक योजना का बड़ा जिक्र किया गया 2003-04 में हमने 2100 करोड़ से घटाकर 1850 करोड़ की की थी। मांगे राम गुप्ता जी बैठे हैं कई बार अकस्मात बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो पहले नहीं सोच सकते वह खर्च पब्लिक इंट्रस्ट के खर्च हैं वह कोई फिजूलखर्ची नहीं है उसमें से योजना हर बार घटती है, मांगे राम जी के समय में भी घटी है और चौधरी बंसी लाल के समय में भी ड्रास्टिकली घटी है और हर साल घटी है मैं आंकड़े दे देता हूँ 1991-92 में रिवाज्ड एस्टीमेट 722 करोड़ था जो 701 रहा, 97 परसैंट अचीव किया। 1992-93 में 804 था 752 रहा, 93 परसैंट अचीव किया। 1993-94 में 839 था घटकर 805 रह गया और 96 परसैंट अचीव किया। 1994-95 में 1019 से घटकर 966 करोड़ किया और 94 परसैंट अचीव किया। 1995-96 में 1225 से घटकर 1116 करोड़ रहा और 91.1 परसैंट अचीव किया और चौधरी बंसी लाल के समय में 1996-97 में 1997-98 में 93 परसैंट अचीव किया गया। 1998-99 में हमने संभाला था और 84.6 अचीव किया और आज की सरकार ने पहले ही साल 93.8 किया और दूसरे साल 94.1 परसैंट अचीव किया और तीसरे साल 97.4 परसैंट अचीव किया और मांगे

[प्रो० सम्मत सिंह]

राम जी का 97.1 परसैंट हाइऐस्ट था that is the highest one in the history of Haryana for the last ten years. I am not talking about all the 30 years. उसमें और किया 2002-03 में 1816 से 1776 किया है और 97.8 परसैंट अचीव किया है जो कि और ज्यादा अचीव किया गया है। (शोर एवं व्यवधान) यह जो मैं कह रहा हूँ यह रिवाइज्ड आउटले प्लान था जो कि अचीव किया है that is a great achievement और जो बोझ अलग से आए जैसे नंबर एक पर केन्द्रीय करों में हिस्सा 38.49 करोड़ कम आया और केन्द्रीय सहायता 45.15 करोड़ रुपये कम आई यह दोनों यदि मिला देता हूँ तो 83.64 करोड़ बनता है यह कमी आई। डिप्टी स्पीकर सर, सहकारी चीनी मिलों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो गन्ना उत्पादक किसान थे उनके भुगतान के लिए 110 करोड़ रुपये शूगर मिलों को किसानों का भुगतान करने के लिए दिये गये हैं कि कभी किसानों का नुकसान न हो जाये और वे मारे न जायें। इसी तरह से एल.ए.डी.टी. का जो पैसा आता है उसका बंटवारा स्थानीय निकायों को 41 करोड़ 70 लाख रुपये किया गया है। बिजली निगमों को वन टाईम सैटलमेंट के लिए 174 करोड़ रुपये ब्याज के लिए दिया है। इसलिए इन कारणों से यह प्लान कुछ कम की गई और कम करना जरूरी हो गया था क्योंकि सरकार की कुछ मजबूरियां थीं जो खर्चा बताया गया है इसमें हमने कोई नाजायज नहीं किया। यह प्रदेश की जनता के लिए खर्च किया गया है और विशेषकर किसानों के लिए किया है। अब मैं वार्षिक योजना के लिए इस साल का ब्यौरा देना चाहूँगा। वर्ष 2004-2005 की वार्षिक योजना 2175 करोड़ रुपये रखी है जो पिछले साल के मुकाबले 17.6 प्रतिशत अधिक है इसमें मेन काम वही हैं जैसे सिंचाई, बिजली, सड़क-परिवहन इनके लिए 941 करोड़ रुपये रखे गए जो कि 43.3 प्रतिशत है। सामाजिक सेवाओं पर 919 करोड़ 87 लाख रुपये जोकि 42.3 प्रतिशत है। डिप्टी स्पीकर सर, सामाजिक सेवाओं के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं उन पर पैसा लगाने के लिए 325 करोड़ रुपये फालतू रखा है जिससे 138675 लोगों को लाभ प्राप्त होगा। दो करोड़ की जनसंख्या में इतने लोग लाभ प्राप्त करेंगे और एक समय वह था जब एच.आर.डी.एफ. का पैसा आता था और उस पैसे को ब्याज कमाने के लिए सरकार रखती थी वह पैसा काम के लिए नहीं लगता था। जबकि यह सरकार आज उस पैसे को लोगों के कामों पर लगा रही है। चौधरी बंसी लाल जी की सरकार में 1998-99 में 32 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च हुए थे और वर्तमान सरकार के समय में 679 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 200 करोड़ रुपये का प्रावधान और रखा गया है क्योंकि यह पैसा भी आगे काम आवेगा असैट्स खरीदने के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड ने 1998-99 में केवल 68 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च किए जबकि वर्तमान सरकार आने के बाद 199 करोड़, 180 करोड़, 124 करोड़, 149 करोड़ इस तरह से 716 करोड़ 62 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और इस योजना के और जोड़ दिए जायें तो 2899 करोड़ 78 लाख रुपये बन जाते हैं। जहां तक वित्तीय सुधारों की बात है। डिप्टी स्पीकर सर, इस सरकार में इतने अच्छे वित्तीय प्रबन्धन की झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। गैर-उत्पादक खर्च कम करके कर प्रणाली में सुधार करके आय के साधन जुटाये जा रहे हैं और 11वें वित्त आयोग ने केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्यक्रम बनाये हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य है जिसने वैट सिस्टम को लागू किया है इसकी परिभाषा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसी तरह से जो रेशनेलाईजेशन सरकारी विभागों में किया है कि जिस विभाग में फालतू कर्मचारी थे उनको दूसरे विभागों

में भेजा गया है। चौधरी भजनलाल जो जानते हैं कि एक समय उनकी सरकार के समय यह था कि एक दफ्तर में क्लर्क तो छः होते थे और चपड़ासी 14 होते थे खासकर मैं कान्फैड की बात कर रहा हूँ। जहां चपड़ासी 14 हों और क्लर्क 6 हों तो वे किसकी सेवा करेंगे, केवल तनख्वाह ही लेंगे। लेकिन इस सरकार ने जो भर्ती की है वे ऐसे हैं जो उनकी सेवा करेंगे। इसमें पब्लिक ऐक्सचैकर का पैसा है एक-एक आदमी की जेब से यह पैसा निकलता है सरकारी सेवा के लिए और इसके इन्ट्रस्ट के लिए निकलता है। We are committed, Sir. इसलिए उनमें बचत की है और जो बचत की है इसको ये कहते हैं कि मुलाजिमों पर खर्चा कम किया है और हम मुलाजिमों को कम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये पढ़ते तो हैं नहीं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। 2002-03 में 4202 करोड़ रुपये रखा था और इस बार 2003-04 में 4443 करोड़ रुपये रखा है। मैं मानता हूँ कि कम हुआ है लेकिन कौन सा कम किया है। राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले में कम हुआ है। एक तरफ खर्चा तो हमारा बढ़ा है लेकिन जो रैवेन्यू रिसीप्ट्स आ रही हैं उसके मुकाबले में मैं कहता हूं कि Yes हमने खर्चा घटाया है पहले यह खर्चा जो 65.88 प्रतिशत था as compare to revenue receipts वह अब घटकर 44.14 प्रतिशत हो गया है। यह बहुत बड़ी इम्प्रूवमैंट है। यह बचा हुआ पैसा किस काम आयेगा विकास के लिए काम आयेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, केवल आंकड़े पढ़कर, Budget at a Glance देखकर कह देना कि हम मुलाजिमों की छंटनी करने जा रहे हैं यह ठीक बात नहीं है। जहां तक छंटनी का सवाल है और सरकारी विभागों की जहां तक बात है पिछले साढ़े चार साल में हमारी सरकार ने एक भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की है, चाहे कोई बेलदार हो, चाहे चौकीदार हो। जहां तक बोर्डज और कॉरपोरेशंज की बात है सरकार इनको ग्रांट्स देती है, उनके लिये साधन जुटाती है लेकिन कभी कभार उनका बोझ इतना बढ़ जाता है कि जिससे पब्लिक इंट्रस्ट के काम, विकास के काम रुक जायें और केवल मात्र चंद लोगों के लिये हम अपना खजाना लुटायें यह हमारी सरकार में नहीं होगा। मैं क्लीयर आंकड़े देकर बात क्लीयर करना चाहता हूँ क्योंकि बार-बार ये लोग कहते हैं कि 50 हजार कर्मचारी छंटनी कर दिए, कभी कहते हैं 30 हजार कर्मचारी छंटनी कर दिए। आगे से ये लोग ऐसी गलत बातें न कहें अपनी ये बातें स्टौप करें, मैं आंकड़ों के हिसाब से इनको बताना चाहूँगा और वे आंकड़े इनके पास भी हैं इनको सोच समझकर बोलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एच.एस.एम.आई.टी.सी. से 2911, कान्फैड से 684, हरियाणा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से 140, एच.एस.एस.आई. से 439, अपैक्स सोसायटीज से 58, इनफैड से 36 और एच.एम.एल. से 791 टोटल कुल मिलाकर 6059 कर्मचारियों की छंटनी बोर्डज और कॉरपोरेशन से की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि मौजूदा सरकार ने पिछले चार साल में कितनी नौकरियां दी हैं। ये बेरोजगारी की बातें करते हैं, मैं मानता हूँ कि बेरोजगारी सरकारी नौकरियों से दूर नहीं की जा सकती। बेरोजगारी को दूर करने के लिये विकास के काम करने पड़ेंगे। विकास के काम करने से जब मैन पावर यूज होगी और मैन पावर यूज होने से नेजिज मिलेंगे उसके बदले काम मिलेगा वह अलग बात है। लेकिन सरकारी नौकरियों का जहां तक सवाल है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जहां पर जरूरत थी वहां भर्ती की गई है। It is on record. I admit each and everything, which we are doing.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं वित्तमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि बोर्डज और कॉरपोरेशंज से जिन लोगों को निकाला गया है क्या उनको नौकरी में लेने के लिये सरकार की तरफ से कोई प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया ?

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसका प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने जो रिक्रूटिंग एजेंसिज हैं वे जो पोस्ट एडवर्टाईज करती हैं उनमें अगर किसी कर्मचारी की क्वालीफिकेशन पूरी होगी तो उनको नौकरी दी जायेगी और 25 प्रतिशत पोस्टें उनके लिये रिजर्व भी की गई हैं। इसमें एज की कोई बार नहीं है। Age is no bar. जहां तक टोटल जौब्स की बात है जो हमारी सरकार ने टोटल जौब्स सैंक्शन की हैं including public sector और गवर्नमैंट सैक्टर में वे 71 हजार सैंक्शन की हैं। इसमें से जो पूरी हो चुकी हैं वे 29 हजार पोस्टें हैं जिन पर लोग ज्वॉयन कर चुके हैं, 34 हजार पोस्टें अंडर प्रोसैस हैं और केवल 8 हजार पैंडिंग जौब्स हैं जिनकी रिक्वीजेशन भेजी जानी है। उपाध्यक्ष महोदय, कई विभागों की रैशनेलाईजेशन अभी भी चल रही है। जो 71 हजार का आंकड़ा है यह धीरे-धीरे 90 हजार पर पहुँच जायेगा। सरकार ने छंटनी नहीं की है बल्कि जौब्स सरकार बढ़ा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के साथी चाहते हैं तो मैं सभी विभागों का पढ़कर सुना देता हूँ लेकिन फिर चौधरी भजन लाल जी कहेंगे कि पढ़ने लग गया। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने fiscal deficit की बात की है। आपको यानी किसी प्रदेश को देश की इकोनोमी के साथ डैफिसिट कम्पेयर करना पड़ता है और दूसरी स्टेट के साथ भी कम्पेयर करना पड़ता है। आपका जो प्रीवियस ईयर रहा है उसके साथ भी आपको कम्पेयर करना पड़ता है तब जा कर आपको अपनी अचीवमैंट्स का पता चलता है। डिप्टी स्पीकर साहब, 1998-99 में जो फिसकल डैफिसिट था वह 2240 करोड़ रुपये था। यह वर्ष 2002-03 में कम होकर 1471 करोड़ रुपये रह गया। कहां आपका डैफिसिट 2240 करोड़ रुपये और कहां 1471 करोड़ रुपये। इससे पता चलता है कि आपका डैफिसिट घट रहा है जबकि ये कह रहे थे कि यह बढ़ रहा है। इसी प्रकार से वर्ष 2003-04 में 1343 करोड़ रुपये रहा। (विघ्न) मैं उस पर भी आऊंगा। (विघ्न) I will come on each and everything. Just wait.

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग बैठिये। आप लोगों का बोलने का यह कोई तरीका अच्छा नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, 2003-04 में फिसकल डैफिसिट 1343.88 करोड़ था। यह भी पहले की अपेक्षा घटा है। अब दूसरा कम्पेयर करते हैं सकल घरेलू उत्पाद के साथ। वर्ष 2001-02 में 4.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2002-03 में यह भी घट कर 2.23 प्रतिशत रह गया है, यानी यह भी घटा है। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि चालू वित्त वर्ष में यह घटकर 1.83 प्रतिशत रह गया है। सर, हमें अगले साल जो राजस्व प्राप्तियां होंगी वे 10.5 प्रतिशत की दर से संभावित हैं। इसके मुकाबले में जो राजस्व में वृद्धि है वह 9.4 प्रतिशत है। यह भी अन्डर कन्ट्रोल है और इसमें भी 1.1 प्रतिशत की कमी हुई है। यह सब अच्छे वित्तीय प्रबन्धन का ही नतीजा है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, इन उपायों से हमें वर्ष 1999-2000 में सकल राजस्व घरेलू उत्पादन में जो प्राप्तियां 7.2 प्रतिशत थी जो अब बढ़ कर 8.44 प्रतिशत हो गई हैं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर साहब, * * * *

श्री उपाध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। कादियान साहब, आप बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं कर्जों की बात बताना चाहता हूँ। ये अपोजीशन के भाई कर्जों का बड़ा शोर मचा रहे थे। ये पहले सुनें तो सही। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : डिप्टी स्पीकर साहब, डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान दुबारा

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

से सदन में इस शर्त के साथ वापस आये थे कि इनका आचरण ठीक रहेगा और आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ यह है कि आज ही मैंने सवेरे एक अकस्मात सराहना कर दी। लेकिन ये फिर उसी लाईन पर आ गए। (विघ्न) आपके नेता ने यह कहा था कि आप अपना आचरण ठीक रखोगे। आप क्यों हाउस का समय खराब कर रहे हो। आप बैठें और हाउस को चलने दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : डिप्टी स्पीकर साहब, वे प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब, एक सम्मानित सदस्य बिना पूछे बार-बार उठता रहे ,यह कोई बात है। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : प्वायंट ऑफ ऑर्डर का क्या आपने ठेका ले लिया है। (विघ्न) इस हाउस में और भी मैम्बर्ज हैं। (विघ्न) इसलिये आप बैठिये, आपको पूरा मौका दिया गया है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर साहब, * * * *

श्री उपाध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। कादियान साहब, आप बैठिये। (विघ्न) कादियान साहब, आप अपनी आदत सुधारो। आप हाउस का समय बर्बाद न करो। आप बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं लीडर ऑफ दी अपोजीशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सम्मानित सदस्य को काबू किया। परम्परा तो यही रहती है कि चेयर की आज्ञा से ही कोई सदस्य काबू हो जाता है, लेकिन चलो ये नहीं मानते तो अलग बात है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठे-बैठे भी नहीं बोलेंगे। क्या आपको बोलने का समय नहीं दिया गया। आपका यह कोई तरीका है, यहां पर हाउस के 90 सदस्य और बैठे हैं। (विघ्न) आप औरों के हक को नहीं खाओगे। आपकी यह बात ठीक नहीं है। आप सब को पूरा समय मिला है। आप बार-बार बीच में इन्ट्रप्ट न करें।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, अब मैं ऋणों पर आता हूँ क्योंकि ऋणों का जिक्र किया गया है। मैं वर्ष 2002-2003 का बताऊंगा क्योंकि 2004 के ऐस्टिमेट्स हैं और 2005 के भी ऐस्टिमेट्स हैं लेकिन 2002-2003 की हमारे पास पूरे वर्ष की एक्चुअल फिगर्ज हैं इसलिए वही कम्पेयर करूंगा। वर्ष 2002-2003 में 18,187 हो गये हैं (विघ्न) और साथ में राज्य की गारन्टी का जिक्र आया। 7600 करोड़ रुपये की गारन्टी हो गई है तो डिप्टी स्पीकर साहब, इस साल का जो अनुमानित है वह 21,649 का है पिछले साल का हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बार 21,649 के जो 18,187 से पहले आया वह लगभग तीन हजार करोड़ समथिंग रुपये पहुँच जाता है। कर्जा लिया है, यह ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कर्जा लिया है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कर्जा खर्चा कहां पर गया है ? बात यह नहीं है बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है असैट्स बनाने पर खर्च किया है और एक-एक चीज में यहां बता दूंगा कि कहां-कहां पर खर्च किया गया है। इनका बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे, असैट्स आप बनाएंगे तो उसका रिटर्न भी आपको आएगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (विघ्न) मेरा प्वायंट ऑफ

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[कैप्टन अजय सिंह]

ऑर्डर यह है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट में वर्ष 2003 में स्टेट की जो गारन्टी थी वह 12,461 करोड़ रुपये थी और यह बता रहे हैं 4 हजार करोड़ रुपये, माननीय वित्त मंत्री जो यह बताने की कृपा करें कि ये यह कैसे बता रहे हैं ?

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक खर्च की बात है पहले की तरह जैसे पावर सैक्टर का है (विघ्न) पावर सैक्टर में हर सरकार सबसिडी देती रही है लेकिन डिप्टी स्पीकर सर, वह केवल बुक ऐडजस्टमैंट के रुप में देते रहे हैं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : कादियान साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) हाउस में एक आप ही हरीश चन्द्र पैदा हुए हैं। (विघ्न) मैंने कई बार आपसे यह गुजारिश कर ली है कि आप हाउस को चलने दें लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सबसिडी फारमर्ज के हित में दी जाती है और हर सरकार यथासम्भव देती रही है लेकिन इसमें फर्क यह है कि पहली सरकारें केवल बुक ऐडजस्टमैंट करती थीं और आपके बजट पर उसका असर नहीं आता था। आपकी सरकार ने 4400 करोड़ रुपये 4 साल में हार्ड कैश सबसिडी दी है that is an achievement and that is in the interest of farmers. उपाध्यक्ष महोदय, किसान के हित के लिये अगर कर्जा लेना पड़ेगा तो लेंगे, किसान को आगे बढ़ाना है। किसान के बिना अर्थ-व्यवस्था समाप्त हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पावर सैक्टर में खर्च बढ़ा है। एच.वी.पी.एन. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम उसके एन.टी.पी.सी., एन.एच.पी.सी. तथा अदर्ज का जो कर्जा बकाया है वह 222 करोड़ था गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया ने देश के सभी पावर मिनिस्टर्ज तथा सभी पावर सैक्रेटरीज़ की एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि आप बौंडज़ खरीदें और इनको आपको लोन्ज़ में डालना पड़ेगा और इसमें रियायत देंगे और सरचार्ज भी माफ करेंगे 222 हजार करोड़ रुपये की जो देनदारी थी कर्जा में बढ़ी थी यह कर्जा में इस वजह से बढ़ी क्योंकि 222 करोड़ रुपये एकमुश्त Onetime Settlement Scheme के अन्दर आपने वह पैसा दिया और लोन के खाते में डाला। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** गारन्टी में नहीं, गारन्टी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि लोन्ज़ के खाते में 222 हजार करोड़ डाला और इससे फायदा कितना हुआ है। इससे ड्यूऐल सरचार्ज का 60% माफ हुआ है यानि 100% पेमैंट करने की वजह से 649.25 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है और एक इन्सैंटिव भी मिला है जो कि throughout the country केवल हरियाणा स्टेट ही ले पाई है। यह इन्सैंटिव यह है कि आपने इनटाईम पेमैंट कर दी इसलिये पहले साल की ऐडवांस की पेमैंट मान रहे हैं कि पहले साल के अन्दर 1.1 की बाउंड वैल्यू के आपके पैसे की ऐडजस्टमैंट हो जाएगी और वह चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। 8% ऑटोमैटिकली इसी लोन में से जाएगा, अगले साल 5% जाएगा फिर 4% जाएगा फिर 4% जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसी पैसे में इसी लोन में से वह रि-पे आप कर चुके होंगे। तो स्पीकर सर, इन कामों के लिये पैसा लिया है। पब्लिक इन्ट्रस्ट के अन्दर लिया है। जहां तक गारन्टी का सवाल है तो स्पीकर सर, अगर वे सुनेंगे तो इनके भी कान खुल जाएंगे। चौधरी भजन लाल जी, मैं गारन्टी के बारे में आपको बताता हूँ कि चारों जो पावर यूटिलिटिज़ हैं उनमें 4035

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

करोड़ रुपये की गारन्टी है। यहां पर सबसे ज्यादा जनरेशन के बारे में बात कही गई है। स्पीकर सर, आप पानीपत में रहते हैं और जनरेशन के बारे में आपको ज्यादा पता है। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले 210 मैगावाट की सिक यूनिट के कम्पलीशन का काम किया है। यह काम काफी समय से लटक रहा था। इस पर 1994 में 239 करोड़ रुपये के खर्च का एस्टीमेट बनाया गया था। स्पीकर सर, अब जो हमने इसको कम्पलीट किया है तो इस पर 985 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। यह खर्च क्रिमिनल/नैगलिजेंस की वजह से हुआ है। यह हमारी वजह से नहीं हुआ है बल्कि ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं इनकी वजह से हुआ है। अब इस बारे में हम कुछ कह देंगे तो इनके दर्द होगा। स्पीकर सर, कहां तो खर्च 239 करोड़ रुपये होना था और कहां पर 900 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुआ है। मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूँगा कि इन कामों को पूरा करने के लिये लोन लेना पड़ता है। इन लोन्ज़ के अगेन्स्ट स्वभाविक है कि गारन्टी भी देनी पड़ेगी। हमें इस पर 362 करोड़ रुपये की गारन्टी देनी पड़ी है। इसी तरीके से स्पीकर सर, पिछले दिनों सैकेन्ड यूनिट का सदन में बार-बार जिक्र किया गया है। जब चौधरी बंसी लाल जी पावर में थे तो ए.बी.बी. कम्पनी को सैकेन्ड यूनिट की रिपेयर का काम 300 करोड़ रुपये में दिया गया था और इस कम्पनी को काम देने के बाद 72 करोड़ रुपये का एल.आई.सी. से लोन लिया गया था। स्पीकर सर, यह पहली बार हुआ है कि कम्पनी को ऐडवांस पेमैंट कर दी गई और वह कम्पनी बीच में ही काम छोड़कर भाग गई। स्पीकर सर, यह पैसा जर्मनी की कम्पनी से 15 प्रतिशत ब्याज की दर पर लिया गया था। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूँगा कि जब पैसा लोन पर लिया जाता है तो उसकी गारन्टी भी देनी पड़ती है। स्पीकर सर, बंसी लाल जी की सरकार के जाने के बाद जब हमारी सरकार आई तो हमने उस कम्पनी की गारन्टी जब्त करवा दी। वह कम्पनी तो भाग गई थी और यह खाता तो खत्म हो गया था। अब वह काम 35 करोड़ रुपये में हो गया है। इसके बाद 7वीं और 8वीं यूनिट का जिक्र आया है। इस पर लगभग 1785 करोड़ रुपये का खर्चा आया है। स्पीकर सर, इसके लिये हमने 1428 करोड़ रुपये का लोन सैंक्शन करवाया है। स्पीकर सर, मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि ये लोन किस बात के लिये लिए जा रहे हैं, ये लोन इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आपकी जनरेशन बढ़े। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 उत्तरी और दक्षिणी कम्पनियां हैं। एक में 278 लाख और दूसरी में 268 लाख रुपये का कर्जा लिया गया है। स्पीकर सर, अगर ये कहते हैं कि इन कामों को करने के लिये कर्जा लेना कोई बुराई हो तो उसको बुराई माना जाएगा। यह पैसा पब्लिक इन्ट्रस्ट के लिए लिया गया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैंने ट्रांसमिशन लोसिज के बारे में बात करी थी, ये उसके बारे में बताएं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि केन्द्र ने एक डैटस-वैटस की स्कीम चलाई थी और हमने उस डैटस-वैटस की स्कीम का भी फायदा उठाया है। बंसी लाल जी और भजन लाल जी की सरकार के वक्त में 14-14 प्रतिशत और 15-15 प्रतिशत पर लोन लिया गया था। स्पीकर सर, उस महंगे इन्ट्रस्ट पर लिये पैसे के बर्डन को कम करने के लिये हमने कम इन्ट्रस्ट पर 1764 करोड़ रुपये का लोन लिया है। मांगे राम गुप्ता जी, अगले साल हमने 1320 करोड़ रुपये का प्लान रखा है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जो लोन लिये जा रहे हैं ये 5.9 प्रतिशत से लेकर 10.5 प्रतिशत तक ब्याज दर से लिये जा रहे हैं। स्पीकर सर, हमने जो यह लोन लिया है इसको लेने की वजह से हमें 190 करोड़ रुपये का ब्याज नहीं देना पड़ा है। हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाया है जो कि हमें उठाना भी चाहिए था। इससे आज हरियाणा प्रदेश का सुधार हो रहा है। स्पीकर सर, 2002-03 में बजट घाटा 454.16 करोड़ रुपये हुआ था और अब

[प्रो० सम्पत सिंह]

यह 226.98 करोड़ रुपये पर समाप्त हुआ है। स्पीकर सर, 227 करोड़ रुपये का घाटा कम हुआ है। (विघ्न) स्पीकर सर, आंकड़े तो तब बताते जब हम कुछ छिपाते, हमने कुछ नहीं छिपाया है। हम तब छुपाते अगर हमने जो एस्टीमेट घाटे का लगाया था, उससे फालतू घाटा हो जाता और अगर ऐसा हो जाता तो ये कह देते कि देखो आपने ऐस्टीमेटस उस समय छुपाए थे लेकिन ऐसा नहीं है ये घाटा 454 करोड़ से 226 करोड़ रुपये तक आ गया है। यह किसान की सरकार है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री हो तथा किसान का बेटा वित्त मंत्री हो तो यह वह कैसे कर सकता है? अगर कोई वाणिज्य परिवार का आदमी होता तो वह ऐसा करता, वह घट बढ़ कर सकता था वह तो छुपाता लेकिन हमने कुछ घट बढ़ नहीं किया, कुछ नहीं छिपाया जो शीशा सामने था वह दिखा दिया। जो कमियां हैं वह बता दीं। (विघ्न) 2003 और 2004 में यह 226.98 से 339.58 हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। 99.39 का इस साल जो घाटा है वह होगा लेकिन स्पीकर सर, कितना बोझ आया है यह भी हमको देखना पड़ेगा। गुप्ता जी के समय जो पांचवां वेतन आयोग आया था उसने केवल हरियाणा की ही नहीं बल्कि सभी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह हम दे रहे हैं। अगर पहली तारीख की छुट्टी हो तो 31 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख या 28 तारीख को ही कर्मचारियों को तनख्वाहें दे दी जाती हैं। गुप्ता जी, बंसीलाल जी के समय का तो छोड़िए बल्कि हमने तो आपका भी भुगता है। आप तो वाणिज्य परिवार से हैं इसलिये आपको इस बारे में पता होना चाहिए। दो तीन साल जो हरियाणा में मद्य निषेध रही तो उसकी वजह से बहुत सरकारी नुकसान हुआ, मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि उनको कितना फायदा हुआ लेकिन सरकार को जो नुकसान हुआ था तो वह भी हमें ही झेलना पड़ा था। स्पीकर सर, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरा कैसे होगा? स्पीकर सर, यह डिपैंड करता है कि आपकी विल पावर कैसी है, आपकी इच्छा शक्ति कैसी है कैसी आप पॉलिसी बनाते हैं, कैसे प्रोग्राम आप लोगों को देते हैं और क्या आप पर व्यापारियों का या मैनुफैक्चर्ज का विश्वास है या नहीं? क्या आपने व्यापारियों को ऐसा एनवॉयर्नमैंट दिया है जिसमें वे आपको सहयोग कर सकें। अगर आपने उनको ऐसा एनवॉयर्नमैंट दिया है तो वे टैक्स पे करने के लिए तैयार होंगे। स्पीकर सर, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आपकी सरकार ने ऐसा एनवॉयर्नमैंट पैदा किया है और करों का सरलीकरण भी इस तरीके से किया है ताकि व्यापारियों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें इसलिए हमें उम्मीद है कि यह घाटा पूरा होगा और राजस्व करों की प्राप्ति होगी। स्पीकर सर, इसी तरह से हुड्डा साहब ने और मांगे राम जी ने वैल्यू ऐडेड टैक्स की बात कही। वैट का जहां तक सवाल है हमने एक व्यवस्था को बदला है। जो हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स है उसकी जगह वैट को रिप्लेस किया है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी चीजों पर रेट्स बजाए बढ़ने के घटे हैं। एक व्यवस्था ऐसी बन गयी कि किसी भी स्टेज पर आप कोई भी बिका हुआ माल छिपा नहीं सकते। इस तरह से इसमें अब ट्रांसपेरेन्सी आ गयी है जिसके कारण पैसा बढ़ा है। हुड्डा साहब बोलते हुए यह भी कह गए कि यह तो आम बात है। 358 करोड़ रुपया बढ़ा है। स्पीकर सर, पहले इन्होंने बताया कि 2001 में 371 करोड़ रुपये बढ़ा था और 2002 और 2003 में जो 358 करोड़ रुपया बढ़ा था वह टोटल रैवेन्यू का था, हर तरह के टैक्सिज का था लेकिन इसमें न तो सैंट्रल सेल्ज टैक्स का आता है और न इसमें हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स का है। इसको हमने रिप्लेस किया है। हमने न तो सी.एस.टी. को रिप्लेस किया है और न ही एल.ए.बी.टी. और न ही पैसेंजर टैक्स को रिप्लेस किया है। जो टैक्स की सारी रिसीट थीं आप उनके बारे में बात कर रहे थे। (विघ्न) वैट की वजह से 22 परसेंट की इंक्रीज आयी है। यह दिसम्बर तक की थी। अब जनवरी के महीने में यह 25 परसेंट हो चुकी है। स्पीकर सर, अगर आप कहें तो मैं ये आंकड़े भी दे सकता हूँ। अब 25 परसेंट इंक्रीज हो गयी

है। इसी तरह से इन्होंने चलते-चलते धान के बारे में जिक्र कर दिया। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, इनको यह भी बताना चाहिए कि वैट लगने के बाद तीन साल के बाद कितना सेल्ज टैक्स मिलेगा ?

प्रो० सम्मत सिंह : स्पीकर सर, इस पर बहुत ऐकेडमिक डिबेट चली थी। सभी स्टेट्स के फाईनेंस मिनिस्टर्ज इकट्ठे हुए थे। उन्होंने इसको लागू कर लिया और अदरवाइज वहां पर 25 स्टेट लेजिस्लेटिव असैम्बलीज ने इसको पास किया है, सारे मानकर आये हैं और उनमें से 16 स्टेट्स ने क्या किया, जो सैन्ट्रल एक्ट से संबंधित चीजें थीं जैसे कम्पनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट उनमें अमैंडमैंट कर दिया, इस वजह से राष्ट्रपति महोदय को भेजना पड़ा। आज उनका वैट का कानून राष्ट्रपति जी के पास पैंडिंग है And they are waiting for it कि वहां से क्लीयर हो कर आएगा कितना प्रौफिट होगा लेकिन हमने कम्पनीज ऐक्ट की, फैक्ट्रीज ऐक्ट की अमैंडमैंट नहीं दी और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेजा ताकि दूसरी स्टेट्स से डिफर न हो। गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की होम मिनिस्ट्री इसको कोऑर्डिनेट करती है वहां से क्लीयर हो गया, फाइनैंस मिनिस्ट्री से क्लीयर हो गया, सभी मिनिस्ट्रीज से क्लीयर हो गया और लागू कर दिया गया। वे लोग इस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। दिल्ली के और राजस्थान के मुख्यमंत्री खड़े होकर यह कहते थे कि हमारे यहां चुनाव आ रहे हैं इसलिए इस बार इसको रोक दो। यह पहले एक अप्रैल, 2002 से लागू होना था फिर 2003 से लागू होना था फिर कहने लगे कि अप्रैल, 2004 कर लो, अब अप्रैल, 2004 भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। हमें उम्मीद है कि यह सब जगह होगा ही। अध्यक्ष महोदय, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर थी इस वजह से भागकर गये वरना तो इससे बढ़िया सिस्टम हो नहीं सकता। इस बात के लिए श्रेय देना चाहिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने कि एक इच्छा शक्ति निभाई और बाकायदा उसको लागू किया। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले साल के अंदर बहुत सी स्टेट्स इसको फौलो करेंगी और उनको फौलो करना पड़ेगा। मेरे साथी पड़ोसी प्रदेशों की बात कह रहे थे। पंजाब की बात कर रहे थे पंजाब के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। 15-20 तारीख को जाकर कहीं तनख्वाह मिलती है लोन एंड वेजिज की लायबिलिटी 125 परसेंट हो गई है आपके पास तो फिर भी 20-25 परसेंट प्लॉन के लिए बच जाता है उनके पास एक नया पैसा नहीं बचता है उनके यहां तनख्वाह भी कर्ज से दी जाती है। प्लीज फोर दी गौड सेक पंजाब से हमारे साथी मुकाबला न करें जहां तक पर कैपिटा इंकम की बात है तो कोई एन.आर.आई. है कोई और है वह अलग बात है। पहले पंजाब प्रदेश कितना विकसित था। थोड़े दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हमारी पर कैपिटा इन्कम कितनी बढ़िया होगी। पंजाब का जिक्र हमारे साथी न करें। इसी तरह से मांगे राम जी ने और हुड्डा साहब ने धान का जिक्र किया। वर्ष 2002-2003 में धान की जो हरियाणा में मंडियों में आवक हुई 30.29 लाख टन और 2003-04 में 35.55 लाख टन हुई। 5.5 लाख टन धान की आवक ज्यादा हुई है आपने तो कह दिया कि 5 लाख टन धान की आवक पंजाब से ज्यादा हुई है। पंजाब हम से काफी ज्यादा प्रौड्यूस करता है इसका मतलब परसैंटेजवाइज हरियाणा की मंडियों में ज्यादा धान आया है। केवल मात्र सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए ये साथी बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर ये कहें तो मैं इनको रसीद दिखा दूं। इन्होंने बोल तो लिया। 5.5 लाख टन ज्यादा हुआ है पंजाब के हिसाब से (विघ्न) मैं बता रहा हूं कि हरियाणा में यह रेंज है वह। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, ****

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : जो सदस्य चेयर की परमिशन के बगैर बोलता है उसकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये।

प्रो० सम्पत सिंह : हरियाणा की रेंज 1100 से 1450 है जबकि पंजाब की रेंज एक हजार से 1400 तक है। इस प्रकार हरियाणा में महंगा बिक रहा है पंजाब से। दूसरी एक बात मैं कहता हूँ कि यह हरियाणा बनने से आज तक इतिहास रहा है कि जो भी टैक्स हैं (विघ्न) आज कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो गये जिनको ज्ञान नहीं है। स्पीकर सर, एक बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वह मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा 1966 में बना था और 1996 से 1999 तक जब चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी जितने भी टैक्स थे चाहे वह जनरल टैक्स हो या सी.एस.टी. हो सारे टैक्स 16914 करोड़ रुपये के इकट्ठे हुए हैं जब से हरियाणा बना है और 1998-99 तक और उसके बाद जो आपने व्यवस्था स्थापित की है जिसमें व्यापारियों से, ट्रेडर्स से, मैन्यूफैक्चर्ज से जिन्होंने आपको कोआप्रेट किया है उसकी वजह से जनवरी, 2004 तक 18851 करोड़ रुपये टैक्स इकट्ठा हुआ है जबकि 1966 से 1998 तक 16914 करोड़ रुपये हुआ है अगर इसकी टोटल ऐवरेज निकालें तो सारा जोड़कर अब तक 18851 करोड़ रुपये टैक्स इकट्ठा हुआ है। पहले यह पैसा लोगों की जेबों में जाता था अब सरकारी खजाने में जाता है। (विघ्न) इसी तरह से स्पीकर सर, एक जो वैट सिस्टम प्रणाली के बारे में इन्होंने कहा। जिन चीजों पर घटा है सरकार ने छूट दी है उन चीजों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। यह जीरो से 4, 8, 12.5 को स्लैब पर 10 प्रतिशत जिसका जिक्र मैंने नहीं किया क्योंकि जनरल रेट ऑफ टैक्स आलमोस्ट दस प्रतिशत हो आता है इसलिये स्लैब इसमें रखा है और सरकार ने इसमें अपने अनुसार थोड़ी अमैंडमेंट भी की है। ताकि स्टेट का ट्रेड सफर न करे। दूसरे, बर्फ, बांस, जलाऊ लकड़ी और लकड़ी के बुरादे पर टैक्स 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर घटा है। मसाले पर 10 प्रतिशत से 4 प्रतिशत घटा है, हैंड पम्प और उसके पार्ट्स पर आठ प्रतिशत से चार प्रतिशत घटा है निर्विघ्न पॉवर सप्लाई यू.पी.सी., मोबाइल सैट और सैल्यूलर फोन पर 12 से लेकर 4 प्रतिशत घटा है। पोल्ट्री फीड सप्लीमैंट्स और कैटल फीड सप्लीमैंट्स पर दस प्रतिशत से चार प्रतिशत घटा है, प्लास्टिक के कच्चे माल पर जैसे पी.वी.सी. कम्पोनैंट्स पर दस से चार प्रतिशत और पी.वी.सी. रैजिंग और प्लास्टिक के पोलीमर पर, कच्ची रबड़ और रबड़ के कैमीकल्ज पर, कार्बन ब्लैक पर दस प्रतिशत से चार प्रतिशत, बायो गैस प्लांट से प्रयुक्त मशीनरी पर और बायो गैस बर्नर और बायो गैस हाई प्लेट को कर मुक्त कर दिया है और बायो गैस खाद और जिप्सम पर दस प्रतिशत से चार प्रतिशत कर दिया है। पुरानी कारों पर जिसमें एक हजार सी.सी. की गाड़ियां हैं 12 प्रतिशत से घटाकर तीन हजार रुपये सेल्स टैक्स कम कर दिया है। वैट के ऊपर विशेष आर्थिक स्कीम, निर्यात इकाई स्कीम, निर्यात प्रसंस्करण स्कीम, निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, औद्योगिक पार्क स्कीम, सॉफ्टवेयर तकनीक स्कीम आदि-आदि निर्यात के सिलसिले में विक्रय के लिए विनिर्माण के प्रयोग हेतु माल बिना कर दिए खरीद सकते हैं। टायर ट्यूब की दर दस प्रतिशत से आठ प्रतिशत कर दी गई है। ये कह रहे हैं कि बढ़ाया है, हमने तो घटाया है। बिजली का सामान जो उद्योगों में प्रयोग होता है दस प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है। रासायनिक खाद कर मुक्त है। विमान टर्बाइन इन्जन, पैट्रोल गैस, तीव्र गति डीजल, सुपर लाईट डीजल, आयल लाईट डीजल, आयल मिट्टी का तेल, सरल पेट्रोलियम गैस, लो सल्फर हैवी स्टोक, बैरनस आयल इसी तरह के सभी आयल एक कम्पनी दूसरी कम्पनी को बेचेगी तो कर की दर केवल चार प्रतिशत होगी। स्पीकर सर, हमने इसमें रियायत दी है इसको घटाया है, कहीं बढ़ाया नहीं है। जो ये बढ़ाने की बात कर रहे थे वो यूजर चार्जिज की बात कर रहे थे। हमने तो कई चीजों पर घटाया है। स्पीकर सर, अभी करन लेजिस्लेशन आयेगा और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी कि कैबिनेट ने उसको एप्रूव कर दिया है। स्टाम्प ड्यूटी जो पहले 12.50 प्रतिशत थी उसको कम करके 6 प्रतिशत किया गया है। इसी तरीके से शहरों में जहां 15.50 प्रतिशत या 16 प्रतिशत थी उसको कम करके 8 प्रतिशत किया गया है। स्पीकर सर, इसी तरीके से मार्टगेज वगैरह,

ट्रांसफर फीस आदि को भी कम करके आधा रेट कर दिया गया है। इस तरह से इस सरकार ने घटाने का काम किया है बढ़ाने का काम नहीं किया। बढ़ाया है तो रैवेन्यू बढ़ाया है और टैक्सिज घटाकर बढ़ाया है ताकि एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। स्पीकर सर, अब जो नुकसान हो रहा है हरियाणा प्रदेश को वह सैंटर के फैडरल सिस्टम के लागू होने से हो रहा है। इसके तहत सैंटर को सैंट्रल टैक्सिज इन्कम टैक्स वगैरह से आमदनी तो सभी स्टेट्स से होगी। हरियाणा सरकार भी एक्साईज ड्यूटी पे कर रही है, हिमाचल प्रदेश, यू.पी., पंजाब यानि सभी स्टेट्स एक्साईज ड्यूटी पे करते हैं और बदले में इनके फैडरल सिस्टम के मुताबिक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सब स्टेटों से पैसा आता है और सबको जाता भी है। अब इसमें क्या कर दिया ब्लू वाईट स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनाव आ गया, ठीक है अपने लंगर कस लो, चुनाव जीतना है इसलिये इस स्टेट की इण्डस्ट्रीज की एक्साईज ड्यूटी माफ कर दो, इन्कम टैक्स माफ कर दो। इसका डायरैक्ट असर किस पर पड़ेगा, हरियाणा पर ही पड़ेगा। वे कोई एक्साईज ड्यूटी पे नहीं करेंगे लेकिन जब फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनको भी मिल जावेगा। उनको डबल फायदा होगा, एक उन्होंने देना नहीं लेकिन ले लेना है। यह नुकसान डायरैक्ट हरियाणा प्रदेश को हुआ है। स्पीकर सर, इसी तरीके से सैंट्रल गवर्नमैंट के इस बजट में मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इन्कम टैक्स में रियायत देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने हाउसिंग बोर्ड, मार्केटिंग कमेटीज, एच.आर.डी.एफ. पर इन्कम टैक्स लगाने की योजना बनाई है जो कि बड़ा घातक फैसला है। इसको न लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार सैंटर सरकार को लैटर भी लिखे हैं। (विघ्न) इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जहां हमें 800-800 करोड़ रुपये मार्केटिंग बोर्ड से, 700-700 करोड़ रुपये एच.आर.डी.एफ. से आ रहा था आज उन पर भी भारत सरकार इन्कम टैक्स लगाने जा रही है। अगर इन पर इन्कम टैक्स लगाया गया तो भुगतना तो हमें ही पड़ेगा और बदले में फायदा बीमारू स्टेट्स ले जावेंगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे सभी साथी भारत सरकार से अपील करें कि हरियाणा प्रदेश को मत मारो। क्योंकि इन चीजों पर इन्कम टैक्स वे लगा रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर सर, केन्द्रीय सहायता भी हमें कम मिली है। बार-बार हर प्लेटफार्म पर यह आवाज हम उठाते हैं। पीछे श्रीनगर में इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग थी उससे पहले हर साल एन.डी.सी. की मीटिंग होती है। हर मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इन बातों को उठाया है कि भारत सरकार स्टेट के संसाधनों को कम कर रही है और सैंटर अपने संसाधन बढ़ा रही है। स्टेट्स को ऐसे समझा जा रहा है जैसे ये भिखमंगी हों। ये सैंटर से मांग मांगकर ले जावेंगी। ऐसा फैडरल सिस्टम मत करो इससे नुकसान होता है खासतौर से उन स्टेट्स को जो परफोर्मिंग स्टेट्स हैं। उनको आप प्रताड़ित करते हो और नोन परफोर्मिंग स्टेट्स को उत्साहित करते हो। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दे बार-बार हर प्लेटफार्म पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने उठाये हैं। इन चीजों की हमें कमी हुई है लेकिन हमने अपने संसाधनों से अपना काम चलाया है। अध्यक्ष महोदय, सैंटर से केन्द्रीय ग्रांट्स में जो कमी आई है उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ कि और खासतौर से मेरे सीनियर साथी राव इन्द्रजीत सिंह को। उन्होंने एक बात फरमाई कि जो इलैवन्थ फाईनांस कमीशन था उसका डिवोल्यूशन ऑफ फण्ड पहले वाले साल के मुकाबले में कम है। यहां पर हरियाणा प्रदेश को सहायता देने की बात भी कही गयी है कि डिवोल्यूशन ऑफ फण्ड की एलोकेट पहले 1.238 परसेंट थी। हमें टोटल डिवोल्यूशन का जो 1.238 परसेंट था वह अब कम होकर 0.947 परसेंट रह गया। यहां कहा गया कि वह इसलिए घट गया कि हम इसको सही तरीके से खर्च नहीं कर पाये और भारत सरकार की शर्तें पूरी नहीं की। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है। यह वर्ष 2002 से 2005 तक की बात है। उन्होंने अपनी 2002 में रिपोर्ट दे दी जबकि खर्च तो बाद में हुआ। इसमें अधिमान किसको दिया यानि वेटेज किसको दी। उन्होंने पर-कैपिटा इन्कम को माना। इसमें रिवर्स हुआ। अगर आपकी इन्कम ज्यादा है तो कम मिलेगा और अगर आपकी इन्कम कम है तो ज्यादा मिलेगा। हरियाणा में पर-

[प्रो० सम्पत सिंह]

कैपिटा इन्कम ज्यादा है। पंजाब, महाराष्ट्र व गोवा में भी पर-कैपिटा इन्कम ज्यादा है। इन सभी स्टेट्स को नुकसान हुआ। उन्होंने वेटेज को साढ़े बारह परसेंट माना है, पापुलेशन को बीस परसेंट माना है, एरिया को को पांच परसेंट माना है और फिजिकल मैनेजमेंट को साढ़े सात परसेंट माना है। इस प्रकार से उन्होंने 100 परसेंट की डिवोल्यूशन की है। मैं राव साहब को बताना चाहूँगा कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि कहीं पर खर्च में कमी थी। उन्होंने हमारे को क्या मान लिया वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने हमारे को सरप्लस स्टेट मान लिया। मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू डैफिसिट 3500 करोड़ रुपये था। इन्होंने कह दिया कि आप का तो 1500 करोड़ रुपये सरप्लस है, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। यह मान करके यह निर्धारण किया और इस मापदण्ड से 1100 करोड़ रुपये से फालतू का नुकसान हो लिया है और डेली का नुकसान अलग से हो रहा है। स्पीकर साहब, सही भायनों में डिस्ट्रीब्यूशन सैन्ट्रल टैक्सिज की जो आनी चाहिए थी वह 2776 करोड़ रुपये की आनी चाहिए लेकिन हमारे पास इसमें से 2323 करोड़ रुपये आए यानि 455 करोड़ रुपये कम आये। इसी तरह से जो केन्द्र से आम सहायता मिलती है वह 1068 करोड़ रुपये के मुकाबले में 973 करोड़ रुपये मिली यानि इस मद में भी 95 करोड़ रुपये कम आये। इसी प्रकार से सैन्ट्रल स्पौंसर्ड स्कीम में जहां हमें 1300 करोड़ रुपये आने चाहिएं थे वहां पर हमें 756 करोड़ रुपये आये यानि इस में भी हमें 544 करोड़ रुपये कम आये। स्पीकर साहब, पेट्रोल और डीज़ल पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर सैस लगाया। इस सैस की वजह से भारत सरकार को हरियाणा प्रदेश से 1100 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। यह पैसा किसका गया है, यह पैसा तो हरियाणा प्रदेश के लोगों का ही गया है। कंजम्पशन तो सारी यहीं पर हुई है। अगर यही टैक्स हमारा अपना होता तो 1100 करोड़ रुपया हमें मिलता। वाह-वाही वो लूटने की कोशिश करते हैं जबकि पैसा हमारा है। यहां पर एक साथी ने कहा कि माल किसका कमाल किसका। मैं उस साथी को बताना चाहूँगा कि माल हरियाणा का और कमाल सैन्टर का। सैन्ट्रल गवर्नमैंट इस सैस का 1100 करोड़ रुपया यहां से ले गई और बदले में सिर्फ 174 करोड़ रुपये दिया है। फिफ्टी-फिफ्टी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी इस सैस में जो कुल आयेगा उसका 50 परसेंट पैसा तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टरी को जायेगा और 50 परसेंट पैसा रोड्ज लिंकेज के लिए जायेगा। अब क्या यह हमारी बदकिस्मती है कि कि हमारा हर गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। वे यह नहीं देखते कि रोड्ज कब की बनी हुई हैं जबकि आज उन सड़कों की मैंटीनेंस को जरूरत है, उनकी बाइर्डनिंग की और स्ट्रैंथम करने की जरूरत है। लेकिन उसके लिए नहीं बल्कि बीमार स्टेट को ज्यादा दे करके हमें 1100 करोड़ रुपये में से सिर्फ 174 करोड़ रुपये दिया। हमारा पैसा हमें देने की बजाये दूसरी स्टेट्स को गया है। हमने तो अपने संसाधनों से काम लिया है वरना तो हमारा साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये और सैन्ट्रल गवर्नमैंट से लेना बनता है जो हमें नहीं मिला यानि हमें कम आया है। यहां पर साथियों ने बोलते हुए सड़कों के बारे में जिक्र किया कि वर्तमान सरकार ने सड़कों की मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2004-05 में इसके लिए 320 करोड़ रुपये रखे गए हैं और 180 करोड़ रुपया मार्किटिंग बोर्ड का इससे अलग है। वर्ष 1999-2000 में सड़कों के लिए कितना पैसा था वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा। उस वक्त सड़कों के लिए सिर्फ 20.32 करोड़ रुपये था। चौधरी भजन लाल जी जब वर्ष 1991-92 से लेकर वर्ष 1995-96 तक जब मुख्यमंत्री रहे तो इन्होंने सड़कों पर टोटल पांच साल में केवल 68.90 करोड़ रुपये खर्च किया था जबकि आपकी सरकार के वक्त में इस काम पर 496.54 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कहां 20 करोड़ रुपये और 70 करोड़ रुपये के करीब और कहां 496 करोड़ रुपये खर्च हुआ। इसके अलावा मार्किटिंग बोर्ड का जो 716 करोड़ रुपये खर्च हुआ वह अलग से है। यानी इस तरह से कुल मिला कर सड़कों पर आपकी सरकार ने 1213 करोड़ रुपये खर्च किए। मेरा कहना यह है कि हमने

सड़कों पर पैसा कम खर्च नहीं किया। यहां पर हुड्डा साहब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी सड़कों के लिए कम ब्याज पर कर्जा देने की। हुड्डा साहब ने कहा कि वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिया जबकि यह सस्ता लोन था। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के लिए सस्ते ब्याज पर कर्जा देने की वर्ल्ड बैंक की स्कीम थी यह स्कीम 690 करोड़ रुपये की थी और आपने इस स्कीम को छोड़ दिया और महंगे ब्याज पर कर्जा लिया। स्पीकर सर, हमने हुडको से भी ब्याज पर लोन लिया और जगहों से भी लोन लिया। स्पीकर सर, आपको मालूम है कि 11 मई, 1998 को पोखरण न्यूक्लीयर टैस्ट के तुरन्त बाद अमेरिका ने इकोनोमिक सैंक्शन लगा दी थी तो स्वाभाविक बात है कि आपको कर्जा नहीं मिला क्योंकि सब जगह सैक्शन लगी हुई थी। किसी भी स्टेट को कर्जा नहीं मिला सब जगह सैक्शन लगी हुई थी। इस बात को जानते हुए भी ये इस बात को उठा रहे हैं इसलिए हमने यह सोचा कि अगर वर्ल्ड बैंक कर्जा नहीं दे रहा न दे कोई बात नहीं। हमारे पास अगर साधन है किसी को अगर हम पर विश्वास है, हमारे घर के अन्दर कोई दाम है तभी कर्जा कोई दे रहा है। हमारी सोच है कि ऐसा नहीं होना चाहिए सड़कें टूटी रहें और लोग रोज मरते रहें इसलिए हुड्डा साहब, इसके लिए हमने 323 करोड़ रुपये का कर्जा लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह कर्जा हमने वर्ल्ड बैंक की सैक्शन लगने की वजह से लिया। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय जी से मैं यह निवेदन करूँगा कि वे कृपया यह बताएं वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए आपने कुछ पैसा कन्सलटैंसी के लिए भी दिया था, वह क्यों दिया था ?

प्रो० सम्मत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि वह तो पहले ही हो गया था लोन के लिए पेपर्ज वगैरह तैयार करने पड़ते हैं और वह सब तो पहले ही हो लिया था वह हमने नहीं किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हुड्डा साहब की एक-एक बात का जवाब दे रहा हूँ। इसके साथ ही इन्होंने स्पैशली पंजाब ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा कि we are paying more passengers tax in Punjab than the K.Ms. we are running in the Punjab. Roughly passengers Tax for one lac Kilometers in Punjab something हुड्डा साहब ने कहा था। स्पीकर साहब, जहां तक सवाल है पिछले अप्रैल और जनवरी, 2004 का हरियाणा रोडवेज 335.12 Lac kms पंजाब टैरीटरी में हमारी बसों ने ऑपरेट किया है और 796 Lac स्पैशल रोड़ टैक्स आया है। ऐप्रोक्सीमेटली 2.38% टैक्स आया है payable in Punjab Territory था वह 2.99 पर किलोमीटर यह शो कर रहा है कि कोई एक्सैस पेमैंट नहीं की गई है बल्कि कम पेमैंट की है। दूसरी बात इन्होंने यह कही Ministry of Roads and Transport highways Government of India ने 2002-03 के अन्दर के.एम.पी.एल. खर्च होता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ इन्होंने पंजाब को राजस्थान के साथ कम्पेयर किया। अब राजस्थान का कम्पैरिज़न हम कैसे करेंगे। हमारा पहले था 4.54 और आज बढ़ कर हो गया है 4.77 । स्पीकर सर, हमने इसमें सुधार किया है। हमने नई बसें खरीदी हैं। जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक किलोमीटर के हिसाब से सब से ज्यादा पर लीटर हमारी बसें चल रही हैं 4.77 और राजस्थान में 4.88 है इसलिए राजस्थान का ज्यादा आ रहा है क्योंकि वहां पर लोकल रूट्स पर बसें नहीं चलती हैं। राजस्थान की बसें नैशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर चलती हैं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : वित्त मंत्री जी, जो पंजाब की पैसेंजर टैक्स की बात है वह मैं नहीं कह रहा

हूँ यह आपकी सी.ए.जी. की 2002 की रिपोर्ट में पेज 122 पर दिया हुआ है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले सी.ए.जी. की रिपोर्ट का ही जवाब दे देता हूँ। जहां तक सी.ए.जी. की रिपोर्ट का सवाल है, सी.ए.जी. ने तो अपने कमैंट्स दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके बाद इसमें डिफरैंट डिपार्टमैंट्स अपना जवाब देते हैं फिर पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी/पब्लिक एकाउंटस कमेटी के पास मामला जाता है वहां पर डिस्कशन होती है और यह रिपोर्ट फिर पास होती है। यह तो केवल सी.ए.जी. की ऑब्जर्वेशन है, इसके बाद इस पर गहन मनन होना है, उसके ऊपर जवाब दिया जाएगा और अन्तिम निर्णय होगा। इनको यह भी मालूम नहीं है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट पर डिस्कशन कब करनी चाहिए, बड़े अफसोस की बात है इसमें अब हम क्या करें। मैंने स्थिति बता दी है। स्पीकर साहब, राजस्थान के साथ हमारा कोई कम्पैरिजन नहीं है और जो हमारा डिफरैंस है वह मात्र .11 का है और वह भी इसलिए है कि राजस्थान नैशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर ही बसें चलाते हैं जबकि हमारी बसें गांवों तक जाती हैं। हमारी बसें तो गांवों में इन्टीरियर तक जाती हैं इस वजह से यह इतना फर्क है। स्पीकर साहब, इन्होंने एक और बात कही कि आपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज पर टैक्स बढ़ा दिया। मोटर व्हीकल ऐक्ट गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया का है और यह टैक्स सैंटर गवर्नमैंट ने बढ़ाया है and we are bound by that. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठें। आपका कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। प्रोफैसर साहब, क्लीयर कर रहे हैं। इसमें जो कुछ भी किया है वह केन्द्र की सरकार ने किया है, स्टेट गवर्नमैंट ने कुछ नहीं किया है। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : यह जो ड्राईविंग लाइसैंस की बात कर रहे हैं तो यह मोटर व्हीकल एक्ट, गवर्नमैंट आफ इण्डिया के अन्डर आता है। यह फीस हमने नहीं बढ़ाई है। टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमैंट के अन्डर नहीं है। इन्होंने कहा है कि Tax on Maxi Cab has been increased. पहले जो टैक्स लिया जाता है तो वह 150 रुपए प्रति सीट के हिसाब से लिया जाता था, इसको हमने घटा कर 100 रुपए प्रति सीट कर दिया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) (विघ्न) इसी तरह से इन्होंने कहा है कि नम्बर ऑफ ट्यूबवैल्ज़ घट गए हैं। अब पता नहीं ये आकड़े कहां से ले आते हैं। इन्होंने 1998-99 में 3 लाख 61 हजार 454 के आंकड़े बताए हैं। 1999-2000 के 3 लाख 53 हजार 899 का फिगर बताया है, अब ये कनैक्शन बढ़कर 3 लाख 79 हजार 099 हो गए हैं। इसमें 26 हजार 800 की बढ़ोतरी हुई है। ये कहते हैं कि आंकड़े घटे हैं। जबकि हमने ट्यूबवैल्ज़ के कनैक्शन 36 हजार 858 बढ़ाए हैं। ड्यूज की वजह से, डिस्कनैक्शन की वजह से और अगर कहीं पर खारा पानी आता है तो कनैक्शन कटवाया ही जाएगा। (विघ्न) हमने 36 हजार 858 कनैक्शन दिए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

चौधरी जय प्रकाश : * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (विघ्न) जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अब मैं टी. एण्ड डी. लोसिज के बारे में कहना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप इस तरीके से बीच में मत बोलें, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। (विघ्न)

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अब मैं टी. एंड डी. लोसिज पर आ रहा हूँ। (विघ्न) टी.एंड.डी. लोसिज पहले 17.8 था और नार्मज के हिसाब से लोसिज 15.5 के होने चाहिए। स्पीकर सर, हरियाणा में एक रैगुलेटरी कमीशन है। हमारी सरकार के आने से पहले जो लोसिज होते थे उन लोसिज को अनमीटर्ड सप्लाई के खाते में खपा दिया जाता था। उस समय यह किया जाता था कि इतने प्रतिशत खपत हुई है तो उतना ही प्रतिशत फार्मर्ज पर डाल दिया जाता था। स्पीकर सर, फार्मर्ज के जिम्मे सारे का सारा पैसा डाल दिया जाता था। लेकिन सर, आज वह बात नहीं रही है। आज रैगुलेटरी कमीशन है, वह एक-एक चीज को मोनिटर करता है। स्पीकर सर, कुछ सदस्यों ने बोलते हुए यह कहा कि खपत 7 और 8 घंटों की है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि रैगुलेटरी कमीशन उसको भी खपत नहीं मानता है। उसका कहना है कि अगर 4 और 5 घण्टों की एवरेज लेंगे तो उसको माना जाएगा। स्पीकर सर, 2001-02 में 40.19 प्रतिशत खपत मानी गई है। हुड्डा जी, उसके बाद हमने इसको 3 प्रतिशत घटाया है। 2002-03 में यह खपत घटकर 37.27 प्रतिशत रह गई थी। Nothing is hidden, हम कोई चीज छिपाते नहीं हैं और हर साल हम उसको घटाएंगे। हम ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको भी ठीक करेंगे। जो नए सब-स्टेशन बन रहे हैं, जितने भी ट्रांसफार्मर्ज बदले जा रहे हैं। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं सदन में यह बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार होती थी, उस वक्त ये एक नया पैसा भी खर्च नहीं करते थे। हमारी सरकार के वक्त में लाईनें बदली जा रही हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत कर दिए गए हैं और सब-स्टेशंज बनाते जा रहे हैं। स्पीकर सर, इसलिए यह स्वाभाविक है कि ये लोस नीचे आएंगे। इन्होंने जो पंजाब के लोस 15 प्रतिशत बताए हैं तो मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि वह 26 प्रतिशत है। यह भी इसलिए है क्योंकि उनके पास ऐग्रीकल्चर का खाता ही नहीं है। स्पीकर सर, जहां तक बिजली की प्राप्ति की बात है तो वह 561 लाख यूनिट की ऐवरेज है। (विघ्न) पहले जो ऐवरेज थी वह 367 लाख यूनिट की थी, अब इसमें 53 प्रतिशत की इन्क्रीज हुई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रघुबीर सिंह जी, आप बीच में बिना इजाजत के न बोलें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (विघ्न) डॉक्टर साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

श्री अध्यक्ष : बैठिए-बैठिए। Be cultured. इस तरह का व्यवहार न करें। इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाए। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : इसी तरह से स्पीकर साहब, यहां पर एच.एफ.सी. का जिक्र किया गया है। (विघ्न)

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पंजाब के लाईन लौसिज 17 परसेंट बताएं हैं जबकि ये 15 परसेंट बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ये पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि बोल रहे हैं। इसलिए जय प्रकाश जी आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंह : हम मेहनत करते हैं इनकी तरह से नहीं हैं। स्पीकर सर, इसी तरह से इन्होंने फाईनेंशियल कॉरपोरेशन का जिक्र किया। (विघ्न) इन्होंने कहा है कि फाईनेंशियल कॉरपोरेशन ने सिर्फ 19.4 करोड़ रुपये ही लोन दिया है। स्पीकर सर, आपको मालूम ही है कि जब से लिब्रलाइजेशन की पॉलिसी आयी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। आप विदाउट परमिशन नहीं बोल सकते। हुड्डा साहब, आप इन्हें बिठाइये।

श्री भुपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर साहब, आप उन्हें अपनी बात कहने ही नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मुझे एक डर है कि ये भाग न जाएं इसलिए मैं एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें सबका जवाब आ रहा है। इनकी कोई बात रिकॉर्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हुड्डा साहब ने एक शब्द एस.वाई.एल. के बारे में कहा था। मैं इस बारे में पहले बता देना चाहता हूँ क्योंकि बाद में कहीं ये वाकआउट न कर जाएं। इन्होंने कहा था कि एस.वाई.एल. पर एक पैसे का बजट हमने नहीं रखा। हुड्डा साहब, आपने केवल न्यू एक्सपैंडीचर 2004-2005 ही पढ़ा है आप सिर्फ बजट एट-ए-ग्लांस के चार पेज पढ़कर ही पास हो जाते हो। अगर आपने न्यू एक्सपैंडीचर 2004-2005 पढ़ा हो तो बताएं। मैं आपको इसका पेज नम्बर बता देता हूँ। आप इसका पेज नं० 362 पढ़ लें और इसका 110 का सब हैड भी पढ़ लें। वह है - "सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स।" पिछले 6-7 सालों से एक करोड़ रुपये का नोशनल हर सरकार रखती आयी है चाहे वह आपकी सरकार थी या चाहे उससे पहले की सरकार थी। (शोर एवं व्यवधान) इनका यह कहना कि एस.वाई.एल. पर एक पैसा नहीं रखा, ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। आप सुनिए ये पिछला सत्र रहे हैं। वह रख रखाव के लिए होता है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, वह नोशनल मनी है। अब ये अपनी बात की झेंप नहीं मिटा सकते। इसका मतलब ये स्टडी नहीं करके आते क्योंकि इन्होंने कहा है कि एस.वाई.एल. पर एक पैसा नहीं रखा है। लेकिन एक करोड़ रुपया नोशनल रखा है। हाउस के सामने मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ कि जब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और वह कह देगा कि फलाना एजेंसी इसको बनाएगी तो हम इसके लिए पैसा देंगे।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

स्पीकर सर, पहले तो पैसा खुद ही लगाना पड़ता है बाद में उसका रिइम्बर्समैंट भारत सरकार करती है। इसलिए पहले पैसा खर्च करने की बात है। एस.बाई.एल. के लिए चाहे हमें ऐस्टीमेटस के अंदर कितना ही सप्लीमैंट्री ऐस्टीमेटस पास करना पड़े, हम करेंगे। चाहे इसके लिए हमें अपना कितना ही खर्चा कम करना पड़े, हम करेंगे। वाकायदा हम एस.बाई.एल. पर पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। That is a notional money और नैशनल मनी आज नहीं बल्कि हर साल रखी जाती है। इन्होंने कहा कि एक पैसा नहीं रखा है। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, ये मजबूरी में कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप इस जोड़ी को बिठाइये। इनको पानी की क्या चिंता है ? (शोर एवं व्यवधान) यह मांगे राम जी की तरह वित्त मंत्री नहीं है। मांगे राम जी पानी थोड़े ही मांगेंगे। (विघ्न)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकॉर्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी, आप बैठिए। (विघ्न) बलबीर सिंह, आप बैठिए। जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : सच्चाई हमेशा कड़वी होती है इसमें कोई दो राय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अभी लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट का जिक्र किया कि कोई एक नया पैसा नहीं आया है यह सैन्ट्रल मिनिस्टर का ब्यान 22.8.03 का है कि फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट मिल आया है। उस वक्त हमारे मैंबर जाकर के उनको मिले और कहा कि ये कैसे कह रहे हैं तब उन्होंने कहा कि इनके रजिस्ट्रेशन के आफिसेस दिल्ली में है इसलिए हम कह रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। हरियाणा गवर्नमैंट ने चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी का जवाब न देना इसका मतलब क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। एक चिट्ठी लिखी उसका भी जवाब देने में मुश्किल हो गई। जुलाई 1999-2000 में फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट 474 करोड़ रहा है, 2000-2001 में 347 करोड़, 2001-2002 में 400 करोड़, 2002-03 में 1857 करोड़ हुआ है। आप कहें तो कंपनियों के नाम भी गिना देता हूँ -- मैसर्ज मारुति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव का 2002-03 में 1399 करोड़, मैसर्ज एफिन इंडिया 24 करोड़, वाल्को इलैक्ट्रिकल्स 29 करोड़, एफएन इंडिया 1 करोड़ 16 लाख, ऐस्कोर्ट्स 14 करोड़ 26 लाख, मैसर्ज जी. कैपिटल पहले साल 75 करोड़, दूसरे साल 115 करोड़, मैसर्ज हौंडा स्कूटर्स पहले साल 115 करोड़ और दूसरे साल 85 करोड़ और तीसरे साल 100 करोड़, डैसो हरियाणा 204 करोड़ इसी तरह से अल्काटेल 37 करोड़।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सम्पत सिंह जी, हमें आपका ध्यान रखना पड़ता है आपको वैसे भी बहुत पसीना आ रहा है अब आप और आंकड़े न बताएं।

प्रो० संपत सिंह : आप संतुष्ट हैं न। आगे इन्होंने कह दिया कि इण्डस्ट्रीज का नम्बर घट रहा है। (शोर एवं व्यवधान) जहां तक उद्योग लगाने की बात है पिछले साल 198 नये बड़े उद्योग और 4500 लघु उद्योग स्थापित हुए हैं। यह कहते हैं कि टोटल नम्बर सैंसिज घट रहा है। स्पीकर सर, ऐसा वक्त भी था जब केवल मात्र सबसिडी लेने के लिए, केवल मात्र एच.एफ.सी. को अपनी जेबी संस्था बनाने के लिए लोन लिए जाते थे और लेकर पार हो जाते थे। आज रोजाना हमें उनके नोटिस मिल रहे हैं, यह काम कर गई पहले की सरकारें और भुगत हम रहे हैं। आज उस समय की इण्डस्ट्रीज की रोजाना ऑक्शन हो रही है। जो पहले की सरकारों के समय इण्डस्ट्रीज लगी थी वे एक दिन भी नहीं चली उन इण्डस्ट्रीज का पैसा खा गई पहले की सरकारें और आज वे संस्था

[प्रो० सम्पत सिंह]

की बात कर रहे हैं। जो इण्डस्ट्रीज इस सरकार के समय में लगी हैं उनमें से एक भी इण्डस्ट्री बन्द नहीं हुई है और आज पानीपत में पैट्रो कैमीकल्ज की इण्डस्ट्री स्थापित हो रही है जिससे दस हजार रुपये का एक्सपोर्ट हो रहा है ये सारी एचीवमैंट्स वर्तमान सरकार के प्रयास से हुई है। (विघ्न) स्पीकर सर, कई माननीय सदस्यों ने कृषि बीमा योजना के बारे में कहा कि बाजरे, ज्वार, चने और सरसों पर तो यह योजना लागू कर दी लेकिन गेहूँ, धान और गन्ने पर इस योजना को लागू नहीं किया। स्पीकर सर, आप किसान हैं और आप इफको के चेयरमैन भी रहे हैं इसलिए आपको इन सब बातों का ज्ञान है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ और ये इस शर्त पर मानने के लिए तैयार हैं सरसों पर तो बीमा रखा है इसमें एक तो ब्लॉक एज ए यूनिट होना चाहिए। ब्लॉक एज ए यूनिट होकर जो नुकसान होगा, उसमें पहली पांच साल की प्रोडक्सन की एवरेज ली जायेगी। मान लो कि 16 क्विंटल प्रति एकड़ आपकी पैडी की पैदावार हुई है और एक लाख एकड़ आपके पास जमीन है तो इस प्रकार 16 लाख टन क्विंटल पैदावार हो गई तो ठीक है अगर नहीं हुई तो उसको नुकसान मानेंगे। अगर उसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच हजार एकड़ जमीन की फसल खराब हो गई तो एवरेज में अगर आपकी फसल अच्छी हुई है तो और एवरेज ज्यादा आ गई तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ब्लॉक पूरी एवरेज के हिसाब से बनाया गया था। इसलिए सरकार ने हाई रिस्क की फसलों को इसमें लिया है। सरसों जो है वह एक मिनट के अन्दर साफ हो जाती है एक सैकिण्ड के अन्दर साफ हो जाती है। इसी तरह कपास में अगर सुण्डी लग जाये तो वह खत्म हो जाती है ये लो रिस्क की है। पिछले सालों के आंकड़े चाहे आप गेहूँ के ले लें, चाहे पैडी के ले लें और चाहे गन्ने के ले लें इतना हाई रिस्क प्रीमियम आपको देना पड़े इस कारण से इन फसलों को नहीं लिया वरना सरकार को इस में कोई गुरेज नहीं था। आज इनको क्यों तकलीफ हो रही है अगर किसी चीज का नाम चौधरी देवी लाल के नाम पर रख दिया जैसे देवी रुपक योजना और देवी रक्षक योजना है, क्या बुरा कर दिया सरकार ने देवी रुपक योजना लागू करके। अगर किसी कमेरे वर्ग का आदमी मर जाता है तो उस परिवार को सरकार की तरफ से एक लाख रुपये दिये जाते हैं जबकि बीमा कम्पनी को सरकार थोड़ा सा प्रीमियम देती है लेकिन बीमा कम्पनी को उस परिवार को एक लाख रुपये देने पड़ेंगे। इसमें बुराई क्या है। बीमा कम्पनी तो आज पछता रही है कि सरकार इतना कम प्रीमियम देती है लेकिन बीमा कम्पनी को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ये यह नहीं कहते कि ऐसी स्कीम को तो ऐडोप्ट करना चाहिए जो कि जनता के वैल्फेयर की है। ऐसी स्कीमें तो सरकार के लिए रखी हैं जिनमें प्रीमियम ज्यादा देना पड़े। जो लोग कम जोत के हैं और जो फार्मरज हैं उनको 50 प्रतिशत का प्रीमियम सरकार देती है। (विघ्न) स्पीकर सर, 1985 में यह एक तिहाई और दो तिहाई हैं ये स्कीमें पुरानी हैं इनको थोड़ा बढ़ाया है इनके स्कोप को भी बढ़ाया है। इसमें एनीमल हस्बैंड्री, हार्टीकल्चर, हाउसिंग को भी शामिल किया गया है। लोगों के जो लोसिज हैं, जो मार्जिनल फार्मर्ज हैं, जो कमजोर हैं उनको 50 प्रतिशत में से आधा सैंटर और आधा स्टेट बीयर करेगा और 50 प्रतिशत उस फार्मर को खुद देना पड़ेगा। अब स्पीकर सर, जिस फसल के अन्दर risks नहीं है उस पर किसान प्रीमियम नहीं दे सकता। हमने तो उल्टा इन फसलों को अलग करवाया है पहले सब फसलों को शामिल कर रखा था आप कोई फसल टाल नहीं सकते थे। यह क्रेडिट जाता है हरियाणा सरकार को। मुख्यमंत्री जी बार-बार मिले, कृषि मंत्री जी बार-बार मिले और इन फसलों को अलग करवाया। हमने कहा कि इन तीन फसलों का हम बीमा नहीं करवाना चाहते और हमें खुशी है कि हमारी बात मानी गई। यह हरियाणा सरकार की अचीवमैंट है। स्पीकर सर, इन्होंने विविधीकरण का जिक्र किया कि हम पहले नहीं बोले, आज बोल रहे हैं। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि 19 मई, 2001 को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उस सम्मेलन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द

कहे उसकी एक लाईन मैं यहां कोट करना चाहूँगा ज्यादा करूँगा तो चौधरी भजन लाल जी बैठे नहीं हैं वरना कह देते पढ़ना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन में कहा कि "कृषि में विविधीकरण केवल नारों और सुझावों से नहीं लाया जा सकता" इसके लिए ढ़ांचागत व संस्थागत प्रबन्ध करने होंगे। यानि 2001 में आज से तीन साल पहले हमने यह मुद्दा उठा दिया था। उसके बाद 3.1.2003 आज से एक साल पहले हमने 1920 करोड़ रुपये की स्कीम भारत सरकार को प्रस्तुत की थी और ये कह रहे थे कि गठबन्धन टूटने के बाद हम ऐसी बात कर रहे हैं। बाद में संबंधित अधिकारियों से विचार विमर्श करके 1960 करोड़ किया जो कि 16 जून, 2003 को भेज दी थी। मैं इनको कहना चाहूँगा कि यह बात कोई आज की नहीं है। स्पीकर सर, मुझे बड़ा अफसोस होता है मैंने जवाब तो उसी समय दे दिया था वैसे कोई साथी खेल नीति के बारे में बोला भी नहीं। हमारी खेल नीति से बढ़िया और कोई खेल नीति नहीं है। आज हिन्दुस्तान के अंदर कोई भी रिजनल सैंटर स्पोर्ट्स का नॉर्थ जोन में नहीं था लेकिन अब आपके यहां सोनीपत में नॉर्थ जोन का रिजनल सैंटर बन रहा है यह अचीवमैंट हमारी सरकार की है। हमारे यहां कि लड़कियाँ कॉमन वैल्थ में, एशिया में गोल्ड मैडल लेकर आती हैं और किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि घास पर हॉकी वे खेलती थी। स्पीकर सर, आप तो खिलाड़ी रहे हैं आपको मालूम है कि हॉकी के नैशनल और इंटरनैशनल गेम्ज एस्ट्रोटर्फ पर होते हैं, घास पर नहीं खेला जा सकता। पहला एस्ट्रोटर्फ गुड़गांव में हमारी सरकार बनवा चुकी है और दूसरा एस्ट्रोटर्फ शाहबाद में कम्पलीट होने जा रहा है। ये हमारी सरकार की अचीवमैंटस हैं। स्पीकर सर, सैंट्रल मिनिस्ट्री से यूनिवर्सिटी भी मंजूर करवाई है। हमारे साथी जय प्रकाश बरवाला जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि जींद में यूनिवर्सिटी बनेगी। मैं उनको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की है लेकिन बनानी तो भारत सरकार ने है। इसके लिए उनको सरकार की सराहना करनी चाहिए, वैलकम करना चाहिए। भारत सरकार के साथ हम मैटर को टेकअप कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वे जल्दी ही हमारी बात को मानेंगे और यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनेगी। यह यूनिवर्सिटी अपने आप में पहली यूनिवर्सिटी होगी। स्पीकर सर, जब से हरियाणा बनी है और हमारी सरकार आई है उससे पहले 50 लाख से ऊपर खिलाड़ियों को टोटल ईनाम नहीं दिया गया जबकि हमारी सरकार ने चार साल में 5 करोड़ रुपये नगद ईनाम के खिलाड़ियों को दिए हैं। हमारी खेल एसोसिएशन की तरफ से बाकायदा खेलों के लिए कलैंडर छपता है जैसे सरकारी कलैंडर छपता है। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके कलैंडर में होता है कि कब रूरल गेम्ज होंगे, कब पंचायत के गेम्ज होंगे, कब जिला स्तर के गेम्ज होंगे, कब यूनिवर्सिटीज और इंटर यूनिवर्सिटीज के गेम्ज होंगे, कब स्टेट चैंपियनशिप होगी, कब नैशनल और इंटरनैशनल गेम्ज होंगे। इस कलैंडर के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को पता चल जाता है। खेल नीति में यह भी लिखा जाता है कि फलां मैडल जीतने पर एक करोड़ रुपये मिलेगा, फलां मैडल जीतने पर 50 लाख रुपये मिलेगा, फलां मैडल जीतने पर 25 लाख रुपये, फलां मैडल जीतने पर 10 लाख, फलां मैडल जीतने पर 7 लाख, फलां मैडल जीतने पर 3 लाख, फलां मैडल जीतने पर 1 लाख रुपया खिलाड़ियों को मिलेगा। इस नीति में अब दो-तीन खेलों को और सम्मिलित किया गया है। Women festival और वैटर्न को पहले छोड़ दिया गया था अब इसमें जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त हैंडीकैप्ड खिलाड़ियों की तरफ पहले कोई ध्यान नहीं दिया गया था अब उनको भी इसमें शामिल किया गया है। स्पीकर सर, अब हर जगह स्टेडियम बनाये जा रहे हैं और हर जगह खेल और खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस बात के लिए इनको सरकार की सराहना करनी चाहिए। स्पीकर सर, चौधरी भजन लाल जी चले गये अब किसको बताऊं फूड ग्रेन्ज के बारे में कि हमारे समय में कितनी फूड ग्रेन पैदा हुई है। 1994 से 1996 शुरू तक चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय 1994-95 में 109.72 लाख टन, 1995-96 में 101.78 लाख

[प्रो० सम्पत सिंह]

टन, 1996-97 में 114 लाख टन उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आ गई और 1997-98 में 113 लाख टन, 1998-99 में 121 लाख टन और हमारी सरकार आने के बाद 1999-2000 में 130.65 लाख टन, 2000-01 में 132.29 लाख टन, 2001-02 में जो कि भयंकर सूखा पड़ा था उस समय 123 लाख टन फूड ग्रेन पैदा हुई। हमारे से पहले सबसे ज्यादा फूड ग्रेन चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय में 121 लाख टन पैदा हुई थी। हमने सूखे के समय किसानों को पूरा पानी देकर, पूरी बिजली देकर अच्छी फसल करवाई थी। वर्ष 2003-04 में जो एस्टिमेटिड है वह 137.16 लाख टन है। राव साहब ने यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात कही कि क्या यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है। कौन पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। सबसे ज्यादा अगर साऊथ हरियाणा के हामी थे तो वे चौधरी देवी लाल जी थे। ओथ लेते ही सबसे पहले गए नारनौल। 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, हमेशा कहते थे कि मेरा प्रोग्राम बनाओ मैं वहां जाऊंगा। अगर चौधरी देवी लाल जी को सबसे ज्यादा प्यार था तो वह नारनौल और महेन्द्रगढ़ के एरिया से था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिये।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, हम तो यही कर सकते हैं कि पूरा पानी के बारे में जितना अवेलेबल है, वह सभी को बराबर मिले। स्पीकर साहब, नरवाना ब्रांच के साथ एस.वाई.एल. का चैनल पैरलल बनाने की बात है, वह तभी होगी जब एस.वाई.एल. का पानी आयेगा। इससे पहले जो पानी ले करके हम आ रहे हैं वह पानी बाद में यमुना सिस्टम में एन.बी.के. लिंक के थ्रू डालते हैं और एन.बी.के. लिंक सिस्टम है और दूसरा बुडेड़ा कम्पलैक्स है। वहां से भी एस.वाई.एल. चैनल में पानी जाना है। अगर वो पानी आपका आ जाता है तो रावी ब्यास का सरप्लस वाटर और एस.वाई.एल. का आ जाता है तो यहां बुडेड्रा से आगे एक जगह यह दोनों इकट्ठी हो जायेंगी। इसके बाद एस.वाई.एल. चैनल का पानी चला जायेगा। इधर एन.बी.के. लिंक ब्रांच में पानी चला जायेगा। अब वह पानी है नहीं। वह न होने की वजह से सिस्टम न होने की वजह से एन.बी.के. का जो सिस्टम है उसमें वह नहीं आ रहा। पीछे जो पानी नरवाना ब्रांच में ले करके आ रहे हैं, नरवाना ब्रांच वाला जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से आपकी एन.बी.के. के अन्दर कैपिसिटी 3700 क्यूसिक्स से ज्यादा की नहीं होती। हम 3700 क्यूसिक्स पानी आज भी दे रहे हैं। एक वह वक्त था जब इतना पानी नहीं दिया करते थे। अब चाहे आगे सिस्टम ना भी हो तो भी ड्रेन में डाल करके लोगों को पानी की प्यास ड्राउट ईयर में बुझाई गयी है। इसलिए ये यह नहीं कह सकते कि हम पानी नहीं दे रहे। जितना पानी सिस्टम के अन्दर अवेलेबल है, वह हम दे रहे हैं और इसी तरीके से इन्होंने या किसी और शख्स ने जिक्र कर दिया कि स्कूलों की बिल्डिंगों की देख-रेख के लिए कोई पैसा बजट में नहीं रखा गया। इसके बारे में मैं बताता हूँ कि जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार जुलाई 1991-1996 तक थी यानि जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब कितना खर्च हुआ। उस अवधि में केवल इस काम के लिए 18 करोड़ रुपये खर्च हुए। जब बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो इनके समय में स्कूलों की बिल्डिंगों और कमरों की रिपेयर आदि पर केवल 11 करोड़ रुपये खर्च हुए जबकि आपकी सरकार अब तक इस काम पर 72.30 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दो-दो बार नहीं बल्कि 6-6 व 7-7 टाइम इस काम पर पैसा खर्च किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान और डी.पी.पी. वगैरह अलग हैं। यह पैसा भी आपको तब मिलता है जब हम अपना शेयर देते हैं। कई स्टेट्स ऐसी होती हैं जो अपना शेयर नहीं दे पाती हैं वह पैसा भी हम लेते हैं जैसे पुलिस मोर्डनाईजेशन में हमने लिया जबकि कई स्टेट्स ले नहीं पायी। इस पैसे को लेने के लिए स्टेट सरकार को

कन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। स्पीकर साहब, केवल 25 परसेंट ग्रान्ट है और 25 परसेंट लोन जबकि 50 परसेंट पैसा आपको अपना देना पड़ता है तब जा कर ऐसा पैसा मिलता है। आपके पास धेला देने का न हो, लोन देने की हिम्मत न हो तो 25 परसेंट आप दे लो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट्स ऐसा शेयर नहीं ले पाती वह शेयर भी हमने लिया है। स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है कि कोई बात बच गयी हो जिसका हमने कोई जवाब ना में दिया हो। मैं एक बात और सदन के सामने कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौधरी देवी लाल जी का रास्ता अपनाया हुआ है। चौधरी देवी लाल जी हमेशा यही कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चला करता है। इस बात को किसी सदस्य ने नहीं उठाया। केवल माननीय सदस्य श्री बिसला जी ने यह बात उठायी थी क्योंकि ये भी उनके सही अनुयायी रहे हैं। (विघ्न) बिसला जी ने पूरी सपोर्ट की है और 1977 में भी पूरी सपोर्ट की थी। यहां पर बोलते हुए इन्होंने प्रोफैशनल टैक्स का जिक्र किया था। इस प्रोफैशनल टैक्स के बारे में मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुझे यह बात बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है कि आज ही घोषणा करो और मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से घोषणा करता हूँ कि हम प्रोफैशनल टैक्स वापस लेते हैं। (तालियां) आप इसके लिए तो तालियां बजा दो। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूँ कि सभी साथी पुरानी बातों को छोड़ कर और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो संतुलित बजट मैंने पेश किया है, जो चहुंमुखी विकास का बजट आया है उसको सारे ध्वनिमत से पास करें, धन्यवाद।

15.00 बजे

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी, शायद आप कुछ कहना चाहते हैं, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने प्रोफैशनल टैक्स हटाने के बारे में जो बात रखी है मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री जी ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस टैक्स को हटाया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हमेशा लोकहित की बात को माना है। पहले भी कई बार जब गवर्नमैंट ने ऐसा कोई निर्णय लिया और हमने बताया कि यह निर्णय लोगों के हित में नहीं है तो सरकार ने सहर्ष हमारे सुझाव को माना और ऐसे निर्णय को विदड्रा किया। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सरकार ने प्रोफैशनल टैक्स को वापिस लिया है इसके लिए मैं अपनी तरफ से, तमाम सदस्यों की तरफ से तथा हरियाणा की जनता की तरफ से सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूँ तथा यह कहना चाहता हूँ कि प्रोफैशनल टैक्स से लोगों को काफी कठिनाइयां आती थीं, गरीब लोगों को काफी दिक्कत आती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को गरीबों का मसीहा कहा ही जाता है, तो लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए सरकार ने इस टैक्स को माफ किया है इसके लिए मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूँ। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। (विघ्न) आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, कोई भेदभाव नहीं है, सदन के नेता खड़े हैं इसलिए अभी आप बैठें। (विघ्न)

डॉ० रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ***** ***** *****

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बैठें, (विघ्न) कादियान साहब जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत करवाना चाहूँगा कि यह बात पहले भी कई मर्तबा आ चुकी है और कई बार मैं इसे दोहरा चुका हूँ अब फिर दोहरा रहा हूँ कि स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रणाली में इस सदन के हर सदस्य को सरकार के खिलाफ नुक्ताचीनी करने का पूर्ण अधिकार है। हम इस बात के पक्षधर हैं कि अगर सरकार कहीं कोई गलत काम करती है तो उसको भूल सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन तो लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, सदन के नेता खड़े हैं इसलिए अभी आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : कादियान साहब, आप मुझे बीच में न टोकें और मेरी बात सुनें। आपने अपना आचरण ठीक रखने की बात रखी थी लेकिन फिर भी आप अपना आचरण ठीक नहीं कर रहे हैं। हुड्डा साहब, अब आप ही इन्हें समझाएं (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि प्रजातान्त्रिक प्रणाली में हैल्दी क्रिटिसिज्म होना आवश्यक है और हम उसके पक्षधर हैं। सदन के माननीय सदस्यों को मैंने कई मर्तबा कहा है कि हैल्दी क्रिटिसिज्म करें और कोई रचनात्मक सुझाव दें, सरकार इसको मानने के लिए निरन्तर तैयार रही है और तैयार है। अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस में टैक्स का बिल पास हुआ जिस को लेकर विपक्ष के नेताओं ने बड़ा प्रचार किया और हमारा सहयोगी दल भी उसमें शामिल रहा प्रदर्शन धरने सब कुछ करते रहे। उसके बाद जब लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी और जब बिल पास होने लगा तो आपने इनको एक अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़े खुले मन से इनको अवसर दिया और इस बिल पर बोलने की बजाए विपक्ष के साथियों ने वाक आउट किया। आपने उस वक्त हाउस को ऐडजॉर्न किया कि शायद दोबारा आ कर ये लोग इस बिल पर चर्चा करें लेकिन ये लोग फिर भी नहीं आए। अध्यक्ष महोदय, बिल पास हुआ और बिल पास होने के बाद भी मौजूदा सरकार ने यह कहा कि अगर इस बिल में कोई खामी है, कोई कमी है और उसके बारे में प्रदेश का कोई भी नागरिक कहेगा तो हम इसमें संशोधन के लिए तैयार रहेंगे। हम तो गांधी जी के अनुयायी हैं और अपने ही लिये गये निर्णय को बदलने में हम लेशमात्र संकोच भी नहीं करेंगे। अगर कोई अच्छा सुझाव आएगा तो हम उसमें अमैंडमैंट के लिए भी तैयार हैं। प्रोफैशनल टैक्स का बिल पास होने के बाद हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर ने सारे प्रदेश के सम्मानित लोगों को, हर समुदाय से जुड़े हुए लोगों को, हर किस्म की यूनियनों और संस्थानों से जुड़े हुए जो सम्मानित सदस्य थे म्यूनिसिपल कारपोरेशनों के प्रैजिडैंट्स और म्यूनिसिपल कमिश्नर आदि की एक मर्तबा नहीं बल्कि तीन मर्तबा मीटिंग बुलाकर लोगों से सुझाव मांगे और जब लोगों के सुझाव हमारे पास आए तो हमने अपने ही पास किए हुए बिल में अगले सैशन में संशोधन किया और हाउस टैक्स के पास किए हुए बिल को अमैंड किया। हम इस बात के पक्षधर हैं और यह हमारी जिम्मेदारी भी है। जनता ने हमारे ऊपर अटूट विश्वास प्रकट किया है, हम उसके पक्षधर हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिए कि प्रोफैशनल टैक्स को वापिस लिया जाए तो हमने उसको वापिस लिया है। अगर आप चाहें तो सदन में रचनात्मक सुझाव दें, सरकार का हैल्दी क्रिटिसिज्म करें। यह नहीं की पुराने प्रैसिडैंट पर चलें जो कि ठीक नहीं है। (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान : * * * *

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सदन के साथी ने जो सुझाव दिया है कि बेरी के मेले बदल दें तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस सुझाव पर हम गौर करेंगे।

बजट 2004-05 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now discussion and voting on demands for grants on the Budget for the year 2004-2005 will take place.

As per the past practice and in order to save the time of the House, all the demands for grants on the order paper (1 to 25) will be deemed to have been read and moved together. Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion. The notices of cut motions given by Sarvshri (Capt.) Ajay Singh, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 8; Sarvshri (Capt.) Ajay Singh, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 9; Sarvshri (Capt.) Ajay Singh, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 11 and Sarvshri (Capt.) Ajay Singh, Karan Singh Dalal and Jagjit Singh Sangwan on Demand No. 15 will also be demand to have been read and moved.

That a sum not exceeding **Rs. 9,37,60,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 1—**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,34,49,72,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 2—**General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 6,75,08,19,000 for Revenue expenditure and Rs. 30,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 3—**Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,74,08,06,000 for Revenue expenditure and Rs. 15,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 4—**Revenue.**

That a sum not exceeding **Rs. 48,64,05,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 5—**Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding **Rs. 9,02,37,26,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 6—**Finance.**

That a sum not exceeding **Rs. 7,55,57,99,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 7—**Other Administrative Services.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,14,47,33,000 for Revenue expenditure and Rs. 4,38,30,62,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 8—**Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding **Rs. 18,78,22,15,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 9—**Education.**

That a sum not exceeding **Rs. 7,22,32,21,000 for Revenue expenditure and Rs. 2,28,09,70,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 10—**Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding **Rs. 60,22,55,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 11—**Urban Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 62,79,51,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 12—**Labour & Employment.**

That a sum not exceeding **Rs. 5,45,30,85,000 for Revenue expenditure and Rs. 1,75,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 13—**Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding **Rs. 27,48,29,000 for Revenue expenditure and Rs. 13,65,02,70,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 14—**Food & Supplies.**

That a sum not exceeding **Rs. 15,99,91,00,000 for Revenue expenditure and Rs. 3,03,33,10,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 15—**Irrigation.**

That a sum not exceeding **Rs. 38,72,20,000 for Revenue expenditure and Rs. 54,60,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 16—**Industries.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,66,37,64,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 17—**Agriculture.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,38,97,38,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 18—**Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding **Rs. 10,07,72,27,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 19—**Fisheries.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,08,85,27,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 20—**Forests.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,06,66,85,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 21—**Community Development.**

That a sum not exceeding **Rs. 23,98,43,000 for Revenue expenditure and Rs. 15,08,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 22—**Co-operation.**

That a sum not exceeding **Rs. 5,92,13,79,000 for Revenue expenditure and Rs. 55,66,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 23—**Transport.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,62,07,000 for Revenue expenditure and Rs. 4,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 24—**Tourism.**

That a sum not exceeding **Rs. 2,36,24,37,000 for Revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 25—**Loans & Advances by State Govt.**

Demand No. 8 (Buildings & Roads)

Capt. Ajay Singh,

Shri Karan Singh Dalal

Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 9 (Education)

Capt. Ajay Singh,

Shri Karan Singh Dalal

Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 11 (Urban Development)

Capt. Ajay Singh,
Shri Karan Singh Dalal
Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re. 1/-.

Demand No. 15 (Irrigation)

Capt. Ajay Singh,
Shri Karan Singh Dalal
Shri Jagjit Singh Sangwan

That the demand be reduced by Re. 1/-.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बताएं कि हमारा कितना समय है। हम 5 मिनट बोल सकते हैं या 6 मिनट बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड नम्बर 8 पर अपने विचार रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए हमने मिस-मैनेजमैंट की बात की थी और लोन के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे कि सरकार ने बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा है। इसके अलावा मैंने और भी बातें कही थी लेकिन उन विषयों के बारे में सम्पत सिंह जी ने अपने जवाब में कुछ नहीं कहा है। मैंने यह भी कहा था कि रिवाड़ी में बाय पास नहीं है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं डिमाण्ड पर बोल रहा हूँ।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में क्लीयर करना चाहूँगा कि कल कैप्टन साहब ने ही नहीं बल्कि जितने भी दूसरे सदन के सदस्यों ने अपने सुझाव और विचार रखे हैं हमने उनको नोट कर लिया है और सरकार उन पर गौर करेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मंत्री जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया है, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐजुकेशन पर और इरिगेशन पर बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मंत्री जी ने आपकी बात का जवाब दे दिया है, अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (Noise and interruption)

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * *

श्री अध्यक्ष : इनकी यह बात रिकॉर्ड नहीं की जाए। कर्ण सिंह जी आप बोलें। (विघ्न) कैप्टन साहब, क्या आपकी बात खत्म नहीं हुई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं लैंड एक्वीजिशन के बारे में बात कहना चाहता हूँ। इसमें जो सैक्शन 4 और सैक्शन 6 है, उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो बिल्ट अप हाउस हैं उनमें सैक्शन 4 ऑब्जैक्शन इन्वाइट किए बिना ही सैक्शन 6 भी लगा दी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कम से

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कम जब उन्होंने जो वह चाहते हैं, वह एस.डी.एम. के सामने बता दिया था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं डिमांड नं० 11 पर बोल रहा हूँ। स्पीकर सर, मैं लैंड ऐक्विज़िशन के बारे में कहना चाहता हूँ कि कम से कम बिल्ट अप हाउस को तो छोड़ना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण आज वहां पर लोगों की हालत खराब हो गयी है। कालोनाइजर्स ने लोगों के लिए जो कालोनीज काटी थी उनमें न तो सीवरेज की फैसेलिटीज दी गयी थी और न ही कोई दूसरा कार्य किया गया था। मेरा कहना यह है कि वहां पर जिस समय यह कालोनीज काटी जा रही थी उस समय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के लोग वहां पर क्या कर रहे थे ? उनकी वजह से ही गरीब आदमी पर आज मार पड़ गयी है।

श्री अध्यक्ष : आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं अर्बन डिवल्पमैंट की डिमांड पर बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : अर्बन डिवल्पमैंट की डिमांड तो अलग है और जो बात आप कह रहे हैं वह अलग है दोनों महकमें अलग-अलग हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल कमेटीज भी अर्बन डिवल्पमैंट डिमांड में आती हैं। मैं तहबाजारी के बारे में कह रहा हूँ। रिवाड़ी एक ऐसा शहर है जहां पर तहबाजारी खत्म की जा रही है इसलिए मेरा कहना है कि सरकार इस पर विचार करे। अध्यक्ष महोदय, जो उपजाऊ लैंड है वह ऐक्वायर नहीं करनी चाहिए। ठीक है आप वहां पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और आपने गढ़ी हरसरू के अंदर मानेसर में जमीन ऐक्वायर करने की बात की है। मेरा कहना है कि जो उपजाऊ लैंड ऐक्वायर की जा रही है उसके रेट बहुत कम दे रहे हैं। वह लैंड ऐक्वायर करें जहां पर पानी मीठा हो लेकिन अगर उपजाऊ लैंड ऐक्वायर की जाएगी तो यह ठीक नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, यह तो आप बजट पर भी बोल चुके हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं० 15 पर बोल रहा हूँ। हमारे यहां पर कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर वाटर लेवल नीचे चला गया है। दोहान पच्चीसी एरिया में कई मीटर तक पानी नहीं मिल रहा है। इसलिए एक तो मैं वाटर रि-चार्जिंग के बारे में जानना चाहूँगा कि सरकार का इस बारे में क्या विचार है ? दूसरे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि टेल एंड की जहां-जहां पर डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो डिफैक्टिव हो गयी हैं, उनको हम ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, लाधूवास और कई डिस्ट्रीब्यूटरीज ऐसी हैं जिनकी टेल पर पानी नहीं पहुँच रहा है तो क्या इनको भी ठीक करवाया जाएगा ? इसके अलावा जे.एल.एन. कैनाल की कैपेसिटी 25 परसेंट इन्होंने बढ़ाने की बात कही है मैं जानना चाहूँगा कि यह कैपेसिटी आपने किस तरह बढ़ा दी ? क्या आपने कोई इसकी रिपेयर की है या आपने इसकी गाद निकाल दी है ? अगर जे.एल.एन. कैनाल की कभी सफाई हुई हो या अगर कभी गाद निकाली हो तो इसके बारे में वित्त मंत्री जी बता दें कि आपने कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है ? इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात है जो पानी के बंटवारे की बात है हम उससे बिल्कुल भी सैटिसफाईड नहीं है। जो पानी का बंटवारा है उसका सही तरीके से बंटवारा होना चाहिए। केवल दो जिले ही पूरे प्रदेश का पानी ले रहे हैं जो कि ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बस बस, आपकी बात पूरी हो गयी है अब आप बैठिए। आप भाषण न दें। अब आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सैंटर की वजह से प्रदेश को 1100 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह आप कौन सी डिमांड पर बोल रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं डिमांड नं० 15 पर बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह तो इसमें नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने यह पांच से घटाकर 4.33 परसेंट कर दिया। क्या यह इसलिए कम कर दिया कि आपको 1100 करोड़ रुपये कम मिले। इस बारे में आप चार साल क्यों नहीं बोले, आप केन्द्र के अंदर सरकार को क्यों सपोर्ट करते रहे, आपके एम.पीज. क्यों सपोर्ट करते रहे उस वक्त क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी एस.वाई.एल. के ऊपर बोले ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिए आपका समय समाप्त हो गया है। दलाल साहब, अब आप बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड नं० 8 पर सबसे पहले विचार रखना चाह रहा हूँ। मैं कट मोशन के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) वर्क्स डिपार्टमेंट है उसको यह चाहिए कि अगर कोई भी सड़क या कोई भी भवन बनाता है तो उसके बाहर एक बोर्ड लगाना चाहिए और उस बोर्ड पर उस ठेकेदार का नाम लिखना चाहिए जो उस सड़क या भवन को बनाता है। इस बोर्ड पर उसका खर्चा लिखना चाहिए, उसकी स्पैसिफिकेशन के बारे में जिक्र करना चाहिए कि इसकी स्पैसिफिकेशंज क्या है ? इसके अलावा उस बोर्ड पर सड़क या भवन की उम्र भी लिखनी चाहिए कि कितने साल के लिए यह बनाया गया है। अगर उससे पहले वह सड़क टूटती है या उस भवन में क्रेक आती हैं या वह बिल्डिंग नहीं बनती है तो उस वक्त के ऐक्सियन, जे.ई. और ठेकेदार की जिम्मेवारी होनी चाहिए क्योंकि अगर यह जिम्मेवारी नहीं होती है तो सरकार जो सड़कें बनाती है वह अगले ही दिन टूटनी शुरू हो जाती है। जो ये टैंडर इसमें देते हैं उसका प्रोविजन इनको ये करना चाहिए कि अब तो सारा सिस्टम कम्प्यूटाइज करने का प्रयास किया गया है तो कम्प्यूटर के माध्यम से किसी भी आदमी को टैंडर देने की इजाजत दें लेकिन इन्होंने टैंडर प्रणाली का एकाधिकार किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब टैंडर वैबसाइट से और सारा ठीक ढंग से लिया जाता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी कहा था आर्कीटैक्चर डिपार्टमैंट जो कि पी.डब्ल्यू.डी. का पार्ट है, उसको रिवाइव करना चाहिए। उसमें सरकार को चाहिए कि मॉडर्न टैक्नोलॉजी को ऐडॉप्ट करके जैसे अंग्रेजों के समय में जो भी बिल्डिंग या पुल बनते थे उनमें कभी कहीं क्रेक नहीं आते थे लेकिन आज जो नयी बिल्डिंग बनती हैं चाहे वे गांव के स्कूल हैं या शहरों में भवन हैं उनमें बनने के दस दिन बाद ही क्रेक आनी शुरू हो जाती हैं और उनमें तरह-तरह की खामियां नजर आने लगती हैं। इनको अपने आर्कीटैक्चर डिपार्टमैंट को रिवाइव करना चाहिए। अब मैं डिमांड नंबर 9 पर बोलना चाहता हूँ। जो ऐजूकेशन की बात है आज गांवों में जो लोग बसे हुए हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत है और लोगों को सरकारी स्कूलों में कोई भरोसा नहीं है इतनी

भारी राशि सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च करती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कम से कम बड़े गांवों में या आठ दस गांवों का समूह बनाकर मॉडल स्कूल बनाएं और उनमें जो टीचर्स लगाए जाएं वह बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने चाहिएं। उनकी क्वालिफिकेशन शहर में पढ़ाने वाले अध्यापकों से भी अच्छी होनी चाहिए और उन स्कूलों में लड़कियों के रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए और जो लड़कियां दूर गांव से आती हैं वे वहां हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और उनके खेलने की व्यवस्था वहां हो।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। हरियाणा एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है इसमें अलग-अलग मापदण्ड नहीं होते हैं। शहर और गांव के लिए क्वालिफिकेशन समान होती है। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि ऐसे मॉडल स्कूल बनाएं जिनसे मां-बाप का भरोसा सरकार में बढ़े। आज मां-बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते और जिनके पास साधन हैं वे अपने बच्चों को दूर-दूर शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं जिससे सरकार के साधनों की बड़ी भारी ब्यर्थ की वेस्टेज हो रही है इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। पिछले दिनों सरकार ने प्राइवेट स्कूल डी-रिकग्नाइज करने का मूव चलाया है अगर स्कूलों को डी-रिकग्नाइज करते हैं वे आपके द्वारा बनाई गई मान्यता को पूरा नहीं करते हैं जो स्कूल डी-रिकग्नाइज होगा उसके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे। इस बारे में सरकार को इंतजाम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब मैं डिमांड नंबर-11 जो अर्बन डवेलपमैंट के बारे में है बात करना चाहता हूँ। इसमें एक कानून हमारे हरियाणा में लागू हुआ और हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट है कि अगर कोई भी जमीन अर्बन डवलपमैंट डिपार्टमैंट एक्वायर करता है तो सरकार को कोई हक नहीं है कि उस जमीन को सरकार वापस रिलीज करे। हाईकोर्ट की जजमैंट यह है कि उसकी ऑक्शन होगी। जबकि यह सरकार हाईकोर्ट की जजमैंट को इग्नोर करके उन जमीनों को अपने * को वापस करती है।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गलत परम्पराएं नहीं डलनी चाहिएं।

उपाध्यक्ष (श्री गोपी चन्द गहलोत) : माननीय कर्ण सिंह दलाल चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में साढ़े तीन साल तक मंत्री रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे झाड़सा गांव की जोहड़ की जमीन जोकि सलोगड़ा के पास है उस जमीन को एक्वायर किया गया था और उस जमीन को यूनिटैक्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी को दिया गया था जिस जमीन पर आज बिल्डिंग बनी हुई हैं ये उस टाईम को याद करें। इस तरह का एक उदाहरण मेरे पास है। यहां पर आज छः कालोनीज हैं जिसमें चौधरी देवीलाल नगर, विकास नगर, रवि नगर आदि बनी हुई हैं। और चौधरी भजन लाल जी जो कि 12 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उनके समय में श्मशान घाटों की जमीन तक नहीं छोड़ी थी। सात कालोनीज जिनमें 80 प्रतिशत से ज्यादा बनी हुई हैं आज बेचारे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे इस एरिया को रिलीज कर दें क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद कर सकते हैं पहले हम चौधरी देवीलाल जी से उम्मीद करते थे। यह सब सरकार पर निर्भर करता है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, जो ये सैक्टर बनाये हैं। स्पीकर सर, गुड़गांव आज हरियाणा का दिल है जहां हर आदमी की नजर आज गुड़गांव पर है और आज वक्त आ गया है कि गुड़गांव में हाउसिंग और कमर्शियल चीजें नहीं करनी चाहिए। आज वहां पर इतनी भीड़ हो चुकी है क्योंकि वह डिप्टी स्पीकर साहब का इलाका है और मेरी ससुराल है इसके अलावा मैं वहां पढ़ा भी हूँ। मेरा आपके माध्यम से सरकार को एक सुझाव है क्योंकि आज अगर गुड़गांव के अन्दर किसी की मौत हो जाती है तो शमशान घाट तक ले जाने में बड़ी भारी दिक्कत आती है। इसलिए सैक्टर में ही शमशान घाट की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

श्री गोपी चन्द गहलोत : चौधरी भजनलाल जी बैठे नहीं हैं। मैंने पहले भी इस बारे में कई बार कहा है कि चौधरी भजनलाल जी की सरकार के समय गांवों के शमशान घाट की जमीन भी एक्वायर की गई थी। मैं आज आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और चौधरी धीरपाल जी का कि जिन्होंने मेरे गांव के जो दो शमशान घाट थे, जिनकी जमीन पहले एक्वायर की गई थी आज सरकार ने रिलीज ही नहीं की बल्कि डवलपमैंट वर्क करवाकर शहर की तरह वहां पर शमशान घाट बनाया है। इसी तरह से मोलाहेड़ा और दूसरे गांवों की जमीन को भी रिलीज किया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, अब मैं डिमांड नम्बर 15 पर बोलना चाहता हूँ। इस बारे में श्री सम्पत सिंह जी ने एस.वाई.एल. के बारे में चर्चा की है। (विघ्न) इस बारे में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ। फरीदाबाद और मेवात का इलाका जिसमें आगरा नहर से पानी आता है। आगरा मेन नहर जो बरसों से है जब से यह नहर बनी है यह अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक पहली दफा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नहर की खुदाई का काम करवाया है जो कि बड़े सुनियोजित ढंग से नीचे तक खुदवाकर नहर की खुदाई करवाई है। स्पीकर सर, हमारी समस्या यह है कि नहर की खुदाई होने के पश्चात जो इसके रजबाहे थे वे ऊंचे हो गये हैं इसलिए इन रजबाहों में पानी कम आता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन रजबाहों की खुदाई भी सरकार द्वारा करवाई जाये ताकि उनमें पूरा पानी आ सके। इससे पहले हमारे समय की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर आगरा नहर के पानी को ज्यादा करवाया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उस पानी को घटा दिया है। इसलिए फरीदाबाद के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता है इसका कारण यह है कि इस सरकार की यू.पी. की सरकार से मिलीभगत है इसलिए पानी घटा है इसलिए उस पानी को बढ़वाया जाये। नहर की खुदाई हो चुकी है इसलिए रजबाहों की खुदाई भी होनी चाहिए जिसके कारण किसानों के खेतों में अंतिम छोर तक पानी पहुँच सके।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, जब आप कृषि मंत्री थे उस समय इसकी खुदाई नहीं हुई क्या ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरी नहरों की तो हुई थी लेकिन मेन आगरा कैनाल की नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आपने क्यों नहीं करवाई।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल जी जब विपक्ष में थे और कांग्रेस की यहां सरकार थी तब ये इस बात का बहुत जिक्र किया करते थे कि कभी इनकी सरकार आई तो ये आगरा कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। ताकत के बलबूते पर ले लेंगे। चौधरी बंसीलाल जी की सरकार बनी और साढ़े तीन साल तक रही। उसमें ये पावर मंत्री भी रहे लेकिन इन्होंने एक सैकिण्ड भी आगरा कैनाल का जिक्र नहीं किया। अब ये या तो पुरानी बात को भूल गये या इनकी पावर खत्म हो गई होगी। अध्यक्ष

महोदय, कर्ण सिंह जी जब विपक्ष में बैठते हैं तब जनहित की बातों की तरफ ध्यान आता है। बदकिस्मती से जब ये सत्ता पक्ष में आते हैं तब इनको जनहित की बातें दिखाई नहीं देती। जब ये कृषि मंत्री थे तब ये कहते थे कि सारी नील गाय पकड़ लेंगे। उस समय दो नील गाय पकड़ी गई थीं और एक नील गाय पर 1.50 लाख रुपये के करीब खर्चा आया था। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, ये पुरानी बात भूल गये हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डिमांड नम्बर 8 के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ कि पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर.) महकमे ने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज शहरों और गांवों में बना रखी हैं। उन बिल्डिंग्ज की टूट फूट ठीक नहीं होती और न ही उनकी सफाई हो पाती है। किसी भी बिल्डिंग में जाकर देख लो सभी के शीशे टूटे हुए हैं उनको ठीक करने के लिए हर साल बजट बनता है लेकिन वे ठीक नहीं होती। उन बिल्डिंग्ज की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई गांव ऐसे हैं जहां एक-एक या दो-दो बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं। वे जिस प्रयोजन के लिए बनाई गई थीं वे प्रयोजन नहीं चल रहे। बहुत से विभागों के लिए बिल्डिंग बनी हुई हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बिल्डिंग बना दी गई, मिनी बैंकों के लिए बिल्डिंग बना दी गई। कई जगहों पर रिहायशी मकान भी बने हुए हैं। लेकिन उनके रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके रखरखाव की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी गांव में भवन किसी विभाग के लिए बन गया और वह विभाग वहां कार्य नहीं कर रहा तो वह बिल्डिंग किसी दूसरे विभाग को ट्रांस्फर कर दी जाये न कि दूसरे विभाग के लिए अलग से बिल्डिंग बनाई जाये। बहुत से गांवों में इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि विभागों के जो स्टोर हैं वे कागजों में तो पूरी तरह से भरे हुए हैं। उनमें साल में, दो साल में या तीन साल में अफसर बदलने पर हर बार दूसरा अफसर आने पर कागजों में रिकॉर्ड पूरा दिखा दिया जाता है लेकिन असल में पूरा सामान नहीं होता। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि समय-समय पर मौके पर जाकर सामान की चैकिंग होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 9 के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल हैं इनके अंदर बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ज्यादा बच्चे पढ़ते प्राइवेट स्कूलों में हैं और उनके नाम सरकारी स्कूलों में लिखे हुए हैं। ज्यादातर सरकारी स्कूलों की यही हालत है। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि चैकिंग करके पता लगाया जाये कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके नाम सरकारी स्कूल में लिखे हुए हैं और वे पढ़ते प्राइवेट स्कूलों में हैं या अध्यापकों के घर पर पढ़ते हैं। इस बारे में भी कमेटी बनाकर चैकिंग होनी चाहिए। जैसा कि वित्तमंत्री जी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान जिसे पहले प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता था इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन लक्ष्य कम अचीव होता है। अध्यक्ष महोदय, दादरी तहसील में झोजू गांव है वहां पर गांव वालों ने और इलाके के लोगों ने मिलकर बहुत ज्यादा पैसे से लड़कियों का कालेज बनाया है। मेरी मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि लड़कियों के उस कालेज को तुरन्त मान्यता दी जाये।

श्री रणबीर सिंह मन्दोला : ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर सर ! मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि जिस झोजू गर्ल्ज कालेज की बात ये कर रहे हैं उसके बारे में आदरणीय सांसद भाई अजय चौटाला जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : यदि वे घोषणा कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं सांसद महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हाँ कर दी लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि सांसद सरकार नहीं है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा था कि वह इसे मान्यता दे और सरकार घोषणा करे कि इस आने वाले सैशन से वहां पर पढ़ाई शुरू हो जायेगी। (विघ्न) हमारी घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। यहां पर सी.एम. साहब

[श्री जगजीत सिंह सांगवान]
बैठे हैं, एजूकेशन मिनिस्टर साहब बैठे हैं। (विघ्न) मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, अब आप बैठिये।

श्री जगजीत सिंह सांगवान : स्पीकर साहब, अभी तो मैंने दो डिमांड्ज पर और बोलना है। स्पीकर साहब, मैं उस बात के लिए ना नहीं करता, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अगर सरकार की तरफ से मान्यता दे दी जायेगी तो यह अच्छी बात होगी। हम इस बात के लिए सरकार का स्वागत करेंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे।

स्पीकर साहब, अब मैं डिमांड नम्बर 11 पर बोलना चाहता हूँ। मैं नगर विकास के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी पीछे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि जिन कालोनीज के अन्दर नक्शे पास नहीं होंगे उनके अन्दर कोई सुविधा नहीं देंगे लेकिन उन कालोनीज में जिस किसी कालोनी में 400-500 घर हैं और उनमें से 300 के नक्शे पास हो गए हैं और 100 घरों के नक्शे पास नहीं हुए हैं तो जिन लोगों के नक्शे पास हुए हैं उनको भी वह सुविधा नहीं मिल पाती जबकि उनके नक्शे आदि पास कर दिए गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जिन लोगों ने नक्शे पास नहीं करवाए हैं। जिन लोगों ने टैक्स दिया है, नलके लगवा लिए हैं, बिजली की तार सरकार ने उनको दे दी है, वे लोग बिजली के बिल दे रहे हैं और अब आगे बकाया लोगों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं यानि जो 100-150 घर नए बन गए हैं उनकी वजह से वे बेचारे 300-400 घर बेचारे ख्वामख्वाह खामियाजा भुगत रहे हैं। इसमें मेरा सुझाव है कि जिन्होंने नक्शे पास करवाए हैं उनको तो सारी सुविधाएं मिलें और दूसरा यह है कि एक सड़क को पहले ईंटों का बनाया जाता है और फिर कंकरीट का बनाया जाता है। लेकिन उसके नीचे मल निकासी का, सीवरेज का या पानी का कोई काम नहीं देखता। कहने का मतलब यह है कि वहां पर बिना प्लानिंग के सारा काम होता है जिस कारण बाद में वे सारी की सारी सड़कें टूट जाती हैं। फिर बाद में उसकी रिपेयर आदि का बार-बार बजट बनता है और उस पर बार-बार पैसा लगता है। वह टूट जाती है, वह खराब हो जाती है तो इस किस्म का वहां पर सबसे पहले सीवरेज का काम होना चाहिए। बिजली वालों को कहना चाहिए कि वह अपनी तारें डाल लें इसी प्रकार से टेलीफोन वालों को कहो कि वे भी अपनी तार पहले ही खींच लें ताकि वे सड़कें बार-बार न टूटें। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस किस्म का एक ज्वॉयंट प्रयास सभी महकमों को मिल कर करना चाहिए ताकि जो सड़कें बनें उस पर जो कार्यवाही करनी है, सुविधा देनी है वह पूरी कर लें ताकि वह बार-बार न टूटे।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 15 जो इरीगेशन से संबंधित है इसमें भी मोटे तौर पर तो स्टोर वाली बात आती है जो मैंने चौ. एण्ड आर. वाली डिमांड में कही है। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सभी विभागों में सरकारी टेलीफोनों का बड़ा मिसयूज होता है। किसी भी विभाग में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक टेलीफोन करेंगे तो वह बिजी मिलेगा। कर्मचारी अपने घर से लिस्ट बना कर के ले जाते हैं और सभी दफ्तर में जाकर टेलीफोन करने में जुट जाते हैं। कोई अपनी साली को, कोई मामा को, कोई फूफा-बुआ को फोन करने लग जाते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि सरकार का पैसा बच सके। यह रोक हरेक लैवल पर होनी चाहिए। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में इमलोटा का माईनर आर-1 है। इस पर मैंने पहले भी एक दो बार हाउस में आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव दिया था कि इसके अन्दर डबल मोटर लगनी चाहिए। इस वक्त वहां पर एक मोटर लगी है जिसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी मोटर न लगने के कारण पहली मोटर का भी पैसा बेकार हो गया। अगर यह दूसरी मोटर लगेगी तभी जाकर वहां पर सिंचाई हो सकेगी, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने भी एक नोटिस आपकी सेवा में दिया था।

श्री अध्यक्ष : आपका शॉर्ट नोटिस जो था वह डिसअलाऊ कर दिया गया है।

राव इन्द्रजीत सिंह : स्पीकर साहब, जिस दिन इन्होंने दिया था उसी दिन मैंने भी अपना नोटिस दिया था। मेरे अकेले का नोटिस डिसअलाऊ क्यों कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : राव साहब, अब आप बैठिये।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now voting on Demands on the Budget for the year 2004-05 will take place.

First, I will put cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demands to the vote of the House.

Demand Nos. 1 to 7

That a sum not exceeding **Rs. 9,37,60,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 1—**Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,34,49,72,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 2—**General Administration.**

That a sum not exceeding **Rs. 6,75,08,19,000 for revenue expenditure and Rs. 30,00,00,000 for capital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 3—**Home.**

That a sum not exceeding **Rs. 1,74,08,06,000 for revenue expenditure and Rs. 15,00,00,000 forcapital expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 4—**Revenue.**

That s sum not exceeding **Rs. 48,64,05,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 5—**Excise & Taxation.**

That s sum not exceeding **Rs. 9,02,37,20,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 6—**Finance.**

That s sum not exceeding **Rs. 7,55,57,99,000 for revenue expenditure** be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-2005 in respect of charges under Demand No. 7—**Other Administrative Services.**

The motion was carried.

Demand No. 8

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No. 1 on Demand No. 8 given by Capt. Ajay Singh Yadav, Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh Sangwan to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is-

That a sum not exceeding Rs. 2,14,47,33,000/- for revenue expenditure and Rs. 4,38,30,62,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 8— **Buildings & Roads.**

The motion was carried.

Demand No. 9

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No. 2 on Demand No. 9 given by Capt. Ajay Singh Yadav, Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh Sangwan to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 18,78,22,15,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 9—**Education.**

The motion was carried.

Demand No. 10

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 7,22,32,21,000/- for revenue expenditure and Rs. 2,28,09,70,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 10— **Medical & Public Health.**

The motion was carried.

Demand No. 11

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No. 3 on Demand No. 11 given by Capt. Ajay Singh Yadav, Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh Sangwan to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 60,22,55,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 11—**Urban Development.**

The motion was carried.

Demand Nos. 12 to 14

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 62,79,51,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 12—**Labour and Employment.**

That a sum not exceeding Rs. 5,45,30,85,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,75,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 13—**Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs. 27,48,29,000/- for revenue expenditure and Rs. 13,65,02,70,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 14—**Food and Supplies.**

The motion was carried.

Demand No. 15

Mr. Speaker : Now, I put cut motion No.4 on Demand No. 15 given by Capt. Ajay Singh Yadav, Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh Sangwan to the vote of the House.

Question is—

That the demand be reduced by Re. 1/-

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 15,99,91,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,03,33,10,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 15—**Irrigation.**

The motion was carried.

Demand Nos. 16 to 25

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 38,72,20,000/- for revenue expenditure and Rs. 54,60,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 16—**Industries.**

That a sum not exceeding Rs. 2,66,37,64,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 17—**Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs. 1,38,97,38,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 18—**Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs. 10,07,72,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 19—**Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs. 1,08,85,27,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 20—**Forests.**

That a sum not exceeding Rs. 2,06,66,85,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 21—**Community Development.**

That a sum not exceeding Rs. 23,98,43,000/- for revenue expenditure and Rs. 15,08,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 22—**Co-operation.**

That a sum not exceeding Rs. 5,92,13,79,000/- for revenue expenditure

and Rs. 55,66,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 23—**Transport.**

That a sum not exceeding Rs. 1,62,07,000/- for revenue expenditure and Rs. 4,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 24—**Tourism.**

That a sum not exceeding Rs. 2,36,24,37,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2004-05 in respect of charges under Demand No. 25—**Loans & Advances by State Government.**

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 17th February, 2004.

15.38 hrs. (The Sabha then * adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 17th February, 2004)

38065—H.V.S.—H.G.P., Chd.